ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

# योजना

दिसंबर : 2004

मूल्य : 7 रुपये

## चुनौतियां और संकल्प

## तेल-मूल्य और भारतीय अर्थतंत्र

## ... और अब होगी देश में कृष्ण क्रांति

## भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्यों की मध्यावधि समीक्षा

## मानवाधिकार संस्थाएं एवं संरक्षण की कार्य प्रणाली

## पर्यावरण मित्र बांस की आर्थिक संभावनाएं

## बीमारियों की रामबाण दवा - प्राणायाम

## अतंरिक्ष से अध्यापन

## तेल कीमतें

# गणतंत्र दिवस, 2005

'योजना' पत्रिका के गणतंत्र दिवस, 2005 का विशेषांक मुख्य रूप से 'योजना आयोग की भूमिका' विषय को समर्पित होगा।

स्वतंत्रता दिवस के बाद से आर्थिक विकास और प्रगति हमारे मुख्य स्तंभ हैं। लेकिन वैश्वीकरण, उदारीकरण और विपणन शक्तियों की बढ़ती भूमिका के कारण योजना आयोग की भूमिका चर्चा का विषय बन गई है। आगामी विशेषांक में योजना–प्रक्रिया के विभिन्न मुद्दे शामिल किए जाएंगे जिनमें ग्रामीण विकास, महिला संवेदनशीलता और पर्यावरण जैसे विषय शामिल रहेंगे। इसमें योजना–प्रक्रिया का विकास, दसवीं पंचवर्षीय योजना और मध्यावधि समीक्षा पर खुले विचार सम्मिलित किए जाएंगे।

विशेषांक में उपर्युक्त तमाम मुद्दों पर अपने–अपने विषयों के विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों के बेबाक विचार रहेंगे।

इस विशेषांक को पाने के इच्छुक पाठक अपने स्थानीय एजेंटों के पास अपनी प्रति की अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं अथवा विज्ञापन और **प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड–IV, तल–VII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 (टेलिफोन संख्या : 26100207)** से संपर्क कर सकते हैं।

इस विशेषांक का मूल्य 15 रुपये है।

# योजना

वर्ष : 48 अंक 9 दिसंबर, 2004 अग्रहायण–पौष, शक–संवत् 1926


## इस अंक में


- चुनौतियां और संकल्प — पी. चिदंबरम — 5
- तेल–मूल्य और भारतीय अर्थतंत्र — वेद प्रकाश अरोड़ा — 12
- .....और अब होगी देश में 'कृष्ण क्रांति' — कुंवर सुनील सत्यम — 19
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004–05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्यों की मध्यावधि समीक्षा — प्यारालाल राघवन — 23
- मानवाधिकार संस्थाएं एवं संरक्षण की कार्य प्रणाली — अरुण कुमार दीक्षित — 26
- पर्यावरण मित्र बांस की आर्थिक संभावनाएं — देवेंद्र सिंह — 32
- स्वास्थ्य चर्चा – सारी बीमारियों की रामबाण दवा – प्राणायाम — राजेन्द्र राय — 39
- विज्ञान – अंतरिक्ष से अध्यापन — शैलेंद्र मोहन कुमार — 43
- जहां चाह, वहां राह – विकास, स्वच्छ वातावरण और भलाई के प्रतीक : संत बलबीर सिंह सीचेवाल — बलबीर माधोपुरी — 45
- मंथन – सुख और दुख — आभा श्रीवास्तव — 49
- नए प्रकाशन — – — 51
- ज्ञान–सागर — रीना — आवरण तीन



प्रधान संपादक – अनुराग मिश्रा

संपादक – राजेन्द्र राय

सहायक संपादक – योगेन्द्र दत्त शर्मा

उप संपादक – रेमी कुमारी



संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666 / 2508, 2566
ई–मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in



संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

आवरण – ऋत्विका मैत्रा

रेखाचित्र – संजीव शाश्वती



योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–
विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; द्विवार्षिक : 135 रु.; त्रैवार्षिक : 190 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.



'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

# संपादकीय

तेल मूल्यों में वृद्धि एक ऐसी विकट समस्या है जिसका सामना हमारे देश को इस समय गंभीरता से करना पड़ रहा है। हालांकि विश्व में तेल की प्रचुरता है, फिर भी कुछ देश और वहां की सरकारें या फिर कुछ तेल कंपनियां अपने निहित स्वार्थों के लिए तेल–मूल्यों को घटाने–बढ़ाने का खेल खेलती रहती हैं। भारत अभी तक तेल–मूल्यों में वृद्धि का सामना सफलता पूर्वक करता रहा है लेकिन लगता यही है कि यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। हाल ही में सरकार को तेल–मूल्यों में वृद्धि का निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा जिससे आम जनता के बीच कुछ बेचैनी अनुभव की गई। स्वयं सरकार ने भी इसे एक बड़ी चुनौती माना है। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न आर्थिक संपादकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने कहा कि "सबसे बड़ी चुनौती विश्वव्यापी कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से उत्पन्न हुआ, पेट्रोलियम क्षेत्र में स्थिरता और संरचनात्मक सुधार के लिए खतरा बना रहना है।"

एक तथ्य यह भी है कि विश्व में कच्चे तेल के कुल भंडार इतने सीमित हैं कि उनसे आगामी 40 वर्षों तक ही तेल की मांग पूरी की जा सकती है। ऐसे में हमें वैकल्पिक संसाधनों को अपनाना पड़ेगा। इस दृष्टि से ऐथेनोल की उपयोगिता को रेखांकित किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि ऐथेनोल बनाने वाली चीजों की खेती की जाए और तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए। इस प्रयास को 'कृष्ण क्रांति' का नाम दिया गया है। कृष्ण क्रांति निश्चित ही भारत की 'टिकाऊ विकास' के प्रति प्रतिबद्धता को दृढ़ता प्रदान करेगी।

# आपकी राय
(संदर्भित अंक–सितंबर, 2004)

## भगीरथ प्रयास आवश्यक

'योजना' का सितंबर अंक पढ़ा। भारत में शिक्षा और उसके प्रसार के समक्ष खड़ी चुनौतियों पर सारगर्भित लेख सराहनीय थे। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का ह्रास और उपभोक्तावाद का हावी होना निश्चित रूप से चिंतनीय है।

वर्ष 2004–2005 के आम बजट में शिक्षा पर दो प्रतिशत उपकर लगाने तथा उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण शर्तों में शिथिलता करने के लिए वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम को साधुवाद। दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में कम साक्षरता दर राष्ट्र के सामने गंभीर चुनौती के रूप में आई है। विशेषकर बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है।

देश में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है, पर एक बात बार–बार मस्तिष्क में कौंधती है कि कहीं विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण के बीच भौगोलिक के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक विभाजन रेखा न बन जाए।

**संगीत कुमार**
**भोपाल**

सर्वश्रेष्ठ पत्र

## नए तथ्य आवश्यक

**शिक्षा पर आधारित विशेष अंक पढ़ा। अंक का प्रत्येक आलेख ज्ञान से लबरेज था। कौशलेंद्र प्रपन्न द्वारा लिखित सामयिक लेख 'इतिहास, विवाद और बदलाव' पढ़ा। इस आलेख के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास की कड़ी में प्रतिदिन एक नई कड़ी नहीं जुड़ती है क्या? अगर प्रतिदिन एक नया इतिहास बनता है तो उन छात्रों को नया इतिहास पढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में जहां तक मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार पुरानी सरकार के द्वारा रखे गए पाठ्यक्रम को बदलकर छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर रही है। पाठ्यक्रम में नवीनता लाने के लिए नए तथ्यों का संकलन अपरिहार्य है। अतः लेखक को एक सरकार के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए अपितु अपने मौलिक विचारों को ही रखना चाहिए। इतिहास बदलता नहीं है लेकिन उसमें प्रत्येक क्षणोपरांत एक नवीनता आती है। अतः हर नवीन विषय को छात्रों के सामने रखना कोई बुरी बात नहीं है।**

**प्रदीप कुमार झा, नई दिल्ली**

## प्रेरक लेख

अंक में 'सफलता की परिभाषा' शीर्षक लेख पढ़ा। यह लेख उन मध्यमवर्गीय छात्र–छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा जो गरीबी के कारण अपने आदर्शों को छोड़ रहे हैं। मैं भी एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी मां का तीसरा बेटा हूं।

यह लेख पढ़कर मैं भावविभोर हो गया। मैंने अपने कई साथियों को यह लेख पढ़ाया, जो 'योजना' नहीं लेते हैं। उन सभी ने इस लेख की प्रशंसा की। कष्ट चाहे कितने भी हों, अपने उसूलों और आदर्शों पर चलकर ही लोग महान बन जाते हैं।

**अमित कुमार पोद्दार,**
**पूर्णियां (बिहार)**

## शिक्षा का उद्देश्य

सितंबर अंक पढ़ा। संपादकीय एवं मंथन जैसे कालम के लेख सशक्त माध्यम की अभिव्यक्ति करते हैं। 'ग्लोबल वार्मिंग की नई चुनौतियां' जैसे लेख संग्रहणीय हैं। मधु शुक्ला का लेख 'भारत में शिक्षा का विस्तार' आज की वस्तुस्थिति को प्रकट करता है।

दार्शनिक प्लेटो का शिक्षा के संबंध में विचार है कि 'शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौंदर्य और जितनी संपूर्णता का विकास हो सकता है, उसे संपन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।' शिक्षा में केवल बुद्धि का प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और आत्मा का अनुशासन भी सम्मिलित होना चाहिए। संसार रूपी समुद्र में जीवन के सुचारु संचालन तथा मंगलमय जीवन के लिए शिक्षा पतवार है। आज परंपरागत शिक्षा की बजाय व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षा के व्यावसायीकरण से तात्पर्य है कि सामान्य शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक जीवन के लिए उपयोगी शिल्पों एवं व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त करना है। इस शिक्षा का लक्ष्य कुशल शिल्पी तैयार करना नहीं, वरन विद्यार्थी में उद्योग–धंधों के प्रति प्रेम और उनकी ओर झुकाव उत्पन्न करके शारीरिक श्रम के महत्व की अनुभूति कराना है। यह शिक्षा जनतांत्रिक भावना विकसित करने के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास करेगी।

**अजय कुमार गुप्ता,**
**जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)**

## उच्चस्तरीय लेख

सितंबर अंक का प्रथम लेख इस अंक को अति विशिष्ट बना देता है। 'सफलता की परिभाषा' शीर्षांकित सुब्रोतो बागची का व्याख्यान अत्यंत उच्च कोटि के विचारों का प्रगटीकरण है। सफलता के महान सबक को इतने सरल, प्रवाहमय, रोचक और बोधगम्य रूप में देकर 'योजना' के संपादक मंडल ने पाठकों के प्रति अपने गंभीर तथा घनिष्ठ लगाव का प्रदर्शन किया है। पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी इतने उच्चस्तरीय लेख प्रकाशित होते रहेंगे।

इतने विद्वत्तापूर्ण विचारों के धनी सुब्रोतो बागची को हृदय से धन्यवाद।

**नीरज अग्रवाल**
**नार्थ कैम्पस डी.यू., दिल्ली**

हमारे टॉपर्स

**Amritendu Sekhar**
*BPSC 1st Topper*

"सर के G.S. पढ़ाने-समझाने एवं अभिभावक की तरह मार्गदर्शन का तरीका अद्भुत है"

**Ajay Kumar**
*BPSC 8th Topper*

**ILA G. PARMAR**
*IAS 2003*

सामान्य अध्ययन के कुल 600 अंक में 588 अंक और निबंध के 200 अंक नोट्स एवं कक्षा में किए गए अभ्यास के अनुरूप आया है तब अधिक भटकाव क्यों?

# G.S.

## सामान्य अध्ययन

IAS/PCS (फाउंडेशन + मुख्य + प्रारम्भिक) + टेस्ट सीरिज + मानक प्रश्न-उत्तर प्रारुप कक्षाएँ

*By*

# R. Kumar & Team

वैकल्पिक विषय के रूप में / इतिहास / का वैज्ञानिक तरीके से अध्यापन जिससे प्री० में 90 से 100 प्रश्न सही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 350 अंक

हमारे टॉपर्स

**Shashi Bhusan Singh**
*UPPCS Topper*

"G.S. और इतिहास मेरे लिए सबसे अंकदायी रहा इसका सम्पूर्ण श्रेय सर को जाता है।"

**Sunil Kumar Agarwal**
*IAS 2003*

Updated जीवंत पत्राचार

*सामान्य अध्ययन :-*
मुख्य परीक्षा - 7 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 4 Booklet
*इतिहास :-*
मुख्य परीक्षा - 3 Booklet
प्रारंभिक परीक्षा - 3 Booklet
हिन्दी साहित्य - 3 Booklet

Science & Tech. by R. Kumar IAS TUTORIALS
Economics by R. Kumar & Team IAS TUTORIALS
Indian Polity by R. Kumar IAS TUTORIALS
History by R. Kumar IAS TUTORIALS
G. Science by R. Kumar IAS TUTORIALS
...

*शुल्क एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें:-*

| अन्य विषय | इतिहास द्वारा विशेषज्ञ समूह | समाज शास्त्र द्वारा डॉ० एस.आर. सिंह | लोक प्रशासन द्वारा मनीषा सिंह | हिन्दी साहित्य द्वारा वी.एस. सिंह |
|---|---|---|---|---|

आवासीय सुविधा उपलब्ध

**आस्था IAS TUTORIALS**
102-103, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (O) 27651392 Cell.: 9810664003

1 मई, 2004 से IAS TUTORIALS का नया नाम आस्था IAS TUTORIALS हो गया है।

# चुनौतियां और संकल्प

○ पी. चिदंबरम

## (17 नवंबर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक संपादक सम्मेलन के उद्घाटन पर वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य)

यह वार्षिक सम्मेलन सरकार और मीडिया के बीच परस्पर वार्तालाप के लिए एक महत्पूर्ण मंच है – मुझे विश्वास है कि यह मंच हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक अवसर प्रदान करता है। मुझे आशा है कि इसमें आगामी दो दिनों में होने वाले विचार–विमर्शों से प्रेरणा मिलेगी और विचारों का उच्चस्तरीय आदान–प्रदान होगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) लगभग छह महीने से सरकार में है। इस अवधि के दौरान, आर्थिक दिशा में हमने कम से कम तीन चुनौतियों का सामना किया है। सबसे बड़ी चुनौती विश्वव्यापी कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से उत्पन्न हुआ, पेट्रोलियम क्षेत्र में कीमतों में स्थिरता और संरचनात्मक सुधार के लिए खतरा बना रहना है। वृहद् आर्थिक प्रबंधन और सुविचारित सक्षमशील उपायों के संयोजन के माध्यम से हमने प्रशासित मूल्यों से बाजार के माध्यम से निर्धारित मूल्यों की दिशा में पुनः बढ़ना आरंभ किया है, जबकि समग्र मुद्रास्फीति और नागरिकों पर बढ़ते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया है। दूसरे, इसी मध्य पिछले छह महीनों के दौरान देरी से मानसून आने से और इसके अल्प रहने के कारण चालू वर्ष के लिए विकास की संभावनाओं के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। ये चिंताएं कुछ सीमा तक औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के मोर्चों पर अच्छे निष्पादन से प्रतिसंतुलित हुई हैं। अल्प मानसून के बावजूद अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त पूर्तियों के बारे में चिंताएं अतिरिक्त आयात करके दूर कर ली गई हैं। तीसरे, हमें कार्यभार ग्रहण करने के लगभग तत्काल बाद घरेलू शेयर बाजारों में अस्तव्यस्तता का भी सामना करना पड़ा था। व्यापारिक अवसंरचना, जोखिम नियंत्रण तंत्र और निपटान प्रणाली इस अस्तव्यस्तता को नियंत्रित करने में समर्थ सिद्ध हुए हैं। ठोस मूल्य सिद्धांतों के साथ भयाक्रांत करने वाली धारणाओं को तेजी से दूर कर दिया गया है जिससे आरंभिक अस्तव्यस्तता बहुत पीछे रह गई है। बाजार का परिदृश्य सकारात्मक बनता गया है।

ऊर्जा की वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि के बाद भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल अपेक्षाकृत अनुकूल है। वैश्विक आर्थिक गतिविधि में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2004 में विश्व अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। बढ़ते रोजगार और समायोजनकारी वृहत् आर्थिक नीतियों के साथ–साथ बढ़ती कारपोरेट लाभप्रदता के कारण वैश्विक उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार के बने रहने की संभावना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हुए जबर्दस्त सुधार, जापान में सुधार के बेहतर संकेत और चीन तथा जापान द्वारा किए गए अच्छे कार्यनिष्पादन के कारण उभरते एशिया में उच्च वृद्धि की संभावनाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था की सकारात्मक संभावनाओं के पीछे प्रमुख चालक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए, भारत के लिए यह उपयुक्त अवसर है कि वह वैश्विक एकीकरण को सुसाध्य बनाने वाली मौजूदा नीतियों का लाभ उठाकर शेष विश्व के साथ कारोबार का विस्तार करे। हमें और सशक्त सुधारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

गत राजकोषीय वर्ष (2003–04) में हासिल की गई 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर के बाद, चालू वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुमान, जिन्हें केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किया गया है, 7.4 प्रतिशत की समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर्शाते हैं। तथापि, देश के कुछ भागों में अल्प वर्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से वर्ष की बाकी तिमाहियों में उत्पादन वृद्धि में मंदी आने की संभावना है। हाल में जारी की गई वर्ष 2004–05 हेतु वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधिक समीक्षा में, भारतीय रिजर्व

बैंक ने चालू वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में 6.0–6.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर होने का अनुमान लगया है। साथ ही यह हमारे विश्लेषण के अनुसार ही है। मैं, यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि चालू वर्ष हेतु 6 प्रतिशत जमा की अपेक्षाकृत अल्प वृद्धि दर के बावजूद भारत का संसार की एक तीव्रतम वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना रहना जारी रहेगा। पिछले वर्ष 8.2 की वृद्धि दर के साथ (जो पूर्ववर्ती रूप में 4 प्रतिशत के अल्प आधार पर थी) 6 प्रतिशत से अधिक की कोई भी वृद्धि दर संतोषजनक मानी जानी चाहिए।

चालू वर्ष के दौरान, देश में 36 मौसम--विज्ञान के उन--प्रभागों में से 13 में वर्षा काफी कम थी। इससे, पिछले वर्ष की तुलना में, खरीफ उत्पादन के समूचे स्तर पर असर पड़ने की संभावना है। तथापि, रबी फसल के लिए संभावनाएं अनुकूल रहना जारी रहीं जिससे वर्ष के लिए कृषि उपज के काफी कम स्तर के संबंध में चिंताएं शांत हो गईं। 1 नवंबर, 2004 को यथानुमानित, खाद्य स्टाक खाद्य आपूर्तियों के पर्याप्त स्तरों को दर्शाते हुए बफर मानदंडों से 6 मिलियन टन से अधिक थे।

जहां प्रचुर मानसून से कम मानसून ने हमें खेती क्षेत्र में वृद्धि संबंधी हमारी प्रत्याशाओं को धुंधला करने के लिए बाध्य किया है, वहीं पर अर्थव्यवस्था की समूची वृद्धि के संबंध में हमारा भरोसा उद्योग तथा सेवाओं द्वारा दिखाए गए लचीलेपन से मजबूत हुआ है। घरेलू औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि होना जारी है। पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद अनुमान समग्र औद्योगिक उत्पादन के लिए 6.8 प्रतिशत दर का संकेत देते हैं जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में हुई वृद्धि से लगभग एक प्रतिशतांक अधिक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से वर्ष के प्रथमार्द्ध की लगभग 7.9 प्रतिशत कुल औद्योगिक वृद्धि का पता चलता है। विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से वृद्धि पर है और यह वर्ष के दौरान गैर–पीओएल आयातों की सुदृढ़ वृद्धि में भी दृष्टिगोचर होता है। वर्ष के प्रथमार्द्ध में मुख्य आधारिक रचना वाले उद्योग जैसे विद्युत, पेट्रोलियम एवं कोयला उद्योगों ने प्रभावशाली वृद्धि दर्शाई है।

सेवा क्षेत्र जिसका योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पाद के आधे से भी अधिक होता है, ने वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर अपना संतोषजनक कार्य कायम रखा है, जो चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में सेवा क्षेत्र में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में क्षेत्र द्वारा दर्ज 7.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है।

हाल के वर्षों में भारत के बाह्य क्षेत्र ने अपनी शक्ति बढाकर वृद्धि की है। चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान देश ने चालू खाते में लगभग 2 बिलियन डालर का अधिशेष दर्ज किया है। हाल के वर्षों में देश को प्राप्त चालू खाता अधिशेष अदृश्य खाता पर अधिशेषों की बढ़ती हुई शक्ति को दर्शाते हैं जिन्होंने व्यापार खाते में घाटों को अत्यधिक निष्प्रभावित किया है। व्यापार निर्यातों में तेजी से वृद्धि हो रही है, परंतु, व्यापार आयातों में और तेजी से वृद्धि हो रही है जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी, मध्यवर्ती एवं पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए बढ़ती हुई आमेलित क्षमता को इंगित करती है। इस प्रकार, चालू वर्ष के प्रथमार्द्ध में अमेरिकी डालर की दृष्टि से निर्यात में जहां 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं तेल–भिन्न आयातों में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय निर्यातों के प्रशंसनीय कार्य ने भी ऐसे निर्यातों पर डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि के संभावित प्रभाव संबंधी अटकलों पर विराम लगा दिया।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार, हमारे कुल विदेशी मुद्रा भंडारों में राशि बढ़कर 122 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक हो गई है। वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाहों की राशि लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डालर रही, जो कि 2003–04 के प्रथमार्द्ध में प्राप्त स्तर के दुगुने से अधिक है।

चालू वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त संवेग को भी खाद्य–भिन्न ऋण की तीव्र वृद्धि में दर्शाया गया है। घरेलू पूंजी बाजारों में भी पुनर्प्राण आ गए हैं जिसे हालिया महीनों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों के अंतर्प्रवाहों की मात्रा में तीव्र वृद्धि द्वारा देखा गया है। भारतीय पूंजी बाजारों को शासित करने वाले विनियामक ढांचे को बढ़ाने और गहरा करने के प्रयास वर्ष के दौरान जारी रखे गए हैं। मैं अपने वक्तव्य के पश्च भाग के दौरान इस संबंध में किए गए कुछ विशेष उपायों पर रोशनी डालूंगा।

जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था, कीमतों पर नियंत्रण रखना हमारे लिए एक मुख्य नीतिगत चुनौती रहा है। थोक मूल्यों में हालिया वृद्धि पेट्रोलियम एवं विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण हो सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों तथा इस्पात जैसी विशेष मदों पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क दरों को कम करके किए गए राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों, दोनों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुरक्षित नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि द्वारा मूल्यों में नियंत्रण रखने के लिए अपनाया गया है।

लोक वित्त की हालत में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अधीन के नियमों को अधिसूचित करके उसे लागू किया है। यह कानून हमें, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत तक कम करने का अधिदेश देते हैं। केंद्रीय बजट (2004–05) का

लक्ष्य राजस्व तथा राजकोषीय घाटों को सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 4.4 प्रतिशत तक कम करना है। चालू वर्ष के दौरान कर संग्रहणों में उत्साहवर्धक वृद्धि ने हमें बजटीय लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में सचेतक आशावादी बना दिया है।

अब मैं विगत छह महीनों के दौरान हुए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत घटनाक्रमों पर प्रकाश डालूंगा।

सरकार परिवर्तन के पश्चात आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया की निरंतरता के संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थीं। मुझे विश्वास है कि अब तक ये सब आशंकाएं समाप्त हो गई होंगी। हमारी सरकार सुधारों के प्रति दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के मूल निर्माता डा. मनमोहन सिंह के होने से मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे कि देश में आर्थिक सुधारों का प्रबंधन सुरक्षित हाथों में है।

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अप्रतिवर्तनीय है। हम आर्थिक संवृद्धि तथा निवेश को प्रेरित करने के लिए रोजगार का सृजन करके तथा गरीबी को कम करके सुधारों को सुदृढ़ और व्यापक तथा तीव्र करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तथापि, हम मानते हैं कि आर्थिक सुधार अर्थहीन हो जाएंगे जब तक कि वे हमारे देश के आम लोगों के जीवन स्तर तथा गुणवत्ता पर एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। तदनुसार, इस बार हमारा उद्देश्य सुधार प्रक्रिया को 'जनता उन्मुखी' बनाने का है।

हमारी सरकार द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम एक अद्वितीय नीति दस्तावेज है जो हमारे देश की आम जनता की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। हमारे द्वारा अब तक अपनाई गई नीतियों तथा भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में प्रतिष्ठापित संकल्पना को हासिल करने का प्रयास करते हुए सुधार जारी रखे जाएंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था जिन कठिन समस्याओं का सामना कर रही है उनसे उबरने के लिए छह माह की अवधि काफी कम है। फिर भी, इस छोटी–सी अवधि में हमने केंद्रीय बजट और अन्य नीतियों के जरिए एनसीएमपी की प्राथमिकताओं को निष्पादित करने का प्रयास किया है। मैं आज नीतिगत घोषणाओं का संदर्भ नहीं दूंगा बल्कि केवल नीति निर्णयों और वास्तव में लागू उपायों का विवरण ही दूंगा। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

### कृषि और ग्रामीण विकास

- कृषि ऋण के संबंध में एक विस्तृत नीति 18 जून, 2004 को घोषित की गई। 30 सितंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों ने तीन वर्षों के अंतर्गत कृषि के लिए ऋण


DESTINATION IAS ACADEMY

IAS/PCS (Pre-CUM-Mains - 2005-06)
U.G.C. / NET / SLET

भूगोल
द्वारा
संजय सिंह

लेखक :
1. क्रॉनिकल भूगोल
2. क्रॉनिकल वस्तुनिष्ठ भूगोल
3. क्रॉनिकल भारत एवं विश्व का भूगोल

सामान्य अध्ययन /G.S. द्वारा
कैलाश मिश्रा
संजय सिंह
डी. आचार्य

समाज शास्त्र/Sociology
द्वारा प्रवीन किशोर

विशेषताएँ
1. विषय के सभी खण्डों का विस्तृत विवेचन
2. संभावित एवं विगत वर्षों के प्रश्नों की सविस्तार चर्चा
3. साप्ताहिक टेस्ट एवं मूल्यांकन
4. पूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री
5. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सत्र
6. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में अलग–अलग कक्षाएँ

किन्हीं दो विषयों पर विशेष छूट, पत्राचार सविधा उपलब्ध

इतिहास
द्वारा
डी आचार्य
(के दक्ष निर्देशन में)

राजनीति विज्ञान/ Pol. Sci.
द्वारा
कैलाश मिश्रा

भूगोल
FOUNDATION COURSE BEGINS
Maximum Output in Minimum Input

मुख्य संपादक :
ट्रेण्ड एनैलिसिस

लेखक :
1. भारतीय अर्थव्यवस्था
2. भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3. बदलते हुए परिदृश्य में भारत की विदेश नीति

at B-12, COMMERCIAL COMPLEX
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI - 9
Mob.: 9868080491, 9868338235, 9818329854

SNEWS : 9811124003

प्रवाह को दुगुना करने की दृष्टि से कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए 41,937 करोड़ रुपये संवितरित किए।

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 1 अप्रैल, 2004 के प्रारंभ से अगले तीन वर्षों में 5.85 लाख स्व–सहायता समूहों के संवर्द्धन और उन्हें बैंक से जोड़ने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। 31 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष हेतु 1.85 लाख के लक्ष्य के समक्ष 86,377 स्व–सहायता समूहों को 110 करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्रदान कर ऋण सुविधा से जोड़ा गया है।
- देश में सहकारी ऋण प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु एक कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना की सिफारिश करने के लिए एक कृतिक बल स्थापित किया गया है। इस कृतिक बल की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केंद्रीय ऋण सहायता (सीएलए) प्राप्त कर रही कुल 181 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 37 परियोजनाओं की पहचान वर्ष 2004–05 के दौरान और शेष 46 परियोजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने के लिए की गई है।
- वर्ष 2004–05 के लिए 8,000 करोड़ रुपये की संचित निधि के साथ ग्रामीण ढांचागत विकास निधि (आरआईडीएफ) को पुनर्जीवित किया गया है और 908 करोड़ रुपये की योजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।
- त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) को 3148 करोड़ रुपये की बजट में रखी राशि के समक्ष 1485.16 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
- कृषि से सीधे रूप से जुड़े जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और उन्हें पुनः चालू करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल संसाधन विकास योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें प्रायोगिक स्कीम तैयार करने के लिए परियोजना प्रस्तावों हेतु अनुरोध करते हुए राज्यों को भेज दिया गया है। हमारा इरादा इस स्कीम के कार्यों को 1 जनवरी, 2005 से शुरू करने का है।
- 200 करोड़ रुपये के परिव्यय और 100 करोड़ की केंद्रीय सब्सिडी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए एक जल संचयन स्कीम शुरू की गई है। चालू वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपये संवितरित किए जाने की संभावना है।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसका उद्देश्य बागवानी उत्पादन को दुगुना करके वर्ष 2011–12 तक 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 300 मिलियन टन पर लाना है। शीघ्र ही इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
- तिलहन/खाद्य तेल के उत्पादन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसका उद्देश्य बागवानी उत्पादन को दुगुना करके वर्ष 2011–12 तक 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 300 मिलियन टन पर लाना है। शीघ्र ही इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
- तिलहन/खाद्य तेल के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 'तिलहन, दाल, आयल पाम तथा मक्का की समेकित योजना जो केंद्रीय प्रायोजित हैं, देश के 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। सरकार तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु तिलहन के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कार्यान्वित कर रही है और उन्हें लाभप्रद मूल्य प्रदान करने का सुनिश्चय करती है।
- कृषि आय बीमा योजना के अलावा, जिसे गेहूं तथा धान (रबी) की फसलों हेतु चुनिंदा जिलों/राज्यों में रबी 2003–04 के दौरान प्रारंभ किया गया था, खरीफ 2004 के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर 'वर्षा बीमा योजना' नाम से एक मौसम बीमा योजना प्रारंभ की गई थी।
- ग्रामीण आवास निर्माण में बढ़ोत्तरी को तेज करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी वित्तपोषण सुविधा दरों को 50 आधार बिंदु तक घटा दिया है।

**रोजगार सृजन**

- चालू अंत्योदय अन्न योजना के विस्तार को इसमें अन्य 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जोड़कर बढ़ाया गया है।
- गरीबों में प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने की वैधानिक गारंटी प्रदान करने हेतु आशयित राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम विचाराधीन है और इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

**आधारभूत संरचना**

- आईडीबीआई, आईडीएफसी, आईसी आईसीआई बैंक, एसबीआई, एलआईसी, बड़ौदा बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक सहित वित्तीय संस्थाओं के एक अंतर–संस्थागत समूह की स्थापना ढ़ांचागत परियोजनाओं को त्वरित कार्यान्वित करने हेतु की गई है जिसमें विशेष रूप से विमानपत्तन, नौपत्तन तथा पर्यटन पर जोर दिया गया है।
- केंद्र सरकार के बजट (2004–05) में

की गई घोषणाओं के बाद, पत्तन क्षेत्र में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। तूतीकोन पत्तन न्यास को सेतुसमुद्रम् पोत नहर परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए ठेका दिया गया है। इस रिपोर्ट के शीघ्र पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा, कोच्चि पत्तन में वलारपदम् पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर नौकांतरण टर्मिनल के विकास हेतु 'बनाओ, परिचालित करो तथा अंतरित करो' (बीओटी) आधार पर 30 वर्ष की समयावधि के लिए मैसर्स दुबई पोर्टस इंटरनेशनल को ठेका दिया गया है।

- नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

**शिक्षा**

- वाणिज्यिक बैंकों ने 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों के लिए सहवर्ती अपेक्षा को हटा दिया है। 31 अगस्त, 2004 तक 915.47 करोड़ रुपये के 61,460 नए विद्यार्थी ऋणों को संवितरित कर दिया गया है।

**स्वास्थ्य**

- सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) का विशिष्ट रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के व्यक्तियों एवं परिवारों के हितों के लिए पुर्नअभिकल्पन किया गया है। योजना के अंतर्गत संशोधित प्रीमियम क्रमशः व्यष्टियों, पांच सदस्यों के एक परिवार और सात सदस्यों के एक परिवार के लिए क्रमशः 165 रुपये और 330 रुपये है। योजना 20 सितंबर, 2004 से प्रवृत्त हुई हे।
- देश में एड्स और एचआईवी से जूझने के लिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चालू पहलों के अतिरिक्त विशिष्ट उपाय आरंभ किए गए हैं। देशभर में एचआईवी महामारी के विस्तार का पता लगाने के लिए 215 सेंटिनल साइटों की स्थापना की गई है। सुरक्षित यौन संबंधों के संवर्धन पर लक्षित संकेंद्रित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एचआईवी/एड्स से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा लोक माध्यम का सक्रियता से प्रयोग किया जा रहा है।

**वरिष्ठ नागरिक**

- दिनांक 2 अगस्त, 2004 से 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रस्तावित एक नई वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आरंभ की गई है।

**लघु उद्योग**

- विशेषतयाः लघु उद्योगों द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में से पचासी मदों को हटा दिया गया है।
- लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण व इक्विटी मार्गों के माध्यम


AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES IAS/IPS

**IAS/PCS**

**आरोहण**

(हिन्दी माध्यम)

"आपके सपनों से मंजिल तक"

**उपलब्ध विषय :-**

| | | |
|---|---|---|
| भूगोल (प्रा०+मु०) | : | राजीव सौमित्र |
| दर्शनशास्त्र (मु०) | : | डा० ए० के० मिश्रा |
| हिन्दी साहित्य | : | डा० निर्मला गुप्ता |
| संस्कृत साहित्य | : | ललित मण्डल |
| इतिहास | : | D.U. के प्रख्यात प्रो० (मु०) डा० ए० के मिश्रा (प्रा० |
| लोक प्रशासन | : | डा० निमिषा गौड़ |
| सामान्य अध्ययन | : | संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा |
| निबन्ध | : | डा० एस० एस० पाण्डे |
| साक्षात्कार | : | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व संबंधित विशेषज्ञों द्वारा |
| पर्सनालिटी डेवलपमेंट | : | विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क (सिर्फ संस्थान के छात्रों के लिए) |

UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र/छात्राओं को निश्चित रुप से एक ऐसी चुनौती मिलती है जिसे लगन, मेहनत, समर्पण व इच्छा शक्ति से ही पूरा किया जा सकता है। देश के दूर-दराज इलाकों से आने वाले छात्रों की एक बड़ी समस्या उचित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व मार्गदर्शन का न मिल पाना है। लिहाजा छात्र/छात्राओं को अपना कीमती समय भटाकव में गुजारना पड़ता है। मध्यम आय वर्ग व कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र/छात्रा, फीस की एक मोटी रकम देने में सक्षम नहीं होते। इसी के मद्देनजर कम फीस में ही हमारा संस्थान एक बेहतर शिक्षण व कुशल मार्गदर्शन की व्यवस्था करता है।

**विशेष आकर्षण:**

सिविल सेवा के अभ्यर्थियों विशेषकर हिन्दी माध्यम के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुनः उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है। विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अतः यहाँ के विशेषज्ञ (यदा-कदा प्रशासनिक अधिकारी भी) द्वारा अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन दिया जाता है।

**संस्थान के सलाहकार सदस्य :** अजीत कुमार (IAS अधिकारी) एस० डी० तिवारी (PCS अधिकारी)

✦ छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था।
✦ पत्राचार कोर्स उपलब्ध।

☞ विशेष जानकारी व मार्गदर्शन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी "अंशुमन" से दूरभाष या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर सम्पर्क करें।

**204, IInd Floor, A-23-24, Satija House, Commercial Complex (Near Batra Cinema) Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Tel. :(Off.) 011-27652362, (Mob.) 0-9868259370**

से बाजार से संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को संशोधित किया गया है।

**पूंजी बाजार**

- प्रतिभूति सौदों से दीर्घावधिक पूंजी लाभों को कर मुक्त किया गया है। अल्पावधिक पूंजी लाभ कर की दर घटाकर 10 प्रतिशत की एक समान दर कर दी गई है।
- वित्तीय बाजार सौदों के संबंध में कर संग्रहणों को सरल एवं कारगर बनाने के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) लगाया गया है।
- घरेलू स्टाक एक्सचेंजों को म्यूचुअल संगठनात्मक रूपों से पृथक्कीकृत रूपों में बदलने के लिए विधायी ढांचे की व्यवस्था हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 संशोधित किया गया है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लघु निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु प्राथमिक प्रतिभूति बाजार को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी व निवेशक–केंद्रिक बनाते हुए कतिपय उपाय किए हैं। इनमें सुकारक गुणवत्ता निर्गमों हेतु निर्गम मानकों की शुरुआत, प्राथमिक बाजार में संसूचित निर्णय लेने में निवेशकों की सहायता करने के लिए वर्द्धित प्रकटीकरण मानदंड, पणधारकों के लिए वहनीय मूल्य के सृजन हेतु पारदर्शी व वृद्धित कारपोरेट अभिशासन मानक, शेयरों की संख्या की तुलना में आवेदनों के मूल्य के आधार पर लघु निवेशक की परिभाषा बदलना तथा कृत्रिम कारकों व बाजार शक्तियों के लिए संवेदनशील मूल्य खोज को निरापद बनाने के लिए बही निर्माण मार्गनिर्देशों का पुनरीक्षण शामिल हैं।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए ऋण निधियों में निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि को अधिसूचित कर दिया गया है जिसके बाद यह 1 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 1.75 बिलियन अमेरिकी डालर हो गई है।
- सेबी ने, बैंकों तथा उनकी अनुषंगी कंपनियों के मामलों को छोड़कर, विदेशी संस्थागत निवेशकों के पंजीकरण संबंधी आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई करने संबंधी समय अवधि को 13 कार्य दिवसों से घटाकर 7 कार्य दिवस कर दिया है।
- एक्सचेंजों के नकदी खंडों के दलालों द्वारा देय पंजीकरण शुल्क संबंधी समस्या के संतोषजनक समाधान के लिए सेबी ने 15 जुलाई, 2004 से सेबी (ब्याज देयता नियमन) स्कीम, 2004 को आरंभ किया है।
- एक समिति, जिसका गठन विशिष्ठ क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया था जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशक पोर्टफोलियों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी क्षेत्रीय सीमाएं लागू नहीं होंगी, ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की इस रिपोर्ट को व्यापक प्रसार एवं चर्चा के लिए वित्त मंत्रालय की वेब साईट पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

**राजकोषीय उपाय**

- राज्य वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 18 जून, 2004 को आयोजित बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि राज्य स्तर पर पहली अप्रैल, 2005 में मूल्यवर्धित कर (वैट) को लागू किया जाए। वैट के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करने वाली एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का भी गठन कर दिया गया है। राज्यों को राजस्व, हानि के मामले में क्षतिपूर्ति के मुद्दों पर सहमति बन गई है।
- राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) ने आर्थिक राज्य सहायता को कारगर ढंग से लक्षित करने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की है। संसद के समक्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पूर्व इस रिपोर्ट की इस समय जांच की जा रही है।
- राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय ऋणों पर ब्याज दर 1 अप्रैल, 2004 से 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है।

इन उपायों के अलावा, जो कि पहले ही कार्यान्वित या शुरू किए जा चुके हैं, अनेक और उपाय भी कार्याभिमुखी हैं। मैं जरूर यह बात दोहराना चाहूंगा कि ऐसे अनेक नीतिगत मुद्दे हैं जिनपर हम राज्यों के साथ निकटता से समन्वय करके कार्य कर रहे हैं।

ये विशेष तौर पर रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन, कृषि, ग्रामीण विकास, मानव विकास, अवसंरचना और लोक वित्त से संबंधित नीतियों से जुड़े हैं। ये सभी उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं, जैसाकि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) द्वारा बताया गया है। हम जानते हैं कि हमारी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, यह जरूरी है कि अनेक क्षेत्रों में नीतियां विकेंद्रित प्रक्रिया के जरिए रूप–आकार ग्रहण करें। तदनुसार हम देश के विभिन्न भागों में लोगों की विशिष्ट जरूरतों को आकलन करने के लिए सभी प्रासंगिक मुद्दों पर राज्यों से साथ विचार–विमर्श कर रहे हैं और इन नीतियों को इन जरूरतों के अनुरूप बना रहे हैं।

भारत और उसकी जनता ने एक अधिक प्रतिष्ठित, सम्मानजनक और समृद्ध जीवन मुहैया कराने के लिए हमें जनादेश दिया है। हम विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकारते हैं और अपने देश की जनता द्वारा हमें सौंपे गए विश्वास के प्रति आभारी हैं। मैं उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करता हूं। ❑

फाउण्डेशन कोर्स **I.A.S : 2005** (Pre-cum-Main)

# इतिहास
द्वारा रमेश चन्द्रा

# सामान्य-अध्ययन एवं निबन्ध
द्वारा रमेश चन्द्रा एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ

# दर्शनशास्त्र
द्वारा उपेन्द्र कुमार

**मुख्य-परीक्षा** 'मुख्य-परीक्षा में सफलता विषय के प्रामाणिक ज्ञान तथा उसके सम्यक् प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है।'

**विशेषतायें**

- तीन महीने का विस्तृत कार्यक्रम
- प्रत्येक टॉपिक पर व्याख्यान।
- टॉपिक से संबंधित संभावित प्रश्नों का उत्तर-प्रारूप एवं उत्तर लेखन।
- उत्तर लेखन पर विशेष बल, अतिरिक्त कक्षायें।
- प्रत्येक विषय पर विगत वर्षो के प्रश्नों का विश्लेषण।
- यू० पी० एस० सी० पद्धति पर साप्ताहिक मॉडल टेस्ट
- सम्पूर्ण कम्प्यूटराईज्ड अध्ययन सामग्री।

**नामांकन प्रारम्भ**

**विशेष**

प्रारम्भिक परीक्षा टेस्ट सीरीज (कुल २० टेस्ट) - प्रारम्भ 16 जनवरी से
प्रारम्भिक परीक्षा मूल्यांकन टेस्ट सीरीज - प्रा० परीक्षा के एक माह पूर्व
मुख्य परीक्षा मूल्यांकन टेस्ट सीरिज - मुख्य-परीक्षा के एक माह पूर्व
साक्षात्कार - मुख्य-परीक्षा परिणाम के ३ दिन पश्चात्

## I.A.S. : 2005 नया सत्र : 29 नवम्बर एवं 5 जनवरी

**प्रारम्भिक-परीक्षा**

- विगत 2-3 वर्षों में प्रा० परीक्षा प्रश्न-पत्र के स्वरूप में आये परिवर्तन के अनुरूप अध्ययन सामग्री एवं कक्षा-योजना।
- उ० प्र०, उत्तरांचल, म० प्र०, बिहार, राजस्थान झारखण्ड छत्तीसगढ़ आदि राज्य सेवाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का समावेश।
- प्रत्येक टॉपिक के समापन के पश्चात् प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न पर टेस्ट।
- परीक्षा के एक माह पूर्व आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की तरह 5 छद्म-परीक्षाओं का आयोजन

**Lodging & Fooding Facility Arranged**

## राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का संयोजन दूर स्थित विद्यार्थियों एवं क्लास-कोचिंग लेने में असमर्थ विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है।

**विशेषताऐं:**

- पूर्णतया संशोधित सामग्री
- विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तर जाँच की डाक द्वारा व्यवस्था।
- कार्यक्रम में नामांकित छात्रों की समस्याओं का सीधे 'रमेश चन्द्रा' सर के द्वारा साप्ताहिक निवारण।

**विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास, दर्शनशास्त्र, हिन्दी साहित्य**

**फीस:** मुख्य परीक्षा (प्रति विषय)- 2500/- रुपये मात्र।
प्रारम्भिक परीक्षा (प्रति विषय) - 2000/- मात्र।

नोट: कार्यक्रम में नामांकन हेतु दिल्ली में भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट 'रमेश चन्द्रा' के नाम निम्न पते पर भेजें।

**द हिस्टोरिका**

2063(BASEMENT), OUTRAM LINES, KINGSWAY CAMP, DELHI- 9
TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

# तेल–मूल्य और भारतीय अर्थतंत्र

○ वेद प्रकाश अरोड़ा

*हालांकि विश्व में तेल की प्रचुरता है, फिर भी कुछ देश, सरकारें अथवा तेल कंपनियां अपने स्वार्थों के लिए तेल मूल्यों को घटाने–बढ़ाने का खेल खेलती रहती हैं। भारत अभी तक मूल्यों में वृद्धि का सफलतापूर्वक सामना करता आया है लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती।*

अगर किसी आधारभूत वस्तु के मामले में कोई देश पराश्रयी हो, तो वह उस देश के अर्थतंत्र के लिए कितना भारी पड़ता है– इसका ज्वलंत और पीड़ाकारी प्रमाण है भारत में कच्चे तेल की कमी। इसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के निरंतर बढ़ते जाने और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 56 डालर प्रति बैरल को पार कर जाने से न सिर्फ विश्व के शेयर और अन्य बाजारों में हड़कंप मच गया है बल्कि उसने मजबूत से मजबूत अर्थतंत्र वाले देश को जड़ से हिलाकर रख दिया है। न सिर्फ महंगाई ऊंचे आसमान पर बढ़ती चली गई है, बल्कि कहीं–कहीं मंदी की काली छाया भी पैर पसारने लगी है। डालर का मूल्य कम हुआ है तो सोने का मूल्य बढ़ा है। अनुमान है कि सोने का मूल्य जल्द 450 डालर प्रति औंस को स्पर्श करने लगेगा। एशिया के शेयर बाजारों, जैसे– निक्केई और हांगकांग के सूचकांक लुढ़कने लगे और कंपनियों की कमाई भी घट गई। इस कड़वे सच से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कच्चे तेल के दाम में बेतहाशा वृद्धि ने सभी देशों को झकझोर दिया है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और रसाई गैस जैसे पेट्रो उत्पादों के महंगे होने से न सिर्फ खाने–पीने की चीजों, जैसे – सब्जियां, फल दालों, तिलहनों के मूल्य बल्कि बसों–टैक्सियों, ट्रकों, रेलों के किराए और सोना–चांदी तक की कीमत यानी जीवन को जीने लायक बनाने की हर चीज कमोबेश महंगी हो गई है। तेल–उत्पादों के मूल्य में वृद्धि, संक्रामक रोग की तरह रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर राजसी और रईसी–ठाठ की वस्तुओं तक के दामों को ऊंचाइयों पर ले गई है। बढ़ते मूल्यों का चक्र एक सिरे से आरंभ होकर दूसरे सिरे तक सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित करता चला गया है। कर्मचारियों, गृहणियों, विद्यार्थियों, व्यावसायियों, व्यापारियों, किसानों और मजदूरों – सभी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन चुनावों में अपनी जन हितकारी छवि बनाए रखने के लिए पिछली सरकार की तरह वर्तमान सरकार ने भी तेल के बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रकोप से यहां की जनता को

ढाल बन कर बचाए रखा और विश्व बाजार में कच्चे तेल के भाव प्रति बैरल 56 डालर के रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाने के बावजूद तेल कंपनियों को मूल्य बढ़ाने से रोके रखा था। जब वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 15 नवंबर तक इन्हें न बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन घाटे के महाकार लेते जाने और तेल कंपनियों के लिए भारी घाटा बर्दाश्त के बाहर होते जाने के कारण, मजबूरी में और भारी मन से सरकार ने 4 और 5 नवंबर के बीच की मध्यरात्रि से रसोई गैस के दाम 20 रुपये प्रति सिलेंडर, पेट्रोल के दाम 2 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की। लेकिन गरीब के ईंधन – मिट्टी के तेल के दाम ज्यों के त्यों बनाए रखे गए हैं। रसोई गैस की कीमत तब तक प्रत्येक महीने पांच–पांच रुपये बढ़ाई जाती रहेगी जब तक उसमें आयात मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर समाप्त नहीं हो जाता। उधर डीज़ल दाम के मामले में हल्की राहत देते हुए वृद्धि को बढ़े हुए आयात मूल्य के अंतर के आधे तक सीमित रखा गया है। सच तो यह है कि जब से तेल की कीमत का मामला प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था से हटाकर बाजारवादी ताकतों के भरोसे छोड़ा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर या उससे कुछ कम घरेलू मूल्यों को लाए जाने को लंबे समय तक टालना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया था। लगभग एक वर्ष पहले कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल 30 डालर के आसपास था, लेकिन यह मूल्य दुगुना होने के कगार तक पहुंच कर अब 48 से 55 डालर प्रति बैरल के बीच चल रहा है।

भारत में वर्ष 2002 से वर्ष 2003 तक तेल का मूल्य कमोबेश स्थिर रहा या मंथर गति से बढ़ा लेकिन वर्ष 2004 के दौरान इसमें लगभग हर महीने उछाल आता चला गया, हालांकि बाजार में उसकी आपूर्ति पर्याप्त बनी रही। मोटे अनुमान के अनुसार पिछले दस–ग्यारह वर्षों के दौरान तेल की मांग में प्रत्येक वर्ष औसतन 1.6 से 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि इस वर्ष यह तेजी से चढ़कर तीन–चार प्रतिशत के आसपास पहुंच गई। इधर भारत में 4.1 प्रतिशत की औसत चक्रवृद्धि दर से मांग बढ़ती जा रही है, जो चीन और मैक्सिको की 3.8 प्रतिशत मांग से भी अधिक है। यह खतरे की घंटी को रह–रह कर बजा रही है। कारण, यह वृद्धि विश्व में सर्वाधिक है। तेल विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2025 तक विश्व की कुल खपत में एक तिहाई मांग भारत और चीन की होगी। तब तक भारत की तेल मांग लगभग दुगुनी हो जाएगी और वह चीन की कुल मांग के बराबर पहुंच सकती है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में तेल और गैस के मात्र 0.4 प्रतिशत भंडार हैं, जबकि पश्चिम एशियाई देशों में 65 प्रतिशत सुरक्षित भंडार हैं। तेल और गैस की साढ़े बारह करोड़ टन की खपत के कारण इस समय भारत अन्य आयातकों की सूची में सबसे ऊपर है। जापान, कोरिया, यूरोपीय देशों और घाना की तरह भारत हमेशा तेल का आयातक देश बना रहेगा। 1990 के दशक से भारत में कच्चे तेल का उत्पादन निरंतर कम होता चला गया है। 1991 में विदेशी तेल पर भारत की निर्भरता 30 प्रतिशत थी, जो बढ़ते–बढ़ते इस समय 70 प्रतिशत हो गई है। इसका मूल कारण है उत्पादन कम और मांग अधिक। कुछ पीछे मुड़कर देखने पर हम पाते हैं कि जनवरी 1991 में खाड़ी युद्ध आरंभ होने के समय हम कच्चे तेल की अपनी जरूरत के एक तिहाई से भी कम का आयात करते थे। बांबे हाई का उत्पादन भी लगभग अधिकतम स्तर पर पहुंच गया था। तब पेट्रो उत्पादों की आंतरिक मांग देश में कच्चे तेल के उत्पादन से अधिक नहीं थी। तब कम आयात के कारण भारत के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की वृद्धि से प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन अगले 12 वर्षों में स्थिति में बदलाव आता चला गया और देश कच्चे तेल के आयात पर अधिकाधिक निर्भर होता चला गया। यह स्थिति बाहरी परिदृश्य से बिल्कुल अलग है। तेल निर्यातक देशों के संगठन के इंडोनेशियाई अध्यक्ष पोरनोमो युसगियानतोरो के अनुसार इस समय कच्चे तेल का विश्वव्यापी उत्पादन प्रतिदिन खपत से लगभग 21 लाख से 25 लाख बैरल अधिक हो रहा है। भंडारों में तेल भरा पड़ा है। इसलिए कच्चे तेल की सप्लाई में कमी का कोई सवाल नहीं है। अगर इस समय तेल मूल्य 55–56 डालर के आसपास चल रहे हैं तो इसमें दस से पंद्रह डालर की राशि राजनीतिक जोखिम के प्रीमियम की है। इसका सीधा संबंध भौगोलिक और राजनैतिक मुद्दों से होता है और इसका विश्व के तेल बाजार से कोई सरोकार नहीं होता। तेल निर्यातक संगठन ओपेक के अनुसंधान विभाग के निदेशक डा. अदनान शिहाब आलदिन का विचार है कि मांग के आधार पर आपूर्ति बने रहने से मूल्य में कोई खास अंतर नहीं पड़ता लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता और अप्रत्याशित अथवा असाधारण घटनाओं के कारण गुड़गोबर हो जाता है। अगर स्वयं तेल उत्पादक देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए तो भी तेल की आपूर्ति में रुकावट पड़ सकती है। तेल की कीमत में वृद्धि बाजार और बाजारी शक्तियों के कारण भी हो जाती है। ओपेक सदस्यों का भी विचार है कि कच्चे तेल की कीमत के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने में तेल निर्यातक देशों का कोई सीधा हाथ नहीं है। पर सभी पर्यवेक्षक इस विचार से सहमत नहीं हैं। हमारे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम तेल मूल्य में रिकार्ड तोड़ वृद्धि के लिए ओपेक देशों को जिम्मेदार ठहराते हैं। बहरहाल, तेल मूल्य बढ़ने के कई अन्य स्थाई–अस्थाई कारण हैं। आज विश्व द्रुतगामी यातायात और

# LUCKNOW CHAPTER
# SOCIOLOGY for IAS, PCS & UGC-NET

## Social Issues & Essay

## By A.P. PANDEY (Renowed Expert)

**"The Man who made SOCIOLOGY a Safer Optional"**

- **Discussion & revision sessions**
- **Topic based Study material is given**
- **Review of previous year questions**

IAS मुख्य परीक्षा 2004 में समाजशास्त्र के दोनों प्रश्न पत्रों में पाण्डेय सर के पढ़ाये समस्त प्रश्न पूछे गये, तथा निबन्ध एवं सामान्य अध्ययन (द्वितीय प्रश्न पत्र) में, महिला मुक्ति किस ओर ? वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत की संस्कृति पर उसका प्रभाव, मानवाधिकारों के क्षेत्र में एमनेस्टी इण्टरनेशनल की विशेष भूमिका, आज के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नेहरू जी के विचारों की प्रासंगिकता।

### OTHER SUBJECTS & FACULTY

| | | |
|---|---|---|
| History | : | Dr. Misra, Dr. Dixit, Dr. S.K. Pandey |
| Pub-Ad. | : | D. N. Pandey (Allahabad) & Others |
| Geography | : | D. K. Misra (Delhi)& Others |
| Economics | : | Anand Shukla (Allahabad) & Others |
| Philosophy | : | Kaushlendra Tewari & Others |
| Hindi Lit. | : | Dr. A. Dixit, Dr. R.P. Diwedi & Others |
| Zoology | : | Dr. Himanshu Rai |
| Botany | : | Dr. R.S. Chauhan |
| Law/PCS(J) | : | Dr. Avatar Singh*, (Course Direct). Prof. G.P. Tripathi*, Dr. O.P. Srivastava*, Dr. R.A. Yadav Dr. Sant Kumar & Others |

*सुप्रसिद्ध लेखक एवं विधि विशेषज्ञ

### GENERAL STUDIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| History | : | Ancient : | Dr. A. Dixit/ Dr. Pandey |
| | | Medival : | Dr. D.V. Misra / Dr. Sharma |
| | | Modern : | Mr. S. Ahmad / Dr. Misra |
| Science & Tech. | : | Er. K. Tewari & Prof. S.C. Srivastava | |
| Statistics & Maths | | | |
| Indian Economy | : | Anand Shukla (Allahabad) & Others | |
| Geography | : | D. K. Misra (Delhi) & Others | |
| Indian Polity | : | D.N. Pandey (Allahabad) & Others | |
| Current Affairs | : | Current Events - Er. K. Tewari / Dr. Misra<br>National & International Org.-A.P. Pandey | |

### FREE WORKSHOP & BATCHES

**GS & PUB-AD.**
on 1st & 28th Dec., 2004 at 10 AM

**SOCIOLOGY & HISTORY**
on 5th & 29th Dec., 2004 at 1 PM

**PCS (J)**
on 3rd & 28th Dec., 2004 at 3 PM

**ZOOLOGY, BOTANY & PHILOSOPHY**
on 6th & 22nd Dec., 2004 at 9 AM

**ECONOMICS** - 27th Dec., 2004 at 10 AM

**GEOGRAPHY** - 28th Dec., 2004 at 4 PM

- Classes for **UGC-CSIR, NET/JRF** Starting in all the subjects (Humanities & Life Science) from 1st week of Jan. 2005
- Separate Classes for UGC-CSIR, NET-1st Paper

# TIMES IAS ACADEMY® IAS/PCS, PCS(J) for UGC-CSIR NET/JRF

**B-33, Sector-C, (Near Aliganj Post Office) Aliganj, Lucknow**

**PHONE : 0522 - 2010651, 9415548748**

आधुनिक संचार साधनों से परस्पर इतना सट गया है कि अगर इराक और सऊदी अरब में तेल क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों या तेल पाइप लाइनों पर आतंकवादी हमले हो जाएं या अन्यत्र किसी एक तेल क्षेत्र में समुद्री तूफान आ जाए, विनाशकारी भूकंप आ जाए, राजनीतिक उथल–पुथल हो जाए, गृह–युद्ध जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाए, जबदस्त हिंसात्मक घटनाएं हो जाएं, या अन्य विस्फोटक स्थिति पनपने लगे तो तेल के मूल्य एकदम बढ़ जाते हैं। जैसे 1979 में ईरानी क्रांति के दौरान तेल मूल्य 80 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। ओपेक के तीसरे बड़े तेल उत्पादक देश वेनेजुएला में राजनीतिक तनाव क्या पैदा हुआ कि तेल उत्पादन में गिरावट आ गई। इसी तरह नाइजेरिया में श्रमिक हड़ताल से तेल उत्पादन बंद हो गया तो मैक्सिको खाड़ी में इवान नाम के समुद्री तूफान से जहाजों पर तेल का लदान और उसकी ढुलाई का काम बंद रहा, नार्वे के जहाज मालिकों की संस्था ने तेल रिग श्रमिकों के लॉक आउट को बढ़ा दिया तो रूस में प्रमुख तेल कंपनी युकोस के वित्तीय घोटाले ने तेल उत्पादन में व्यवधान डाल दिया। इसी तरह स्पेन में बम विस्फोटों के बाद तेल की सप्लाई कम हो गई। उत्तरी गोलार्द्ध में कड़ाके की ठंड के कारण अमेरिका में गरमाने वाले तेल और डीजल की सप्लाई अपर्याप्त हो गई। वहां गर्मियों की तुलना में सर्दियों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग काफी बढ़ जाती है। सर्दियों में पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने से तेल खपत में भारी वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रपति पद के धुंआधार चुनाव प्रचार के लिए भी तेल की मांग से कहीं ज्यादा उछाल आया। जर्मनी और जापान जैसे देशों में कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए ईंधन भंडार को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यूरोप और अन्यत्र तेल की कमी हो जाने से उसका मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। बढ़ती मांग और घटती सप्लाई के अलावा सट्टेबाजी भी तेल उपभोक्ताओं पर कहर ढहा देती है। इधर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस वर्ष रबी की फसल की बुवाई के आरंभिक दौर में मानसून की वर्षा कम होने से कृषि विकास दर तीन प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगी। तेल–मूल्यों में वृद्धि और कृषि विकास दर में संभावित गिरावट के कारण इस वित्त वर्ष में 6 से 6.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद दर से संतोष करना पड़ेगा, जबकि पहले 6.5 से 7 प्रतिशत सकल घरेलू का अनुमान लगाया गया था। वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम के अनुसार अगर तेल–मूल्य प्रति बैरल पांच डालर बढ़ जाएं तो सकल घरेलू उत्पाद आधा प्रतिशत कम हो जाता है और मुद्रास्फीति डेढ़ प्रतिशत बढ़ जाती है। हालांकि विश्व में तेल की प्रचुरता है, फिर भी कुछ देश, सरकारें अथवा तेल कंपनियां अपने स्वार्थों के लिए तेल मूल्यों को घटाने–बढ़ाने का खेल खेलती रहती हैं। भारत अभी तक मूल्यों में वृद्धि का सफलतापूर्वक सामना करता आया है लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसका मुद्रास्फीति और अर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक के अनुसार प्रति बैरल कच्चे तेल के मूल्य में एक अमेरिकी डालर की वृद्धि हो जाने से हमारे तेल आयात बिल में 60 करोड़ अमेरिकी डालर यानी लगभग 2800 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाती है। भारतीय तेल निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और आईबीएम को तेल के बढ़े अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण अप्रैल से सितंबर तक के 6 महीनों में 2100 करोड़ (21 अरब) रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। इधर रसोई गैस पर प्रति सिलेंडर 158 रुपये का घाटा हो रहा है तो उधर मिट्टी के तेल की सब्सिडी पर 11 रुपये प्रति लीटर देने पड़ते हैं। इन दोनों चीजों की सब्सिडी पर इन कंपनियों को 4900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। घाटे की कुछ भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां डीजल के दाम एक रुपये और पेट्रोल के दाम 60 पैसे लीटर बढ़ाने की मांग कर रही हैं।

कुछ खामियों के रहते हुए आज हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद इतनी मजबूत रफ्तार, इतनी तेज और विस्तार इतना बहुआयामी हो चुका है तथा वह अनुकूल और प्रतिकूल हालात में अपने को तदनुरूप ढालने की इतनी क्षमता और लचीलापन हासिल कर चुकी है कि कच्चे तेल और तेल उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रिकार्ड तोड़ ऊंचाई पर चले जाने के बावजूद वे उसमें यहां–वहां खम ही डाल सके हैं। हर महीने तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में उछाल पर उछाल आने से अर्थतंत्र पर कई दबाव पड़े हैं और उसे कई झटके भी लगे हैं। फिर भी निर्यात की गति सराहनीय रही है, लेकिन आयात उससे भी अधिक होने से व्यापार में कुछ असंतुलन बना रहा है। मौद्रिक नीति में फेरबदल से मुद्रास्फीति कम हुई है, लेकिन वह पिछले वर्ष चार–पांच प्रतिशत की मुद्रास्फीति की अपेक्षा काफी अधिक है और वह इस समय कमोबेश 7 प्रतिशत चल रही है। महंगाई भी कुछ बढ़ी है। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस वर्ष सितंबर के आरंभिक दो सप्ताहों में मुद्रास्फीति की दर आठ प्रतिशत से आगे निकल कर 8.33 प्रतिशत तक पहुंच गई थी जो चार वर्षों में सर्वाधिक थी। सरकार ने तुरंत हरकत में आकर पेट्रो उत्पादों और इस्पात के सीमा और उत्पादन शुल्कों में कटौती तथा खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी कर दी और रिजर्व बैंक में जमा राशियों के लिए अनुसूचित बैंकों का नकदी आरक्षण अनुपात बढ़ा कर बाजार से नकदी को समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि बाजार में अधिक नकदी आने से कीमतें बढ़ जाती है। पैसा कम

होगा तो खर्च भी कम होगा और मुद्रास्फीति भी सिमटने लगेगी।

कीमतों पर अंकुश को और कसने के लिए सरकार ने फिर दूसरी बार 18 अगस्त को डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में तीन से पांच प्रतिशत की कटौती की ताकि इनकी कीमतें न बढ़ें, खुदरा मूल्य जहां के तहां रहें और कच्चे तेल के दाम में उछाल की मार से आम उपभोक्ताओं को बचाया जा सके। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कटौती से पड़ा भार स्वयं और सार्वजनिक कंपनियों ने मिलकर उठाया। तेल उद्योग का तो यह कहना था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा और उत्पाद शुल्कों में कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें उलटे एक रुपये प्रति लीटर कम हो गईं।

देश में तेल के बढ़ते मूल्यों की चुनौती का सामना करने के लिए कई प्रस्ताव किए गए हैं। संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का प्रस्ताव किया है। यह कोष खनिज तेल पर लगाए गए शुल्क से प्राप्त राशि से बनाया जा सकता है। अनुमान है कि पिछले 12 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये वार्षिक एकत्र किए गए हैं। इस पर मिले ब्याज को जोड़ने पर यह राशि 1,00,000 करोड़ यानी 10 खरब हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट या वृद्धि के अनुसार इसमें राशि जोड़ी जा सकती है या निकाली जा सकती है। इस राशि से, रसोई गैस, मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल के आयात शुल्क या उत्पादन शुल्कों में कमी की भरपाई भी की जा सकती है। इससे मिट्टी के तेल और रसोई गैस पर सब्सिडी भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्यानुसार शुल्क लगाने की बजाय एक निश्चित या विशिष्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। क्योंकि मूल्यानुसार ड्यूटी प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि आंतरिक अर्थव्यवस्था के लिए कहीं अधिक भारी प्रमाणित होती है। संसदीय समिति ने उपभोक्ताओं के हितों के रक्षा के लिए एक पेट्रोलियम नियामक बोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया है। कुछ वामपंथी नेताओं ने पेट्रोल और डीजल मूल्य बढ़ाने की बजाय शुल्कों में परिवर्तन करने की मांग की है उन्होंने आग्रह किया है कि सब्सिडी वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तथा इनके आयात शुल्कों में कम से कम पांच प्रतिशत कटौती कर दी जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के एशिया प्रशांत निदेशक डेविड बर्टन का विचार है कि इस तरह के मूल्य–अंकुशों और सरकारी सब्सिडी से वित्तीय लागत और देनदारियां बढ़ जाती हैं। विश्व बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में असामान्य वृद्धि के कारण इसकी कीमत भारत में भी बढ़ाना जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तेल कंपनियां घाटे में चली जाएंगी। वित्तीय स्थिति खराब होने पर कंपनियों के कारोबार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इससे राजस्व भी कम होगा। अगर आयात और उत्पाद शुल्कों में कटौती करनी ही है तो उसके साथ–साथ यह भी जरूरी है कि तेल को ज़ाया न होने दिया जाए, ऊर्जा का अधिक कुशल उपयोग किया जाए, परिवहन के नए साधन तथा नए तौर–तरीके और ईंधन के नए विकल्प खोजे जाएं, नई टेक्नोलाजी में निवेश किया जाए, ऊर्जा के ऐसे वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग किया जाए जिनमें प्राकृतिक गैस, पानी और गैर पारंपरिक संसाधन शामिल हों। इस मामले में दिल्ली के उदाहरण से प्रेरणा ली जा सकती है जहां सारे सार्वजनिक बस बेड़े को प्राकृतिक गैस से चलाकर न सिर्फ प्रदूषण से बचा गया, बल्कि तेल के उपयोग से भी मुक्ति पा ली गई। यहां यह भी आवश्यक है कि गैस–मूल्यों के कच्चे तेल के मूल्यों से किसी भी तरह के संबंध को धीरे–धीरे अलविदा कह दिया जाए।

इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ओपेक ही बाजार में आपूर्ति करने वाला एकमात्र संगठन नहीं है। वह कुल विश्व उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत ही उत्पादित करता है। गैर–ओपेक देशों का भी निर्यात बाजार में दखल है और मूल्यों पर वे भी निर्णायक प्रभाव डालते हैं। गैर–ओपेक देश रूस तेल के मुख्य निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आया है। ओपेक इसके संभावित परिणाम को भलीभांति जानता है। लेकिन वह अपने उत्पादन में परिस्थिति के अनुसार कटौती या बढ़त कर तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को अपने पसंदीदा दायरे में रखने की फिराक में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि इस वर्ष तेल की विश्वव्यापी मांग हद से हद लगभग 10 लाख बैरल प्रति दिन बढ़ेगी। उधर गैर–ओपेक देशों का निर्यात के लिए उत्पादन 14 लाख बैरल प्रति दिन बढ़ने की संभावना है। इसमें रूस और कजाकिस्तान का प्रतिदिन लगभग 6 लाख बैरल और अफ्रीकी देशों का 4 लाख बैरल का उत्पादन शामिल है। परिणाम यह होगा कि ओपेक के कच्चे तेल की मांग कम हो जाएगी। गैर–ओपेक देशों के निर्यात में प्रत्येक वृद्धि पर ओपेक के उत्पादन में कटौती जरूरी हो जाएगी, ताकि मूल्यों में और कमी न हो जाए। तेल मूल्य में कल्पनातीत वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जैसे– सौर, पवन, लहर, भू–ताप और हरित ऊर्जा स्रोतों से काम लेने की आवश्यकता और संभावना बहुत बढ़ गई है। ब्राजील में फसल पर कीटनाशी पाउडर छिड़कने वाले विमान इपानेमा का ईंधन, पारंपरिक ईंधन में ऐथेनोल को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह प्रदूषण रहित होने के साथ–साथ किसी भी अन्य बढ़िया ईंधन की तरह उपयोगी होता है। अब तो इसका प्रयोग

मोटर कारों में निरंतर अधिक होता जा रहा है। सबसे रोचक बात यह है कि ऐथेनोल, गन्ने, चुकंदर, मकई, जौ, आलू, सूरजमुखी या गंध सफेदा से तैयार किया जाता है। इनकी फसलों को उगाने के लिए काफी इलाका चाहिए और इसकी भारत में कमी नहीं है बल्कि इनमें से बहुत–सी फसलें तो अब भी उगाई जाती हैं। गन्ना ऊर्जावान कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन का सर्वाधिक बढ़िया संसाधन है। संभवतः ब्राजील में ऐथेनोल बनाने में यह सर्वाधिक सहायक रहा है। पेट्रोल और डीजल के साथ ऐथेनोल मिलाने की टेक्नोलाजी पर भारत और ब्राजील के बीच पहले से चला आ रहा समझौता नई मिश्रित तरल ऊर्जा बनाने में काफी सहायक हो सकता है। भारत ने पेट्रोल में सीमित मात्रा में ऐथेनोल मिलाने का काम पहले से शुरू कर रखा है। आरंभ में यह काम गन्ना उगाने वाले आठ राज्यों में आरंभ किया गया है। यह मिश्रण सारे भारत में उपलब्ध होने पर उसमें ऐथेनोल का अंश दुगना कर दिया जाएगा। तब यह टेक्नोलॉजी वैकल्पिक नहीं बल्कि मुख्यधारा की टेक्नोलॉजी बन जाएगी। ब्राजील में 20 प्रतिशत मोटरगाड़ियों में इस नए मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, फिएट, फोर्ड, वाम्सवैगन और जी–एम की खरीद करते समय आप को यह छूट होती है कि आप ऐथेनोल मिश्रित ईंधन वाली गाड़ी चाहते हैं या विशुद्ध पेट्रोल से चलने वाली। अगर भारत में इस टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर अधिकाधिक मोटरगाड़ियां और अन्य वाहन ऐथेनोल और पेट्रोल के मिश्रण से चलाई जाएं तो पेट्रोल की बचत तथा विदेशी मुद्रा के संग्रहण के क्षेत्र में यह एक युग प्रवर्तक कदम होगा। वैसे भी विश्व में अगले केवल 40 वर्षों की मांग पूरी करने के लिए ही कच्चे तेल के भंडार हैं। भविष्य में होने वाली तेल की

*(शेषांश पृष्ठ 21 पर)*

# खबरों में

- भारत में सितंबर, 2004 में टेलिफोन का घनत्व बढ़कर 8.03 प्रतिशत हो गया जबकि मार्च, 2004 में यह मात्र 7 प्रतिशत था।
- सरकार ने खाद्यान्न की विकेन्द्रित वसूली के लिए प्रोत्साहन की कई नई योजनाएं बनाई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को दो अरब रुपये का कमीशन इसी प्रोत्साहन योजना की शृंखला की एक कड़ी है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रणाली को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सुदृढ़ करना है।
- केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए बचत योजना में निवेश की आयु–सीमा घटाकर 55 वर्ष कर दी है।
- घरेलू और विदेशी निवेश के लक्ष्य तय करने के लिए सरकार ने विनिवेश आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है।
- सरकार ने घरेलू विपणन कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
- भारत सन् 2005 में नौ करोड़ टन दुग्ध उत्पादन की सीमा पाटकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है।
- भारत सरकार ने सन् 2004–2005 के दौरान कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और अनाजों के अलावा, गेहूं का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 640 रुपये तय किए गए हैं।
- आर्थिक मामलों से संबद्ध केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक उपक्रमों के पुनगर्ठन के लिए एक सात–सदस्यीय बोर्ड गठित करने का फैसला किया है।
- प्रख्यात फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल को राष्ट्रीय अंखडता तथा संपूर्ण भारत के लोगों में एकता, गहरी मानवीयता और सामाजिक समस्याओं के प्रति इनकी सोच के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- भारतीय मूल के प्रवासी विश्वविख्यात व्यवसायी लक्ष्मी एन. मित्तल के स्वामित्व वाले इस्पात इंटरनेशनल का नीदरलैंड्स के एल.एन.एस. कारोबार और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय स्टील ग्रुप के साथ विलय हो जाने के बाद अब यह मित्तल स्टील कारपोरेशन में परिवर्तन हो गया है जो विश्व की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी के रूप में उभरकर अब पूरे विश्व में अपने–आप में सबसे बड़ी इस्पात कंपनी बनने जा रही है और अब न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज और यूटोनेक्स्ट ऐम्सटर्डम की सूची में स्थान पा लेगी। लक्ष्मी एन. मित्तल, मित्तल स्टील के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
- प्रेस नोट संख्या 18 में उन विदेशी कंपनियों की नई परियोजनाओं की स्वीकृति की सरकार की नीति की चर्चा है जिनका संयुक्त रूप से भारत में कारोबार है। इस बारे में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी नोट संख्या 18 में दिशा–निर्देश स्पष्ट कर दिए गए थे जिससे आम लोगों को इसकी सूचना मिल सके। इसलिए इसे प्रेस नोट संख्या 18 कहा जाता है।

**संकलनः मधु आर. शेखर**

# IAS – 2005

भावी प्रशासको

आई.ए.एस. 2005 की परीक्षा के लिए नया सत्र 4 नवम्बर 2004 से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में पुनः लोकप्रशासन एवं सामान्य अध्ययन में उच्चतम गुणवत्ता के साथ अत्यन्त परिष्कृत रूप में हम उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में।

## लोक प्रशासन द्वारा जे.पी. सिंह

- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अन्तःविषयी दृष्टिकोण के आधार पर विश्लेषण करना ताकि प्रतियोगी न केवल विषय को समग्रता में समझ सकें बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को भी समझ सकें।
- साथ ही टॉपिक के पहलुओं पर आधारित अध्यापन ताकि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में प्रतियोगी समर्थ हों।
- परम्परागत एवं सामयिक पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण विश्लेषण।
- प्रश्नोत्तर लेखन शैली पर विशेष बल।
- अद्यतन स्तरीय सम्पूर्ण नोट्स क्लास संस्कृति के भाग।
- प्रत्येक सदस्य पर व्यक्तिगत ध्यान देना तदनुसार सुधार कार्यक्रम लागू करना।

**निःशुल्क कार्यशाला के साथ**
प्रथम बैच प्रारम्भ : 4 नवम्बर
दूसरा बैच प्रारम्भ : 1 दिसम्बर 4:30 बजे

आइए... महसूस कीजिये...
अन्तर स्पष्ट एवं विशिष्ट है।

**मुख्य परीक्षा, प्रारम्भिक परीक्षा एवं फाउन्डेशन कोर्स उपलब्ध**

## सामान्य अध्ययन द्वारा जे.पी. सिंह एवं टीम

- प्रत्येक खण्ड का विशेषज्ञतापूर्ण अध्यापन तथा खण्ड विशेष के प्रत्येक प्रकार के पहलुओं को स्पष्ट करना।
- प्रश्नोत्तर लेखन पर विशेष बल।
- अद्यतन स्तरीय नोट्स।
- प्रत्येक सदस्य पर व्यक्तिगत ध्यान देना तदनुसार सुधार कार्यक्रम लागू करना।
- समय-समय पर ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों का अतिथि व्याख्यान।

**निःशुल्क कार्यशाला के साथ**
प्रथम बैच प्रारम्भ : 4 नवम्बर
दूसरा बैच प्रारम्भ : 1 दिसम्बर 12:00 बजे

**मुख्य परीक्षा, प्रारम्भिक परीक्षा एवं फाउन्डेशन कोर्स उपलब्ध**

### पत्राचार कार्यक्रम (CORRESPONDENCE COURSE)

दिल्ली न आ सकने वाले प्रतियोगियों के लिए हमने एक सम्पूर्ण व अत्यन्त उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है - लोकप्रशासन (मुख्य परिक्षा), सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा), लोकप्रशासन (प्रारम्भिक परीक्षा) एवं सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक परीक्षा) एवं सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक परीक्षा), मुख्य परीक्षा की किसी भी विषय की सामग्री 2500/- में, प्रारम्भिक परीक्षा की सामग्री 2000/- में उपलब्ध है। इन्हे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का, दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट **JAGDISH PRASAD SINGH** के नाम भेजें।

## प्रारम्भिक परीक्षा कार्यक्रम - 2005

लोक प्रशासन एवं सामान्य अध्ययन में चार महीने का गहन कक्षा कार्यक्रम 4 नवम्बर 2004 से शुरू होगा। यह कार्यक्रम ऐसे प्रतियोगियों के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जो अभी तक गम्भीर प्रयास के बाद भी प्रारम्भिक परीक्षा में सफलता प्राप्त नही कर सके हैं। (दूसरा बैच प्रारम्भ : 1 दिसम्बर, 2004)

*जहाँ चाह... ... वहाँ राह* **The will to win IAS Exam**

*हॉस्टल सुविधा उपलब्ध*

# JIGISHA IAS ACADEMY

Add.—FLAT NO. 303, IIIrd Floor A 29-30
JAINA HOUSE COMM. COMPLEX
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
**Ph. 011-55175836 Cell: 9810569158**

विवरणिका (PROSPECTUS) के लिए 50/- का बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर भेजें।

**नोट : किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पूर्व हमारे यहां 3 निःशुल्क कक्षाएं अवश्य करें।**

# .....और अब होगी देश में 'कृष्ण क्रांति'

❍ कुंवर सुनील सत्यम

*हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के बाद अब समय है 'कृष्ण क्रांति' यानी ब्लैक रिवोल्यूशन का। वर्ष 2004 इसी क्रांति का वर्ष है। यह देश में एक ऐसी क्रांति होगी जिसकी एक बार शुरुआत हो जाने के बाद देश को हमेशा जरूरत रहेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हरित क्रांति देश में आज भी जारी है। अब प्रारंभ होने वाली इस 'कृष्ण क्रांति' से देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करने की आशा है।*

कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के बाद अब समय है 'कृष्ण क्रांति' यानी ब्लैक रिवोल्यूशन का। वर्ष 2004 इसी क्रांति का वर्ष है। यह देश में एक ऐसी क्रांति होगी जिसकी एक बार शुरुआत हो जाने के बाद देश को हमेशा जरूरत रहेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हरित क्रांति देश में आज भी जारी है। अब प्रारंभ होने वाली इस 'कृष्ण क्रांति' से देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करने की आशा है।

**कृष्ण क्रांति का उद्देश्य**

कृष्ण क्रांति का उद्देश्य देश को पेट्रोल एवं डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) क्योंकि काले रंग का होता है, इसलिए इसके उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को 'कृष्ण क्रांति' की शुरुआत कहा जा रहा है।

देश में पहले इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतिशत 70 था लेकिन तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और देश के विकास पथ पर तीव्र गति से बढ़ने के कारण तेल की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आज हम अपनी आवश्यकता का लगभग 70 प्रतिशत आयात करते हैं और सिर्फ 30 प्रतिशत का ही घरेलू उत्पादन हो पाता है जिस पर प्रति वर्ष लगभग 84 हजार करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। भारत में 2000–01 में कच्चे तेल का 3.24 करोड़ टन उत्पादन हुआ जो कि हमारी आवश्यकता का लगभग एक तिहाई मात्र था। इस समय देश में प्रति वर्ष 10.2 करोड़ टन तेल की मांग है। अनुमान है कि यह बढ़कर सन् 2007 तक 14.5 करोड़ टन एवं सन् 2012 तक 17.6 करोड़ टन हो जाएगी। जिस गति से देश में पेट्रोलियम पदार्थों का उपभोग हो रहा है उस गति से भारत के सभी तेल भंडारों के आगामी लगभग 45–50 वर्षों में समाप्त हो जाने का अनुमान है। ऐसे में हमारे समक्ष अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिर्फ आयात पर निर्भर रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा, जिससे हमारी 'ऊर्जा सुरक्षा' खतरे में पड़ जाएगी जो सामरिक दृष्टि से देश के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। यह 2020 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सपने के लिए भी राह का सबसे बड़ा रोड़ा सिद्ध हो सकता है।

उक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार इस ओर गंभीर है। एक ओर जहां घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर ऊर्जा प्रतिरूप को बदलने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऊर्जा के अन्य सभी संभव विकल्पों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दिशा में 'कृष्ण क्रांति' एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होने जा रही है।

**क्रांति के घटक**– कृष्ण क्रांति के अंतर्गत देश में ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल एवं 'बायोडीजल' के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। ये दोनों ही इस क्रांति के प्रमुख घटक हैं। देश में ऐथेनोल का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। साथ ही बायोडीजल के लिए 'रतनजोत' (जटरोपा) आदि की व्यावसायिक कृषि की शुरुआत की जा रही है।

**ऐथेनोल**

वर्ष 1931 से विश्व के कई देशों, जैसे – संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्राजील आदि में ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोलियम का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में इसके प्रयोग पर गत लगभग तीन दशकों से विचार–विमर्श चल रहा था। लेकिन पिछली सरकार के कार्य काल में ही यह योजना फलीभूत हो सकी। सरकार ने अप्रैल 2001

में एक अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोत तथा खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति को जैव ईंधन (बायो फ्यूल) पर राष्ट्रीय नीति एवं इस प्रकार के ईंधन से जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन करना था। फरवरी 2003 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने संपूर्ण देश में ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल एवं डीजल के प्रयोग पर अपनी मुहर लगा दी है। अभी तक देश के 9 गन्ना राज्यों एवं इसके निकटवर्ती केंद्रशासित राज्यों, यथा – उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु तथा चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं पांडेचेरी में 1 जनवरी, 2003 से 5 प्रतिशत ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग हो रहा था। अक्टूबर, 2003 से मध्य प्रदेश तथा उत्तराचंल में भी यह कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार जल्दी ही यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। ऐथेनोल मिश्रित डीजल के मिश्रण के 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

**बायोडीजल**

उपेक्षित जंगली पौधे रतनजोत (जटरोपा) से देश में बायोडीजल (जैव डीजल) का उत्पादन किया जाएगा। यह कार्य सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा है। कई विकसित देशों में वाहनों में बायोडीजल का प्रयोग किया जा रहा है। देश में इंडियन आयल द्वारा इसका व्यावसायिक परीक्षण सफल रहा है। सरकार ने रतनजोत से बायोडीजल उत्पादन करने संबंधी 1430 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है जिसका क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय की संस्था नेशनल ऑयलसीड एवं वेजीटेबल आयल डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया जाएगा। रतनजोत के बीजों से प्राप्त होने वाले तेल को परंपरागत डीजल में मिलाकर 'बायोडीजल' तैयार होगा। वर्तमान वाहनों के इंजन में किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना ही यह बायोडीजल प्रयोग किया जा सकेगा अर्थात् इसके लिए वर्तमान इंजनों में किसी तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।

अभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश आदि राज्यों का रतनजोत की व्यावसायिक खेती के लिए चयन किया गया है। सरकार ने अभी कुल 3.3 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को इसकी खेती के लिए चिह्नित किया है। रतनजोत की एक विशेषता यह है कि यह सम शीतोष्ण जलवायु का पौधा है जिसे पानी की अत्यंत कम आवश्यकता होती है। इसके बीजों से बायोडीजल प्राप्त होता है। देश की जलवायु के अनुसार इसकी कुछ किस्मों को फसल के लिए चुना गया है। यह तीन साल बाद उत्पादन देना शुरू करता है। आरंभिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम आंका गया है, जो पांच साल बाद बढ़कर 12 टन तक हो सकता है। इसके बीज से लगभग 40 प्रतिशत के बराबर बायोडीजल की प्राप्ति होती है।

देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.), आई. आई.टी दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून ने रतनजोत की खेती के सफल फील्ड ट्रायल किए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सांइस, बंगलौर में एक पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।

इंडियन आयल इस संबंध में पहला प्रोजेक्ट लगाने वाला है। गैर खाद्य तेलों, यथा– रतनजोत से बनाए जाने वाले इस बायोडीजल का प्रयोग के तौर पर रेवाड़ी (हरियाणा) में कुछ सीमित बसों में उपयोग किया जाएगा।

बायोडीजल की खेती के लिए इंडियन आयल ने भारतीय रेलवे से भी एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत रेल लाइनों के साथ खाली पड़ी 500 हेक्टेयर भूमि पर इंडियन आयल बायोडीजल की खेती करेगा। इसमें से 80 हेक्टेयर भूमि इसे प्राप्त भी हो चुकी है जिस पर 'बायो डीजल' की खेती के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन टेंडर आमंत्रित कर चुका है। इंडियन आयल को इससे दो–तीन वर्षों में 500–800 मीट्रिक टन बायोडीजल के उत्पादन का अनुमान है।

**बायोडीजल का सफल प्रयोग**

रेलवे में बायोडीजल के प्रयोग की संभावना का अध्ययन करने के लिए रेलवे ने लखनऊ स्थित अपनी अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रयोग किए। 31 जनवरी, 2003 को पहली बार दिल्ली–अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में इसका सफलतम प्रयोग किया गया।

**कृष्ण क्रांति के समक्ष समस्याएं**

तत्कालीन सरकार ने ऐथेनोल और बायोडीजल की कृष्ण क्रांति को पूर्ण सहयोग देने का वायदा किया और वर्ष 2004 को 'बायो ट्रेड वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की। लेकिन फिर भी कृष्ण क्रांति के फलीभूत एवं विकसित होने में कई व्यावहारिक समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। देश के उत्तर–पूर्वी राज्यों सहित अनेक स्थानों पर भौगोलिक दशाएं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल नहीं है जिससे वहां पर ऐथेनोल उपलब्ध नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं गोवा में आवश्यकता से अधिक ऐथेनोल उपलब्ध है। इस प्रकार सरकार को विकेंद्रित रूप से ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल उत्पादन करने हेतु समस्या का सामना करना पड़ेगा। इससे ऐथेनोल विहीन क्षेत्रों में ऐथेनोल अथवा ऐथेनोल मिश्रित परिवहन में अनावश्यक खर्च आएगा जो उन राज्यों में ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल की लागत को अन्य राज्यों की अपेक्षा ऊंचा रखेगा। इसी प्रकार तमिलनाडु एवं पांडिचेरी जैसे राज्यों में स्थानीय सरकार द्वारा ऐथेनोल पर 30

प्रतिशत उत्पाद कर लिए जाने से वहां ऐथेनोल महंगा पड़ता है जिससे इन राज्यों, में ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल उत्पादन का कार्यक्रम लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल एवं डीजल के संदर्भ में भी ऐथेनोल का उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीक को और अधिक विकसित करना होगा।

**कृष्ण क्रांति के दूरगामी प्रभाव एवं लाभ**

इस क्रांति से देश की ऊर्जा सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था पर गहरे प्रभाव पड़ेंगे। निश्चित ही कृष्ण क्रांति की सफलता देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। इससे देश को पेट्रोल के आयात पर खर्च होने वाली बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी भारी मात्रा में बचत होगी और देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी।

ऐथेनोल चीनी मिलों से निकलने वाली गाद (शीरा) से बनाया जाता है। पहले यह बेकार चला जाता था लेकिन अब इसका सदुपयोग हो सकेगा। यातायात के लिए प्रयोग किए जाने वाले ईंधन में ऐथेनोल के मिश्रण से गन्ना उत्पादकों को भी लाभ होगा। यह पेट्रोल के प्रदूषक तत्वों को भी कम करेगा। इसी प्रकार रतनजोत जैसे पौधों से बायोडीजल प्राप्ति के भी अनेक लाभ देश को मिलेंगे। बायोडीजल हेतु रतनजोत आदि की व्यावसायिक खेती के लिए सरकार किसानों को अनुदान एवं आसान शर्तों पर ऋण देने की योजना बना रही है। बायोडीजल को ज्यादा परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रदूषण रहित होता है तथा इसमें सल्फर की मात्रा भी शून्य होती है। इसे पर्यावरण के यूरो–3 मानकों में रखा गया है। बायोडीजल ज्वलनशील भी नहीं है। अतः इसका भंडारण एवं परिवहन भी आसान है। प्रारंभ में बायोडीजल कुछ महंगा अवश्य होगा लेकिन बाद में यह ईंधन का श्रेष्ठ एवं सस्ता विकल्प ही होगा। इस ईंधन की कीमत 11–12 रुपये प्रति लीटर होगी जो परंपरागत डीजल की कीमतों से कम है। यह सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. से भी सस्ती होगी।

बायोडीजल की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर होगी तथा लोगों की आय बढ़ने से आत्मनिर्भरता भी आएगी। रेल पटरियों के पास खाली पड़ी बेकार भूमि के अलावा बंजर भूमि में भी रतनजोत जैसे बायोडीजल उत्पादक पौधों की खेती की जा सकती है। यह मरुभूमि में भी उगाया जा सकता है। इस प्रकार बंजर एवं मरुभूमि को भी अब खेती योग्य बनाया जा सकेगा।

**निष्कर्ष**

कृष्ण क्रांति निश्चित ही भारत की 'टिकाऊ विकास' के प्रति प्रतिबद्धता को दृढ़ता प्रदान करेगी। देश की वर्तमान एवं भावी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कृष्ण क्रांति का सफल होना जरूरी है। सरकार को अपने तमाम प्रयासों से इसके मार्ग में आने वाली प्रत्येक कठिनाई को दूर करना होगा। ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन को सुगम बनाने में 'पाइप लाइन परिवहन प्रणाली' सहायक सिद्ध होगी जो परिवहन लागत को भी घटाती है इसलिए हमें अपना पाइपलाइन परिवहन तंत्र भी सुदृढ़ करना होगा। यह क्रांति भारत की आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगी तथा भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ❑

**(स्वतंत्र पत्रकार)**

---

*(पृष्ठ 17 का शेषांश)*

कमी को पूरा करने के लिए अभी से गंभीरतापूर्वक कदम उठाने होंगे। देश में 18 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है। अगर मात्र एक करोड़ भूमि में ही ऐथेनोल बनाने वाली चीजों की खेती की जाए तो भी देश तेल के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकेगा। ऐसा ही कदम डीजल के मामले में उठाया जा सकता है। स्पेन में ओलिव तेल, मलेशिया में पाम–आयल और फ्रांस में रेपसीड का डीजल में मिश्रण किया जाता है। इनके बीजों की बुवाई करके एक ही झटके में डीजल की कमी बहुत हद तक दूर की जा सकती है। इस तरह कच्चे तेल और डीजल में काफी आत्मनिर्भर होने पर न केवल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि रोजगार के अवसर जुटाने में भी मदद मिलेगी। हमारे यहां ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत, अमेरिका यूरोपीय देशों, चीन और जापान की तुलना में कम है, लेकिन विशाल जनसंख्या के मद्देनजर काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। निस्संदेह शुरुआती दौर में जैव ईंधन महंगा पड़ेगा, लेकिन जैसे–जैसे उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, दाम में कमी होती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए जैव–रिफाइनरियों यानी शोध कारखानों का जाल बिछाना होगा और प्रौद्योगिकी को निरंतर उन्नत और सुदृढ़ बनाते जाना होगा। पेट्रोल का राशनिंग लागू कर, एक व्यक्ति के पास एक कार से अधिक न रखने का सिद्धांत लागू कर, कार्यालयों में मोटरगाड़ियों का बेतहाशा प्रयोग सीमित कर, तथा पुरानी गाड़ियों और पुराने इंजनों का प्रयोग बंद करके भी पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकेगा और इससे संकट से उबरने में बहुत सहायता मिलेगी। इस सारी पृष्ठभूमि में अगर हमारे चंद नेता थाइलैंड के प्रधानमंत्री के निवास से कार्यालय को मोटर की बजाय साइकिल पर जाने से प्रेरणा लेते हुए कार मुक्ति अभियान की अगुवाई करने की पहल करें तो सारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किफायत के लिए जादुई प्रभाव पड़ेगा और सुखद परिणामों से रूबरू हुआ जा सकेगा। ❑

**(स्वतंत्र पत्रकार)**

**ADMISSION OPEN**
**15th November**

# लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

*By*

# Atul Lohiya

*(A person who believes in hard work and scientific approach)*

## UGC-NET

**QUALIFIED IN TWO SUBJECTS**

**HISTORY & PUB. ADMINISTRATION**

***Course Offered:***
* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Test Series for Prelims

*पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध*
*(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)*

**MAINS - 2500/-**
**MAINS + PRE. - 3500/-**
*डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त*

***Send DD/MO in favour of Atul Lohiya***

***UPSC** के साथ **UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS** की भी तैयारी*

**NEW BATCH STARTS FROM 14th DEC. & 5th JAN., 2005**

## 'अतुल लोहिया'

**शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी**

**Cell.: 9810651005, 0532-3217608**

***Sanjay Singh***
*Regional Director (Allahabad)*
*Cell. : 9839746184*

***Shashi Bhushan***
*Director*
*Cell. : 9868378728*

**Our New Branch at Allahabad**

# "PRABHA"

## AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

**FLAT No. 105, 1st FLOOR, VIRAT BHAWAN (MTNL BUILDING), NEAR BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. Cell.: 9810651005**

**Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.**

# भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004–05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्यों की मध्यावधि समीक्षा

## ऋणों के प्रवाह में लगातार सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थिर नीति

❍ प्यारालाल राघवन

जून के महीनों में घरेलू और विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रमों को देखते हुए मौद्रिक नीति में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। 2004–05 के वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति की समीक्षा अपेक्षित थी।

विश्व अर्थव्यवस्था में उम्मीद से अधिक तेज रफ्तार से सुधार होने और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोत्तरी के साथ वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से कई औद्योगीकृत देशों के केंद्रीय बैंकों, खासतौर पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक के मौद्रिक दृष्टिकोण में बदलाव आया।

इन विश्वस्तरीय घटनाक्रमों के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ नए अप्रत्याशित रुझान भी देखे गए। दक्षिण–पश्चिमी मानसून की प्रगति में देरी और कई इलाकों में वर्षा की कमी से कृषि उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा धूमिल हो गई। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि इन घटनाओं के साथ ही थोक मूल्यों में तेज बढ़ोत्तरी हुई और मई 2004 के अंत में इसकी वार्षिक आधार पर साप्ताहिक दर 5 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2004 के अंत में 8.3 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई। समाचारों की सुर्खियों में रहने वाली मुद्रास्फीति की दर और तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी से मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई। इससे ब्याज दरों में चक्रीय वृद्धि का अनुमान लगाया जाने लगा। कई लोगों का मानना था कि केंद्रीय बैंक के सामने पिछले प्रयासों को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है जिसके तहत उसने बाजार स्थिरीकरण योजना के विस्तार से तरलता सीमा बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपये कर दी थी। इसके लिए बैंक ने सी.आर.आर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया और कई अन्य उपाय अपनाए।

लेकिन मध्यावधि समीक्षा में बैंक दर को अप्रैल 2003 में निर्धारित 6 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखकर तमाम अटकलों को विराम लगा दिया। लेकिन स्थिर रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि करके इसे 4.75 प्रतिशत कर दिया गया जबकि स्थिर रेपो रेट 6 प्रतिशत के स्तर पर बरकरार रखी गई ताकि दरों के अंतर में तालमेल बना रहे। रिजर्व बैंक के इस कदम को ब्याज दरों के बारे में रिजर्व बैंक के सूझबूझ वाले मजबूत उपाय के रूप में देखा गया। रिजर्व बैंक ने बैंक दरों में यथास्थिति बनाए रखने का जो फैसला किया है उसका प्रमुख कारण शायद यह है कि पिछले कुछ सप्ताहों में मुद्रास्फीति संबंधी रुझानों में निरंतर गिरावट का रुख रहा है।

आंकड़ों से पता चलता है कि अंकों के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक 7.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है । पिछले वर्ष के 4.9 प्रतिशत के मुकाबले औसत मुद्रास्फीति 6.2 प्रतिशत हो गई है। रिजर्व बैंक ने इस बात पर भी गौर किया है कि थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी के कारण बड़े विषम रहे हैं और यह लौह अयस्क, तिलहन, ईंधन, मूल्य धातुओं, गैर–धात्विक खनिज और गैर–विद्युत मशीनरी के दामों में वृद्धि के कारण हुई है।

इनमें से अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के प्रमुख कारणों में आपूर्ति संबंधी घटकों की भूमिका रही है और प्रभावी मौद्रिक नीति का इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वैसे बैंकों की जमा राशियों में धीमी गति से वृद्धि को रोकना इससे निपटने का एक उपाय है। वित्त वर्ष के दौरान प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा कराई गई राशियों में गिरावट से (जुलाई तक इसमें 2.3 अरब डालर की कम आ चुकी थी) रिजर्व बैंक को प्रवासी (विदेशी) रुपया खातों में जमा राशि की सीमा को बढ़ाकर अमरीकी डालर की एलआईबीओआर/एसडब्ल्यूएपी दरों के अनुसार परिपक्वता से 50 मूल बिंदुओं के बराबर कर दिया गया है। बैंकों को 15 लाख रुपये से कम की फुटकर घरेलू जमा राशियों की न्यूनतम कालावधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन करने की अनुमति दे दी गई है।

मध्यावधि समीक्षा में ऋण वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने पर अतिरिक्त जोर दिया गया है ताकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराए जा सके। ऋण वितरण प्रणाली में बाधाओं को दूर करने का एक उपाय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बैंकों के ऋणों में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के

# ऋण नीति समीक्षा

- सकल घरेलू उत्पाद आकलन 6-6.5% घट गया
- वार्षिक मुद्रास्फीति 6.5% अनुमानित
- बैंक दर 6% पर अपरिवर्तित
- रिपो रेट बढ़कर 4.75% हुई
- पूंजीगत आवश्यकता खुदरा ऋण के लिए बढ़ी

- सात दिन की अवधि जमा फिर लागू
- एनएफबीसी की सार्वजनिक जमा धीरे–धीरे समाप्त
- प्रवासी जमा पर ब्याज–दर की सीमा बढ़ी
- आर.बी.आई द्वारा बैंकों की आलोचना सार्वजनिक की जाएगी
- मकानों के लिए ऋण प्राथमिकता–सूची में होंगे।

प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को समाप्त करना भी शामिल है।

प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋणों के बारे में भी कई कदमों की घोषणा की गई जिनमें कृषि उपकरणों व यंत्रों के लिए ऋण राशि की सीमा बढ़ाना और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए निवेश का वितरण शामिल है। बैंकों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वे विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 40 प्रतिशत प्रत्यक्ष ऋण छोटे और सीमांत किसानों को दें।

विशेष कृषि ऋण योजना का विस्तार अब निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी किया जाएगा और सभी बैंक 2005–06 में कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋणों में 20–25 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा कराए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जो समस्याएं बताई गई हैं उनसे निपटने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन से इन्हें दूर करने के उपाय करने को कहा गया है।

एक अन्य प्रमुख क्षेत्र जिसकी ओर रिजर्व बैंक का ध्यान गया है वह लघु उद्योगों को ऋण देने से संबंधित है। अचल संपत्ति और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त ऋण की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। लघु क्षेत्र के लिए ऋणों के प्रतिभूतीकरण को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए लघु उद्योग क्षेत्र हेतु प्राथमिकता क्षेत्र के लिए अनिवार्य ऋण योजना के तहत प्रतिभूतीकृत आस्तियों में बैंक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंकों को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उससे आगे वित्तपोषण कर सकें।

आवास क्षेत्र के मामले में जो संकेत मिले हैं वे मिले–जुले हैं, एक ओर फुटकर आवास क्षेत्र में ऋणों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 15 लाख रुपये तक के आवास ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में शामिल किया जाएगा। लेकिन बैंक ने आवास ऋण के क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि पर कुछ अंकुश लगाने के लिए अस्थायी आवर्ती उपायों की घोषणा की है। इसके लिए जोखिम दूर करने के उपायों को अपनाया जाएगा ताकि आवास ऋणों पर जोखिम का भार 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत हो जाए। शायद इसके पीछे यह सोच काम कर रही है कि संख्या की बजाए गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया जाए। इसी तरह उपभोक्ता ऋणों पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया है और इसमें व्यक्तिगत ऋण तथा क्रेडिट कार्ड भी शामिल हैं।

ऋणों का प्रवाह बढ़ाने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म ऋणों को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा और सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने वालों का दायरा बढ़ाया जाएगा। बैंक मार्च 2007 तक 5.85 लाख स्व–सहायता समूहों के लिए ऋण सुविधा का विस्तार करेंगे।

रिजर्व बैंक द्वारा घोषित अन्य उपायों में कुछ नई पहल भी शामिल हैं जिनसे हुंडी बाजार का विकास होगा। इनमें हुंडियों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 15 दिन से घटा कर 7 दिन करना, कारोबारी सौदों के सिलसिले में हुंडी जारी करने की सूचना सौदे वाले दिन के अंत तक देना तथा हुंडियों के प्रसंस्करण, निपटान तथा प्रलेखन को युक्तिसंगत बनाने तथा इसके मानकीकरण के उपाय सुझाने के लिए विशेष दल का गठन करना शामिल है।

कुल मिलाकर मध्यावधि समीक्षा में परिवर्तन संबंधी निर्देशों की दिशा मोटे तौर पर ऋणों का प्रवाह बढ़ाने की ओर उन्मुख है जिससे औद्योगिक और निर्यात क्षेत्रों में गतिशीलता बनी रहे। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि अर्थव्यवस्था में वर्तमान अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक यह भी उम्मीद करता है कि विदेशी क्षेत्र से आपूर्ति का झटका अर्थव्यवस्था झेल जाएगी और इससे मध्यम अवधि के लिए मुद्रास्फीति की दर कम की जा सकेगी। ❑

**(लेखक भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ, नई दिल्ली में वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं।)**

# IAS/PCS 2005 (MAINS/PRELIMS)

## CSIR/ UGC-NET

We Kalp your dreams into reality.

KALP ACADEMY
AN INSTITUTE FOR EXCELLENCE

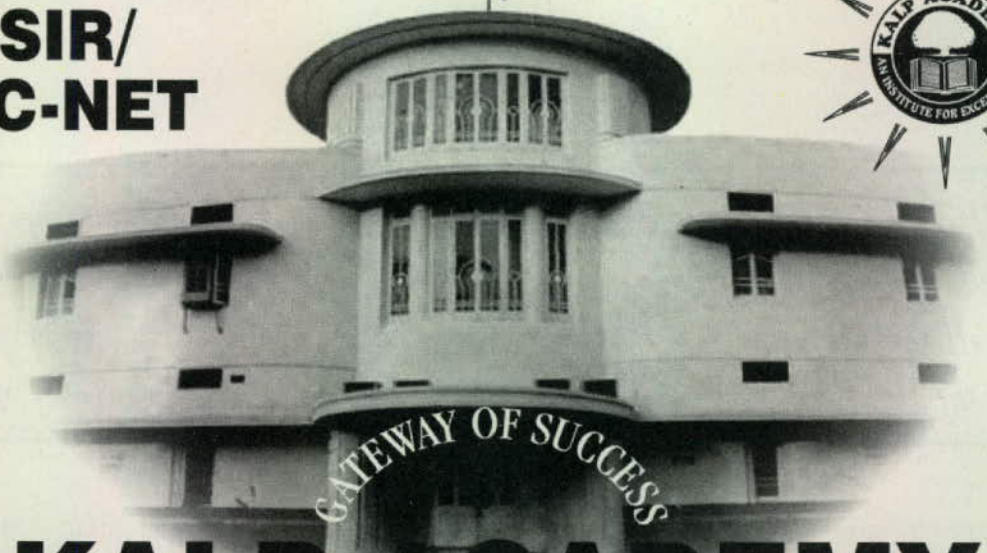


# KALP ACADEMY

## We are India's Biggest & The Best

*Rely on us... We rely only on excellence*

**कल्प हिन्दी माध्यम**

अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान
लोक प्रशासन, भूगोल
इतिहास, दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान,
समाज शास्त्र, संस्कृत, हिन्दी

Read Our Exclusive Magazines
KALP TIMES (Eng.)
कल्प टाइम्स (हिन्दी)
for IAS/PCS

**ENGLISH MEDIUM**

KALP HUMANITIES : Economics, Commerce, Political Science, Public Admn., Geography, Sociology, History, Psychology
KALP SCIENCES : Zoology, Maths, Botany, Physics, Chemistry

*Limited Seats Available - Admission Open*

**BATCHES FROM 20th DECEMBER, 2004 & 5th JANUARY, 2005**

*Separate Hostels for Girls & Boys*

POSTAL COACHING ALSO AVAILABLE

**KALP ACADEMY**
*Symbiosis of Experts for Civil Services*

A-38-40, Ansal Building, Commercial Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009.
Ph. : 27655825, 27655826. Cell.: 9810565283, 9868024975, 20054802

10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस पर विशेष

# मानवाधिकार संस्थाएं एवं संरक्षण की कार्य प्रणाली

○ अरुण कुमार दीक्षित

*मानवाधिकार कोई नई अवधारणा नहीं है। इसकी जड़ें अतीत की गहराइयों में छिपी हैं। वैदिक युग में मानवाधिकारों का अस्तित्व था। प्लेटो तथा अन्य दार्शनिकों ने अपनी कृतियों में मानवाधिकारों को स्थान दिया। ग्रीक के नगर राज्यों तथा रोमन लॉ में नागरिकों के कई अधिकारों को मान्यता दी गई थी।*

मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सम्मानपूर्वक जीवनयापन की है। इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, फिलिस्तीनी समस्या, मुंबई के हिंदू– मुस्लिम दंगे, गुजरात गोधरा, आए दिन पुलिस का उत्पीड़न आदि साक्षी हैं कि पग–पग पर आम आदमी तिरस्कृत, असुरक्षित एवं उत्पीड़ित है। मानव जाति पर जितने कहर इन दिनों ढाए जाने लगे हैं, उतने शायद पहले कभी सुनने को नहीं मिले।

मानवाधिकार कोई नई अवधारणा नहीं है। इसकी जड़ें अतीत की गहराइयों में छिपी हैं। वैदिक युग में मानवाधिकारों का अस्तित्व था। प्लेटो तथा अन्य दार्शनिकों ने अपनी कृतियों में मानवाधिकारों को स्थान दिया। ग्रीक के नगर राज्यों तथा रोमन लॉ में नागरिकों के कई अधिकारों को मान्यता दी गई थी, यथा– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार आदि।

मानवाधिकारों का संरक्षण आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। संपूर्ण मानव जाति शोषण, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद से पीड़ित है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मेग्नाकार्टा 1215, पेटीशन ऑफ राइट्स 1628, हेवियस कार्पस एक्ट 1679, बिल आफ राइट्स 1689, तथा मानव अधिकार घोषणा–पत्र जारी हुए।

**मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित संस्थाएं एवं संगठन**

संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रधान अंग–महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास धारिता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद एक या दूसरे तरीके से मानवाधिकारों से संबंधित कार्य करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा यह दायित्व निहित किया गया है कि महासभा सभी लोगों के लिए जाति, लिंग भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव बिना मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के लिए अध्ययन की व्यवस्था करेगी तथा उन पर सिफारिश (संस्तुति) करेगी। 10 दिसंबर, 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकार किए जाने के पश्चात् महासभा ने मानवाधिकार से संबंधित अनेक घोषणाएं अंगीकार की हैं। इनका संबंध जाति संहार (नर संहार), मूलवंशीय भेदभाव, रंगभेद, शरणार्थी, राष्ट्रीयता विहीन व्यक्तियों, महिलाओं के अधिकार, दासता, विवाह, बाल, किशोरावस्था, विकलांग और मंदबुद्धि व्यक्ति, विकास और सामाजिक प्रगति से है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधिक बल प्राप्त है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद मानवाधिकारों और सभी के लिए मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा उनके अनुपालन के लिए सिफारिशें कर सकती है। इस संबंध में परिषद का विशेष दायित्व है।

मानवाधिकार के संगठनों की विवेचना हम तीन स्तरों कर सकते हैं–

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 2. क्षेत्रीय स्तर पर, और 3. राष्ट्रीय स्तर पर

**अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर**

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके साथ ही यह ऐसे अन्य आयोगों का गठन करेगी जो उसके कार्यों को संपन्न करने के लिए अपेक्षित हों। इस अनुच्छेद के अनुसरण में मानवाधिकार आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक कार्यकारी आयोग के रूप में 1946 में हुई। इसके विचारणीय विषय निम्न थे –

1. अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय बिल
2. नागरिक स्वतंत्रताओं, महिलाओं की प्रास्थिति, सूचना की स्वतंत्रता और इसी तरह के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं
3. अल्पसंख्यकों का संरक्षण
4. मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव का निवारण
5. मानवाधिकार से संबंधित कोई अन्य मामला जो अन्य विषयों के अंतर्गत नहीं आता और
6. संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में मानवाधिकार में संबंधित क्रिया–कलापों के समन्वय के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायता करना।

मानवाधिकार आयोग अपने विचारणीय विषयों के अधीन अपने स्वयं सहायक निकायों की स्थापना उन प्रश्नों की छानबीन के लिए कर सकता है जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। भेदभाव रोकने तथा अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए स्थायी उप–आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी।

महिलाओं की स्थिति पर आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक कार्यकारी आयोग के रूप में हुई थी। महिलाओं के विकास से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएं, क्षेत्रीय संस्थाएं या राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य करती हैं, उनके बीच यह आयोग घनिष्ठ समन्वय करता है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान के क्रियान्वयन की देखरेख का दायित्व आर्थिक और सामाजिक परिषद में निहित है। उस दायित्व के पालन में सहायता के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1985 में आर्थिक/सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति की स्थापना की। समिति का कार्य, आर्थिक समिति और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों का अध्ययन और राज्य पक्षकारों के साथ उनकी विवेचना करना तथा सामाजिक परिषद को सामान्य प्रकृति की संस्तुति करना है।

न्यायधारिता परिषद की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग के रूप में मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण में सीमित है। इसके उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्यायिक अंग है। मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण में इसकी भूमिका यद्यपि बड़ी महत्वपूर्ण किंतु सीमित है।

सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है, परंतु यह मानवाधिकार की समस्याओं के बारे में भी विचार करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रावधान सुरक्षा परिषद को मानवाधिकार समस्याओं को निपटाने के लिए समर्थ बनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों तथा सामाजिक परिषद के अधीन स्थापित संस्थाओं के अतिरिक्त भी ऐसी अनेक संस्थाएं/संगठन हैं जो मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण से संबंधित हैं। इनमें से कुछ की विवेचना करना समीचीन होगा।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना 1947 में महासभा द्वारा की गई थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्रमशः विकास और संहिताकरण को बढ़ावा देना है। यद्यपि आयोग का प्रत्यक्ष संबंध मानव अधिकारों और संरक्षण से नहीं है किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसने मानवाधिकार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त के पद का सृजन शरणार्थियों, विस्थापितों, राष्ट्रीयता विहीन लोगों तथा स्वदेश वापसी वाले लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हुआ था।

संबंधित समिति सभी रूपों में मूलवंशीय भेदभाव के समापन के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान के कार्यान्वयन की देख–रेख के लिए मूलवंशीय भेदभाव से संबंधित समिति की स्थापना की गई है।

नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार इसके राज्य पक्षकारों ने 20 सितंबर, 1976 को "मानवाधिकार समिति" की स्थापना की।

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के समापन की समिति स्थापना 1982 में महिलाओं के विरुद्ध सभी रूपों में भेदभाव के समापन सम्मेलन के कार्यान्वयन की देख–रेख के लिए हुई थी।

बाल अधिकारों से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत बाल अधिकारों की समिति का गठन किया गया जिसके अंतर्गत बालकों के अधिकारों की रक्षा तथा बाल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयुक्त की स्थापना महासभा ने 20 दिसंबर, 1993 को की। आयुक्त को संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था के अंतर्गत के मानवाधिकार के संवर्द्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रणभूमि में मानवाधिकार के बचाव का कार्य सौंपा गया है, आयुक्त से यह अपेक्षा की गई है कि वह मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और लोक सूचना संबंधी कार्यक्रमों को समन्वित करे और मानवाधिकार के प्रति आदर की भावना को विकसित करने के लिए राज्यों से वार्तालाप करे।

संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था के साथ जुड़े हुए विशिष्टीकृत अभिकरण भी मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण के कार्य में, अपने तरीके से और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों के अंतर्गत लगे हुए हैं। इनमें से प्रमुख है – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन। इन विशिष्टीकृत अभिकरणों ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं में कार्यान्वयन के लिए अपनी योजना और प्रक्रिया विकसित कर रखी है। इन अभिकरणों का महत्व इस बात में है कि इन्होंने मानवाधिकार के संघ के प्रयत्नों को अनुपूरित किया है।

**क्षेत्रीय स्तर पर**

विएना मानव अधिकार सम्मेलन 1996 की घोषणा में यह कहा गया था कि "मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण में संगठन मुख्य भूमिका अदा करते हैं।" अतः क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकार के प्रर्वतन में सगठनों का महत्व और बढ़ गया। ये संगठन निम्न हैं–

**(i) मानवाधिकार का यूरोपीय आयोग**– मानवाधिकार के यूरोपीय प्रावधान 1950 के अंतर्गत यूरोपीय देशों की परिषद ने मानवाधिकार के यूरोपीय आयोग की स्थापना की।

**(ii) मानवाधिकार का यूरोपीय न्यायालय**– मानवाधिकार के यूरोपीय न्यायालय की स्थापना 21 जनवरी, 1959 को स्ट्रासबर्ग में हुई थी।

**(iii) मानवाधिकार का अंतर–अमेरिकी आयोग**– 1969 के अमेरिका अभिसमय के अंतर्गत मानवाधिकार के अंतर–अमेरिकी आयोग की स्थापना की गई।

**(iv) मानवाधिकार का अंतर–अमेरिका न्यायालय**– अमेरिकी प्रावधान में उल्लेखित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के क्रियान्वयन एवं संरक्षण के लिए मानवाधिकार के अंतर–न्यायालय की स्थापना की गई।

**(v) अफ्रीकी आयोग**– अफ्रीकी चार्टर 1981 के अंतर्गत मानवाधिकारों के क्रियान्वयन के लिए एक अफ्रीकी आयोग का गठन किया।

**(vi) अरब आयोग**– दिसंबर 1968 में बेरूत में मानवाधिकारों पर एक अरब रीजनल कान्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें एक स्थायी आयोग (मानवाधिकार अरब आयोग) का गठन किया गया। इस आयोग के सदस्य अरब लीग के देश बनाए गए।

**राष्ट्रीय स्तर पर**

मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्द्धन का जो आंदोलन विश्व स्तर पर चल रहा है, उसकी एक मजबूत कड़ी के रूप में राज्य स्तर पर भारत के संविधान में मूल अधिकारों और आर्थिक–सामाजिक अधिकारों (भाग 3,4 में) का समावेश किया गया था। किंतु मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं घटित होती रहीं तो चिंता का विषय बनीं। अतः मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्यों के राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिए, भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया।

**(i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**– मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों और प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन "मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण या उससे संबंधित मामलों" के लिए किया गया। प्रथम मानवाधिकार आयोग 13 अक्टूबर, 1993 को अस्तित्व में आया। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं–

1. स्वप्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शिकायतों पर दी गई याचिका की जांच करना; किसी लोक सेवक द्वारा–

(i) मानवाधिकार का उल्लंघन या उसके लिए प्रेरित करना

(ii) इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने में लापरवाही करना।

2. किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी किसी आरोप वाली कार्यवाही में ऐसे न्यायालय में अनुमोदन में हस्तेक्षप करना।

3. मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना

4. मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना, आदि।

**(ii) राज्य मानवाधिकार आयोग**– मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय v में राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य आयोग को उन सभी कार्यों के निर्वहन करने की शक्ति प्राप्त होगी जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। राज्य आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच केवल उन मामलों के संवर्द्धन में कर सकता है जो संविधान की सातवीं अनुसूची (ii) एवं (iii) में परिगणित प्रविष्टियों में से किसी से भी संबंधित होंगे।

**(iii) जिलों में मानवाधिकार न्यायालय**– अधिनियम के अध्याय vi में जिसमें धारा 30 और 31 सम्मिलित हैं, प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। देश के प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करना अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत मामले का शीघ्रतापूर्ण विचारण किया जाना अधिनियम का विशेष प्रावधान है। ये न्यायालय सरकार की लापरवाही के कारण आज भी सुषुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने रूरल लिटीगेशन एंड एनटाइटिलमेंट केंद्र (R.L.E.K.) जो देहरादून का एक गैर सरकारी संगठन है, के द्वारा दायर याचिका पर एक अंतरिम आदेश पारित किया है कि मानवाधिकार न्यायालय के गठन के बारे में शीघ्र अमल किया जाए।

### गैर सरकारी संगठन

'मानव अधिकार' ने आज के सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण गैर सरकारी संस्थाएं हैं। चाहे वे सरकारों का आह्वान कर रहे होते हैं या संयुक्त राष्ट्र तंत्र का या अपने लक्ष्यों के समर्थन में प्रसार माध्यमों या धरती से जुड़े संगठनों के माध्यम से लोकमत संगठित कर रहे होते हैं, गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार के आंदोलन में पिछले 56 वर्षों में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। ये गैर सरकारी संस्थाएं आज विद्यमान हैं, यही अपने में एक बड़ी उपलब्धि है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के जिन तीन प्रमुख गैर सरकारी संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवधिकार संबंधी प्रावधानों के उल्लेख के लिए, काम किया वे हैं– अमेरिका ज्यूइश कमेटी, दी फेडेरल (बाद में नेशनल) कौंसिल ऑफ चर्चेज़, और कमीशन टू स्टडी दी अर्गेनाइजेशन आफ पीस (शांति के संगठन के अध्ययन के लिए आयोग)। इन संगठनों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का केंद्रीय लक्ष्य हो गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के प्रारंभिक दिनों के अड़ियल रुख से हताश इंटरनेशनल लीग फार दी राइट्स (मानवाधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में परिवर्तित हो गया) ने मानवाधिकार आयोग को दरकिनार कर मानवाधिकार के उल्लंघनों पर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उसने प्रकाशित रिपोर्टों और माध्यमों के जरिए किया। इस तरह इस संघ ने सर्वसत्तात्मक शासनों, सैनिक तानाशाहों, यहां तक कि जनतंत्रात्मक समाजों को शर्मिंदा किया।

एक अति प्रभावशाली मानवाधिकार संबंधी गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन "एमनेस्टी इंटरनेशनल" है जिसकी स्थापना 1961 में लंदन में हुई थी। मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने में इसके शोध विभाग का कोई सानी नहीं है। इसे एक साथ "एक आंदोलन और एक संस्था" दोनों कहा जाता है। इसके उद्देश्यों में से है– सभी उपयुक्त उपायों से, मृत्युदंड दिए जाने, यातना तथा अन्य क्रूर, कैदी और बंदियों के प्रति अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का विरोध करना।

'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की ही भांति अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है, वह है– 'इंटरनेशनल कमीशन आफ जूरिस्ट्स'। यह संगठन 1952 में बर्लिन में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। नियाल मैकडरमैट, जो इंटरनेशनल कमीशन आफ जूरिस्ट्स के महासचिव रहे हैं, के अनुसार यह संगठन "विधि द्वारा शासन के माध्यम से मानवाधिकार संवर्द्धन हेतु लड़ने में पूरे विश्व के वकीलों की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करता है।"

मानवाधिकार पर जो विश्वसम्मेलन विएना में जून, 1992 में हुआ था उसमें 800 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों ने प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें दो तिहाई धरती से जुड़े स्तर के थे।

मानवाधिकार के क्षेत्र में जुटे कुछ और प्रमुख संगठन हैं, जिन्होंने अपना योगदान किया है। उसमें सम्मिलित है– बीनाइ, वी.रिथ, ह्यूमैन राइट्स वाच, फिजिशियंस फार ह्यूमैन राइट्स, इंटरनेशनल लीग फार दी राइट्स आफ मैन, इंटरनेशनल ला एसोसिएशन, वर्ल्ड पीस थ्रू ला सेंटर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन, फाउंडेशन फार दी एस्टैबलिशमैंट आफ क्रिमिनल कोर्ट, लाइयर्स कमेटी फार ह्यूमैन राइट्स आदि।

### राष्ट्रीय स्तर पर

मानवाधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए गैर सरकारी संगठन भारत में भी सराहनीय काम कर रहे हैं और उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में भी स्वीकार किया है। तभी अधिनियम की धारा 12(1) में "मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और

संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का कार्य" मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है। मानवाधिकार आयोग इसे स्वीकार भी करता है "कि उसे व्यावहारिक सहायता तथा ऐसी रचनात्मक आलोचना के माध्यम से ऐसा काफी कुछ हासिल करना है जो गैर सरकारी संस्थाओं और आयोग के पारस्परिक संबंधों एवं अंतःसंबंधों से आगे बढ़ाया जा सकता है।"

इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों की सूची बड़ी लंबी है। मानवाधिकार आयोग की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट 1994–95 के अनुसार ऐसी 200 संस्थाएं हैं जो मानवाधिकारों में अपनी विशेषज्ञता रखती हैं। उनके विवरण आयोग की कंप्यूटर सूची में अंकित कर दिए गए हैं। ऐसे संगठनों में प्रमुख हैं– पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, पीपुल्स फार डेमोक्रेटिक राइट्स, कामन कॉज, तमिलनाडु विधि सहायता एवं परामर्श बोर्ड, आल असम स्टूडेंट यूनियन, दी राइट्स इन प्रिजन कमेटी आफ इंटरनेशनल पी. ई .एन., सिविल लिबर्टीज कमेटी (आंध्र प्रदेश), रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटिलमेंट केंद्र (देहरादून), इंडियन काउंसिल फार एनवायरनमेंटल लीगल एक्शन, वेल्लोर सिटिजंस वेलफेयर फोरम, सहेली, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेंस फोरम, लीगल एड सर्विसेज (वेस्ट बंगाल), चिल्ड्रेन्स एड सोसाइटी, एस. सी. लीगल एड कमेटी, महिला अत्याचार विरोधी जन आंदोलन।

**उच्चतम न्यायालय**

उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार के संरक्षण के विकास में लोकहित वादों के माध्यम से एक सुनहरा अध्याय जोड़ा। सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोकहित वादकारियों की सक्रिय सहायता से भारत में, न्यायपालिका नव प्रवर्तक उपचारिक उपयोग का प्रयोग कर रही है ताकि सरकार को उसके लोक कल्याण की प्रतिबद्धता के लिए बाध्य करके पीड़ित लोगों को संतोष प्रदान कर लोगों के मानवाधिकार का संरक्षण और संवर्द्धन कर सके। अनु–32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण अधिकार रिट जारी करने का है। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार मानवाधिकारों के ही पर्याय हैं। दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों के आयाम को और अधिक बढ़ा दिया है, जैसे, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार : एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अवैध गिरफ्तार तथा निरोध व अभिरक्षा मृत्यु के विरुद्ध सुरक्षा आदि। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। ❑

**(लेखक 'मानवाधिकार एवं कर्तव्य' विषय पर शोध कर रहे हैं)**


An Innovative Study Centre

**ARTH**
**EDUCATIONAL CIRCLE**

*Batches starting from 5th Jan.*

**FOR IAS/PCS and NET/JRF**

The ultimate destination for preparation of Civil Services and NET.

- ★ Guidance by experienced teachers.
- ★ Lucid Notes and writeups.
- ★ Regular tests.
- ★ Flexi module option available for G.S. and 1st Paper of JRF/NET.

**Subjects Offered:**

G.S., History, Public Administration, Sociology, Economics, Geography, Social Work and Home Science (only for NET).

**FOR MORE DETAILS CONTACT: The Co-ordinator, ARTH EDUCATIONAL CIRCLE,**
M-1/87, Sector-B, Aliganj, Lucknow-226024. Phone- 0522-2323606, 9838638535.

# IAS/PCS

INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE STUDIES
प्रशासनिक अध्ययन संस्थान
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।।

## लोक प्रशासन
by
## अशोक कु० दुबे

## इतिहास
एक नवीन रूप में .....
दिल्ली विश्वविद्यालय के गणमान्य प्राध्यापकों द्वारा

*Introducing .....*
## समाजशास्त्र
by
Renowned Faculty

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम
**NCTP**
(National Corr. Training Programme)

## G.S.
**Ashok Kr. Dubey** & Team
***Modular :-***
Sc. & Tech. + Gen. Science by
**R. Mrityunjay**

HOSTEL FACILITY
SC/ST/OBC/HC/WOMAN के लिए शुल्क में विशेष रियायत

Registration Open

## भारतीय अर्थव्यवस्था
by
**K. Bashar**

संस्थान का बढ़ता कद

**PRELIM BATCH 10 Dec. 2004**

# प्रशासनिक अध्ययन संस्थान
# Institute of Administrative Studies

**102/B-14, Ist Floor, Commercial. Complex, Near HDFC ATM, Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph. 27651002, 9312399055, 9811291166**

# पर्यावरण मित्र बांस की आर्थिक संभावनाएं

○ देवेंद्र सिंह

***बांस विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा व सबसे लंबी घास है। अपने कद, दृढ़ता एवं मजबूती के कारण यह सभी प्रकार की घासों से अधिक उन्नत व उपयोगी है। बांस का उपयोग सदियों से मनुष्य अपने जीवन में करता आ रहा है।***

बांस विशाल 'तृण–परिवार' का महत्वपूर्ण सदस्य है। बांस वस्तुतः एक तरह की घास है। इसी तृण–वर्ग में गन्ना, दूब (गांवों में पाई जाने वाली हरी घास), गेहूं, जौ आदि पौधे भी आते हैं। यदि वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह *ग्रेमिनी* (Gramineae) या *पोयसी* (Poaceae) कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम *बंबूसा अरुंडनेसिया* (Bambusa Arundinacea) है। इसका सीधा तना *कलम* (Culm) कहलाता है। तने में समान दूरी पर ठोस गांठें (Node) पाई जाती हैं। दो गांठों के बीच का भाग (Inter Node) खोखला होता है। रोचक तथ्य यह है कि बांस विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा व सबसे लंबी घास है। अपने कद, दृढ़ता एवं मजबूती के कारण यह सभी प्रकार की घासों से अधिक उन्नत व उपयोगी है। बांस का उपयोग सदियों से मनुष्य अपने जीवन में करता आ रहा है। छुटपन में बांस और कागज के आधार पर बनने वाले खिलौने के रूप में, यौवन में बासुरी, पतंग व आइसक्रीम के रूप में, धार्मिक कार्यों में अगरबत्ती के रूप में, बुढ़ापे के सहारे के रूप में तथा मरने के बाद भी श्मशान तक अरथी के रूप में इसका मनुष्य से गहरा रिश्ता है। यह जहां वंचित वर्ग के लिए आश्रय (आवास के रूप में) देने का काम करता है, वहीं प्रभु वर्ग के लिए उपभोक्तावादी और सजावटी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

भारत में बांस सामान्यतः सर्वत्र उपलब्ध होने वाला पौधा है। ध्यातव्य है कि हमारे देश में लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के वन दिखाई देते हैं, जिनमें से लगभग 28 प्रतिशत क्षेत्र पूर्वोत्तर में मौजूद है। साथ ही हमारे यहां बांस में पर्याप्त विविधता भी पाई जाती है। देश में बांस की 25 से अधिक जातियां व लगभग 136 उपजातियां पाई जाती हैं जिसमें से 58 केवल पूर्वोत्तर में हैं। इन्हें स्थानीय भाषाओं में नलबांस, देवबांस, रिंगल, नरी, गोबिया, लतंग, खांग, करैल इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। बांस उत्पादन के मामले में पूर्वोत्तर प्रमुख है; इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक का स्थान आता है। यह हमारे यहां जंगलों में बहुलता से उगता है और प्रायः विभिन्न तरह के कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह गांवों में लकड़ी और लोहे के विकल्प को बखूबी पूरा करता है। आज मनुष्य लकड़ी को अपनी आवश्यकता एवं उपभोग की पहली पसंद बनाकर जंगलों एवं वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस पर्यावरण संतुलन में अपनी महती भूमिका निभा सकता है। अभी तक लकड़ी के विकल्प के न होने का रोना रोया जा रहा था, लेकिन वस्तुतः यह विकल्प की अनदेखी करना है। आज हमारे पास बांस की बहुलता है। आवश्यकता है लकड़ी के विकल्प के रूप में इसके उपयोग के संबंध में लोगों को जानकारी देने तथा दृढ़

इच्छाशक्ति के साथ मानव को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने की।

पारंपरिक रूप से वन्य–जीवन के अभिन्न अंग के रूप में बांस अब हरे सोने में बदल चुका है। इसकी असीम आर्थिक संभावनाओं की गूंज संपूर्ण विश्व में सुनाई पड़ रही है, तभी तो सातवीं विश्व बांस कांग्रेस का आयोजन अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च, 2004 तक दिल्ली में किया गया। बांस का विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः बांस के व्यापार में भारत को प्रमुखता से स्थापित करने, व्यापार की संभावनाओं के दोहन करने और भारत को एक गंतव्य देश के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सरकार ने कांग्रेस की मेजबानी की। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में बांस के आंतरिक और बाहरी उपभोग का संयुक्त मूल्य लगभग 10 अरब डालर तक पहुंच जाने की संभावना है। बांस के क्षेत्र में दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों की अहम भूमिका है। वर्तमान में चीन का बांस उद्योग 25 हजार करोड़ से अधिक है। योजना आयोग के अनुसार भारत का बांस उद्योग लगभग 2043 हजार करोड़ रुपये का है, लेकिन बाजार की संभावना इससे दुगुनी अर्थात 4463 करोड़ रुपये की है। इस क्षेत्र की वृद्धि दर 15 से 20 प्रतिशत की है। इसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 10 वर्षों में अर्थात 2015 तक यह उद्योग 26 हजार करोड़ रुपये का हो जायेगा, जो चीन के बराबर है। योजनाकारों ने ऐसे संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है, जहां बांस का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है:

शूट (105 करोड़), बोर्ड (1000 करोड़), फ्लोरिंग बोर्ड (200 करोड़), कागज–उद्योग (900 करोड़), भवन–निर्माण (550 करोड़), फर्नीचर (380 करोड़), सड़क निर्माण (274 करोड़), अगरबत्ती, माचिस, आइसक्रीम आदि (200 करोड़)।

संप्रति बांस की मांग 26.67 मिलियन टन की है, जबकि आपूर्ति मात्र 13.47 मिलियन टन ही है। इस आपूर्ति का भी अधिकांश भाग अनावश्यक कार्यों में खप जाता है, जबकि इसके उपयोग के उचित प्रबंधन से इससे कहीं अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। प्रबंधन के अभाव में प्रतिहेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इसलिए आवश्यकता है एक सुनिश्चित नीति अपनाकर उस पर अमल करने की, जिससे बांस के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। बांस के क्षेत्र में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही योजना आयोग ने एक कार्यनीति बनाई है, जिसके अनुसार *नेशनल मिशन आन बैम्बू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड डेवलपमेंट* की स्थापना अप्रैल, 2003 में की गई। इसका प्रमुख कार्य बांस विकास के क्षेत्र में आई रुकावटों को दूर करना है।

**बांस पर आधारित उद्योग**

भूकंप प्रभावित देश जापान के जन–जीवन में बांस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उपयोग वहां भवन–निर्माण से लेकर खान–पान व कुटीर उद्योग में बहुतायत से किया जाता है। इसी को दृष्टि में रखकर भारत में भी इसके विभिन्न प्रकार के उपभोग की संभावना बढ़ी है, यद्यपि वैदिक काल से ही भारत में दवा और इमारती कार्य में इसका उपयोग किया जा रहा है। खाद्य–पदार्थ के रूप में, लघु एवं कुटीर उद्योग, पैकिंग उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका उपयोग हो रहा है।

**दवा के रूप में**

एक अनुमान के अनुसार *रामायण* में संजीवनी के रूप में जिस जड़ी का उल्लेख है, वह बांस से ही प्राप्त हुई थी। वैदिक काल से इसका उपयोग दमा, खांसी व हड्डी जोड़ने के सहायक के रूप में किया जाता रहा है। *चरक* और *सुश्रुति* ने भी बांस को विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में प्रयुक्त किए जाने का उल्लेख किया है। चाइनीज एक्यूपंचर में भी बांस का प्रयोग होता रहा है। बांस के स्राव को कड़ा करके दमा व खांसी का इलाज किया जाता है। इसका एक कामोत्तेजक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसी से वंशलोचन नामक एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि भी प्राप्त होती है। संभवतः इसीलिए भारतीय परंपरा में निःसंतान दंपति बांसेश्वर भगवान की पूजा बांस के प्रतीक के रूप में करते हैं। चीन में काले बांस की जड़ से गुर्दे की बीमारी का इलाज किया जाता है। बांस की जड़ व पत्तों से कैंसर व अन्य रोगों का उपचार किया जाता है। इसके रस से बुखार दूर किया जाता है और राख से घमौरियों का उपचार होता है। गांवों में पशु चिकित्सा में बांस की पत्ती का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। मादा पशुओं को प्रसव के समय बांस की पत्तियां खिलाई जाती हैं। वर्तमान में इसके अन्य विविध बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त होने के संबंध में अनुसंधान चल रहा है।

**खाद्य पदार्थ के रूप में**

बांस का प्रयोग पेय एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रमुखता के साथ किया जाता है। आज बांस का जूस अपने आयुर्वेदिक गुणों के कारण लोकप्रिय है। बांस के पत्तों से निर्मित यह गहरे भूरे रंग का द्रव्य है, जिसे निकालने व साफ करने में उच्च श्रेणी की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस जूस में फेनोल एसिड, फ्लैवोनौयडस, इन्नर इस्टर्स, एंथ्राक्वीनोन्स, पॉलीसक्कारइड्, अमीनोएसिड, पेप्टा–साइड्स, मैंगनीज़, जिंक और सेलेनियम जैसे सक्रिय यौगिक पाये जाते हैं। डिब्बे में आकर्षक पैकिंग में ये जूस चीन, हांगकांग और जापान के रेस्टोरेंट में प्रचुरता से मिलते हैं। इसी तरह बांस के पत्ते को बीयर बनाते समय उसमें मिलाने से बांस का बीयर तैयार होता है। ध्यातव्य है कि बांस की पत्तियां बहुत गरम होती हैं। अधिक समय तक इसके सेवन से

खून में लिपिड की मात्रा घटती है, हृदय मजबूत होता है और इंसान की उम्र बढ़ती है।

बांस की जड़ में भूमिगत कंद (राइजोम) चारों ओर फैला रहता है। इन कंदों से ही बांस का नया तना निकलता है, जिसे बांस का शूट कहा जाता है। इसे सतह पर दिखते ही काट लिया जाता है। इसे ताजा या प्रोसेस करके खाया जाता है। सूखे हुए व ताजे शूट वैसे ही स्वाद लेकर खाए जाते हैं, जबकि इसको लंबे समय तक उपयोग में लाने हेतु स्वादिष्ट अचार भी बनाया जाता है। ताजे बांस का शूट कुरकुरा व मीठा होता है। इस शूट में प्याज के बराबर पौष्टिक तत्व उपलब्ध रहता है। इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुरता में होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बांस के शूट कैंसर रोकने में भी प्रभावी होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह दक्षिण–एशियाई देशों में पर्याप्त लोकप्रिय है। इसमें विटामिन, सेल्युलोज, अमीनो अम्ल, और अन्य तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके उपभोग से भूख बढ़ती है, रक्तचाप व कोलेस्ट्राल घटाने में भी सहायता मिलती है। बांस के शूट में 90 प्रतिशत पानी होता है और इसकी अच्छी पैदावार के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। बांस का शूट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। वर्षा ऋतु में जब अन्य फसलों की पैदावार नहीं होती, तब यह ग्रामीणों के अतिरिक्त रोजगार का विकल्प बनकर उनकी आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत में उपलब्ध बांसों की अधिकतर किस्मों के शूट खाने योग्य होते हैं। यद्यपि बड़े शूट का 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा ही खाने योग्य होता है और छोटे शूट में यह मात्रा और घट जाती है। शूट का आकार व कड़वाहट विभिन्न किस्मों में अलग–अलग होते हैं। शूट के उत्पादन के आधार पर बांस की किस्मों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक क्लंपिंग और दूसरा रनिंग। क्लंपिंग किस्म के बांसों के शूट की पैदावार मई के बाद, जबकि रनिंग किस्म की पैदावार वसंत ऋतु में होती है। शूट उत्पादित करने वाली बांस की किस्में भारत के सभी राज्यों में पाई जाती हैं। अतः इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए शूट प्रोसेसिंग यूनिट सभी स्थानों पर आसानी से स्थापित हो सकती हैं। इस रूप में बांस का शूट कच्चे बांस की तुलना में अधिक आमदनी का साधन हो सकता है। देश के पूर्वोत्तर भाग में रहने वाली जन–जातियां बांस के शूट व बीजों को नियमित रूप से खाती हैं और वहां के बाजारों में इनकी पर्याप्त मांग भी रहती है।

**भवन निर्माण में**

भवन निर्माण में बांस बहुत लोकप्रिय है। गांव में यह लोहे/इस्पात का महत्वपूर्ण विकल्प है। अपने लचीलेपन और मनचाहे आकार में काटने की सुगमता के कारण इसका उपयोग टट्टर, छप्पर व खपरैल के घरों में प्रचुरता के साथ किया जाता है। जापान में लोग बांस से ही संपूर्ण मकान बना लेते हैं, जो वहां के नित्य प्रति के भूकंपों के झटकों के खतरे से बचे रहने में सहायक होते हैं। ऊंची इमारतों को बनाने में बांस का ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि स्टील के ढांचे की तुलना में यह कम टिकाऊ होता है, लेकिन स्टील के मुकाबले इसमें लागत केवल छह प्रतिशत आती है साथ ही इसे लगाने व हटाने में सुगमता है। बांस के ढांचे को और टिकाऊ तथा उपयोगी बनाने के लिए इसे तकनीकी रूप से अधिक विकसित किया जाना चाहिए। संप्रति 13.47 मिलियन टन बांस की खपत की तुलना में 3.4 मिलियन टन का उपयोग ही मकान बनाने में होता है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सहित अनेक भागों में बांस के लट्ठे का उपयोग नदियों पर पुल बनाने में भी किया जाता है। सदियों से बांस का इस्तेमाल घरों के खिड़की–दरवाजे बनाने के लिए भी हो रहा है। पर्यावरण मित्र घर के रूप में बांस का विकल्प प्लास्टिक, स्टील और सीमेंट के स्थान पर महत्वपूर्ण है। मजबूत इमारती सामान होने के कारण भवन–निर्माण के कई पहलुओं में बांस का उपयोग हो सकता है, जैसे छतों को सहारा देने वाला ढांचा, छत तैयार करने के लिए बांस की नालीदार चादर, बांस की जाली, बांस के बोर्ड (जिसका उपयोग पार्टीशन व पैनल बनाने में किया जाता है), खिड़की–दरवाजों की चौखट एवं शटर, फ्लोरिंग टाइल्स, प्रारंभिक ढांचा, पुल व सीढ़ियां इत्यादि।

**लघु एवं कुटीर उद्योग**

उद्योगों में बांस का महत्वपूर्ण उपयोग कागज–उद्योग में किया जा रहा है। बांस की बनी लुगदी कागज–उद्योग को नया आधार प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त अन्य लघु व घरेलू उद्योग में इसका बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। बांस को चीरकर छोटी–छोटी तीलियां बनाकर उसका उपयोग अगरबत्ती, पेंसिल, माचिस, टूथ–पिक, चॉपस्टिक्स आदि में किया जा सकता है। अगरबत्ती उद्योग का तो बांस महत्वपूर्ण आधार है। इसका केंद्र कर्नाटक है। इस उद्योग का बाजार 1800 करोड़ रुपये का है, जिसकी प्रतिवर्ष वृद्धि–दर 20 प्रतिशत है। अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिवर्ष एक मिलियन टन होता है। एक किलो अगरबत्ती के निर्माण में बांस का उपयोग 7 से 8 प्रतिशत होता है और पूरे अगरबत्ती उद्योग में बांस का योगदान लगभग 135 करोड़ रुपये का है।

लगभग एक मिलियन टन बांस का प्रयोग आइसक्रीम, पतंग, पटाखे, लाठी–डंडे, मछली पकड़ने वाले उपकरण, टोपियां, टोकरियां, चटाइयां, कुर्सियां, पंखे, बांसुरी, खिलौने इत्यादि में किया जाता है। संप्रति इसमें बांस की खपत 40 करोड़

है, जबकि अच्छे तकनीक का उपयोग कर इसका बाजार 186 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पेंसिल उद्योग इस समय 800 करोड़ रुपये का है। इसमें पांच बड़ी कंपनियां लगी हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेंसिल का बाजार के 80 प्रतिशत भाग पर कब्जा है। सरकार के प्रोत्साहन व उच्च तकनीक का उपयोग कर बड़ी आसानी से लकड़ी की जगह बांस का प्रयोग किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के समय तक माचिस–उद्योग पर विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन व *खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन* (KVIC) के सहयोग से माचिस–उद्योग के क्षेत्र में कई कुटीर उद्योग की इकाइयां स्थापित हुईं। इस समय देश का 70 प्रतिशत उत्पादन कुटीर–उद्योग के सहारे है, जिसकी आर्थिक सहभागिता 80 करोड़ रुपये की है। माचिस की तीलियां लकड़ी की बनती हैं, लेकिन इसके लिए बांस महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। आई.पी. आई.आर.टी.आई. (IPIRTI) ने बांस के परखच्चे से तीली बनाने की तकनीक विकसित की है, जो सभी आवश्यक मानकों पर खरी उतरी है।

पैकेजिंग–उद्योग में बांस को अभी भी दोयम दर्जे का माना जाता है। इसके दो कारण हैं: पहला, यह लकड़ी के मुकाबले महंगा होता है और दूसरा, कील ठोंकते ही फट जाता है, फिर भी उत्कृष्ट तकनीक का उपयोग कर इसका पैकेजिंग–उद्योग में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस आकर्षक हस्तशिल्प उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है।

**पर्यावरण और बांस**

बांस एक पर्यावरण हितैषी पौधा है। यह बहुत ही परिवर्तनशील है। इसे विकसित होने में बहुत कम समय लगता है। इसे 3 से 5 साल का होने पर काट सकते हैं, जबकि अन्य पेड़ 25 से 50 साल का होने पर ही उपयोगी हो पाते हैं। यह धरती के सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसकी कुछ प्रजातियां एक दिन में 8 सेमी. से 40 सेमी. तक बढ़ती देखी गई हैं। बढ़वार का विश्व रिकार्ड एक जापानी किस्म के बांस ने बनाया है, जिसने मात्र 24 घंटे में लगभग सवा मीटर की बढ़वार दिखाई। तीव्र वृद्धि के कारण लकड़ी की तुलना में इसका उत्पादन 25 गुना अधिक होता हैं। बांस की कटाई और तीन महीने के अंदर पुनः तैयार होने से पर्यावरण पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बांस के बागानों में लगाई गई लागत तीन से पांच साल में निकल आती है, जबकि अन्य वृक्षों में यह अवधि लगभग 15 साल है। बांस की कटाई उसके तने के जड़ से होती है। जड़ से पुनः नया शूट निकलने से उसका थोड़े दिन बाद ही व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बांस के पौधे मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का संरक्षण करते हैं, क्योंकि इसके आपस में जुड़े हुए भूमिगत कंद भूमि की ऊपरी सतह को अपनी जगह पर मजबूती से संजोए रहते हैं। बांस की लगातार गिरती पत्तियां वन भूमि पर चादर–सी फैली रहती हैं, इसलिए नमी का संरक्षण भी रहता है। साथ ही तेज वर्षा के समय ये पत्तियां ढाल बनकर भूमि की उपजाऊ ऊपरी परत का संरक्षण करती हैं। बांस के पौधों में हवा में उपलब्ध कार्बन डाई आक्साइड को सोखने की अच्छी क्षमता है। इसके झुरमुट प्रकाश की तीव्रता को कम करते हैं और खतरनाक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बांस के पौधे अन्य वृक्षों के मुकाबले हवा में अधिक आक्सीजन छोड़ते हैं। बांस के पौधों में बंजर भूमि को सुधारने की अच्छी क्षमता पाई गई है। बांस के वनों को प्रकृति विज्ञानी कुदरत की प्राकृतिक सफाई प्रणाली का अंग मानते हैं, क्योंकि यह प्रदूषण को पौध–पोषकों में बदल देता है, जिससे मूल्यवान फसलें पनपती हैं। बांस ऊर्जा उत्पादन में भी अपना योगदान करता है। बांस से कागज बनाने से हरे–भरे पेड़–पौधों के विनाश पर रोक लगती है। इस प्रकार हम अनुभव कर सकते हैं कि बांस किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

इतना महत्वपूर्ण व उपयोगी पौधा होने के बावजूद बांस के साथ एक समस्या भी जुड़ी हुई है। यह समस्या बांस के सामूहिक पुष्पन के संबंध में है। आमतौर पर फूल और फल लोगों को खुशहाली, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, लेकिन बांस पुष्पन, अकाल, दुख और गरीबी का पर्याय समझा जाता है। यद्यपि बांस फूलों के मामले में बहुत कंजूस हैं। इसमें 15–20 साल के अंतराल के बाद ही फूल लगते हैं। कुछ जातियां ऐसी भी हैं, जिनमें 120 वर्ष बाद फूल खिलते हैं। लेकिन रोचक तथ्य यह है कि जब बांस के झुरमुट में फूल खिलना आरंभ होता है, तो यह उम्र के किसी भेद–भाव के बिना पूरे झुरमुट में एक साथ खिलता है। इसे ही सामूहिक पुष्पन कहा जाता है। बांस में जीवन में एक बार ही फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद झुरमुट के सभी वृक्ष एक साथ काल–कवलित भी हो जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है सामूहिक विनाश का चरण। दरअसल सामूहिक पुष्पन के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में बांस के बीज बिखर जाते हैं। बांस के फूल देखने में जई की बाली जैसे होते हैं, जिसमें धान जैसे छोटे–छोटे बीज पाए जाते हैं। चटखने के बाद ये धान के लावे जैसे हो जाते हैं। बांस के ये बीज चूहों का प्रिय आहार है। इसके खाने से उनकी प्रजनन क्षमता में तीव्र वृद्धि होती है। फलतः चूहों की संख्या तेजी से बढ़ती है। जब बांस का बीज खत्म हो जाता है, तो ये चूहे सीधे किसानों के खेत–खलिहानों पर हल्ला बोल देते

हैं। देखते–देखते चूहे सारी फसल और खलिहान नष्ट कर देते हैं। और इसके बाद अकाल, भूख और महामारी का दौर शुरू होता है।

बांस के सामूहिक पुष्पन से अभी तक बीसवीं शताब्दी के दो बड़े अकाल पड़ चुके हैं। पहला अकाल 1910–13 के बीच बांस में आए सामूहिक पुष्पन के बाद पड़ा था। दूसरा अकाल 1959 में मिजोरम, त्रिपुरा और असम की बरक घाटी में बांस के सामूहिक पुष्पन के बाद देखा गया था। यह अकाल इतना भयंकर था कि इसने पूर्वोत्तर को विद्रोही बना दिया। मिजो–विद्रोह बांस के इसी सामूहिक पुष्पन के उपरांत बड़े अकाल का परिणाम माना जाता है। अब इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में ही वर्ष 2003–04 से मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि राज्यों में बांस में फूल खिलने लगे हैं, जिससे सरकार से लेकर आम जनता तक चिंतित हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान पुष्पन पूर्वोत्तर के लगभग 18 हजार वर्ग कि.मी. में विस्तृत बांस के झुरमुट में फैलेगा। मौजूदा सामूहिक पुष्पन को मिजो भाषा में *मौ–तम* कहा जाता है, जबकि 2012 ई. में जिस सामूहिक पुष्पन की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसे *थिंग–तम* नाम दिया गया है। इस समय नीलोकैना बंबूसॉयडीज नामक प्रजाति में पुष्पन हो रहा है और मिजोरम से बांस के फूलने और चूहों की संख्या में वृद्धि की सूचना आने लगी है।

बांस से संबंधित एक भ्रांति इसके अतिज्वलनशील और लकड़ी का विकल्प साबित न होने की है। किंतु वास्तविकता यह है कि लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस का प्रयोग आसानी से हो सकता है। लकड़ी का अधिक उपयोग कागज की लुगदी, प्लाइबोर्ड, भवन निर्माण व फर्नीचर में होता है। बेहतर तकनीक से औद्योगिक उत्पादन कर उपर्युक्त क्षेत्रों में आसानी से बांस को विकल्प के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बांस मजबूत औद्योगिक आधार, पर्यावरण–मित्र तथा आवास–निर्माण के क्षेत्र में इस्पात और प्लास्टिक का अच्छा व किफायती विकल्प होने के साथ–साथ लघु–उद्योगों, हस्तशिल्पों, अगरबत्तियों, चिकित्सा उपयोगों और अन्य तमाम क्षेत्रों में भारी संभावनाओं से परिपूर्ण है। इसके बावजूद भारत में इस उद्योग के संसाधन की उपलब्धता और इसके उपयोग में अधिक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है। एक व्यावहारिक परेशानी यह है कि बांस की अधिकता तो जंगलों और दूर–दराज के गांवों के समीप है, जबकि इससे संबंधित जो उद्योग हैं भी, वे विकसित क्षेत्रों में हैं। अतः जंगली क्षेत्रों से उत्पाद केंद्र तक इन्हें ढोकर लाना पर्याप्त महंगा साबित हो जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक बांसों के प्रबंधन, इन्हें रोकने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी, नई पीढ़ी के उत्पादों का उत्पादन और कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराने की ओर भी कम ध्यान दिया गया है। बांस के विकास में नवीनतम जानकारी की कमी भी एक रुकावट है। उपयोगकर्ता समूह की आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षित प्रजातियों के बांस–रोपन को बढ़ाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बांस की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित कोई डायरेक्टरी नहीं है।

इन्हीं सब समस्याओं और इसके व्यावसायिक उपयोग को लेकर नई दिल्ली में सातवीं विश्व बांस कांग्रेस का 27 फरवरी 2004 से मार्च 2004 तक, आयोजन किया गया। यह कांग्रेस प्रत्येक तीसरे वर्ष आयोजित होती है। इस कांग्रेस में 200 से ऊपर विदेशी प्रतिनिधियों और लगभग 750 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विश्व बांस कांग्रेस का उद्घाटन तथा उपराष्ट्रपति श्री भैरो सिंह शेखावत ने इसका समापन किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि आगामी वर्षों में बांस को लकड़ी के विकल्प के रूप में विकसित करने के साथ–साथ इसकी व्यावसायिक संभावनाओं को और बढ़ाया जाए। इस कांग्रेस के साथ–साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व गिफ्ट स्प्रिंग फेयर का भी आयोजन किया गया। इस क्षेत्र से लगभग 6,000 आयातक व खरीददार जुड़े हैं। इन लोगों को भी बांस के विभिन्न उत्पाद और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों से संपर्क का अवसर मिला।

इस बांस कांग्रेस में आए प्रतिनिधियों ने बांस से संबंधित ज्वलंत समस्याओं को सामने रखा। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु आपस में सलाह–मशविरा किया। साथ ही इसने अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय व्यापारियों को एक दूसरे से मिलने का मंच प्रदान किया। इस बांस कांग्रेस में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस को किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए। विश्व बांस कांग्रेस का मुख्य लाभ यह रहा कि इसने निवेशकों, उपयोगकर्ता समूहों और कुशल कलाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक *लांचिंग पैड* का काम किया। साथ ही इस बैठक ने इस उभरते उद्योग के विभिन्न साझेदारों और समूहों को वैज्ञानिक रूप से शिक्षित करने और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस कांग्रेस में बांस के सामूहिक पुष्पन, सामूहिक विनाश और अकाल के संबंध में भी विचार–विमर्श किया गया। विद्वानों ने इससे निपटने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता बताई। यह सुझाव दिया गया कि प्रजनन द्वारा बांस के नए पौधे तैयार किये जाएं और इन्हें पुराने झुरमुट की जगह तुरंत रोप दिया जाए, ताकि वन पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रयास यह हो कि इस दौरान वनों से बांस के बीज इकट्ठा कर लिए जाएं। बाजार में इसकी अच्छी मांग है, जो

अतिरिक्त आमदनी का एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन और उचित प्रबंधन द्वारा इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि इन पौधों को पुष्पन का अवसर ही न दिया जाए। एक बार पुष्पन प्रारंभ होने पर अन्य पौधों की पुष्पन पूर्व कटाई करके उनको व्यावसायिक उपयोग में लाया जाए या फिर किसी भी पौधे को 10–12 वर्ष से अधिक बढ़ने ही न दिया जाए। *भारतीय वानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद* तथा जोरहाट स्थित इसका सहयोग संस्थान *वर्षा वन अनुसंधान* को सामूहिक रूप से रणनीति बनाकर स्थानीय आबादी को इसके प्रति जागरूक बनाने का प्रयास करना चाहिए।

इस कांग्रेस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत बांस उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक रूप से स्थापित देश के मुकाबले में अपने को तैयार करे। इसीलिए सरकार बांस विकास के क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव लाने की सोच रही है। योजना आयोग सिद्धांत रूप से बांस को बागवानी फसल की सूची में सम्मिलित करने पर सहमत हो गया है। इसका परिणाम यह होगा कि इससे सभी प्रजाति के बांसों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। बांस कांग्रेस से यह बात उभरकर आई कि भारत के गांवों में गरीब व कामगारों के लिए बांस को रोजगार पैदा करने वाले महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जाए। एक नीति के अनुसार बांस को उगाने व काटने का काम गांव का आम मजदूर करे व प्रोसेसिंग, उत्पादन एवं वितरण संबंधी अन्य सारी गतिविधियां निजी कंपनियां तथा उद्योगपति करें। सरकार की भूमिका इन समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण की होगी। इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह सुझाव दिया गया कि वन व अन्य क्षेत्रों में बांस की रोपाई सुनिश्चित की जाए, बांस को केंद्र बनाकर प्लाईवुड उद्योग को पुनः स्थापित किया जाए (सर्वोच्च न्यायालय लकड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुका है) तथा हस्तकला, कुटीर व लघु उद्योगों का विस्तार किया जाए। एक अनुमान के अनुसार इससे लाखों को रोजगार मिलेगा। इस बार की कांग्रेस बांस विकास के पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रही। ये थे – लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस को अपनाना, बांस का औद्योगिक बाजार, बांस को बेहतर उत्पाद बनाने की तकनीक, समाज व पर्यावरण पर इसका प्रभाव तथा सूचना एवं संचार का साधन।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण– मित्र के रूप में बांस जहां भूमि की जैविक उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण रखकर प्राकृतिक सफाई का कार्य करता है, वहीं लघु, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक वैकल्पिक आधार प्रदान करता है। ❑

**(लेखक कालीचरण डिग्री कालेज, लखनऊ में एशियन कल्चर (इतिहास विभाग) विषय के प्रवक्ता हैं।)**


**OUR MILESTONES**

"I found guidance from *Dr. Majid Husain* at CIVILS INDIA very useful one. CIVILS INDIA provides good environment for studying Optionals and General Studies." Arshdeep Singh

"With labour and commitment Proper guidance matters the most which I got at CIVILS INDIA" Shurbir

ARSHDEEP SINGH IAS 3rd Topper

SHURBIR SINGH IAS 4th Topper

**OTHER RESULTS**

138th - Dinesh Kumar ,IAS
145th - Dheeraj Garg ,IPS
252nd - Shyam Kanu Mohanta ,IRS
318th - Punam ,Allied
402nd - Babulal Sonal,IRS

**OUR HIGHEST IN 2003**
Geog.-362; G.S.-361; Essay-142; Interview-220

**IAS 2004-05**
**ADMISSION NOTICE**

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

**GEOGRAPHY** by Prof. Majid Husain
Registration Open June,2005 Batch Screen Test On 22.5.05
*"A name needing no introduction"*
**6th Topper in the very first Batch (2002) and 3rd & 4th Toppers in the second Batch (2003)*

**GEN. STUDIES** by Dr.Majid Husain, Dr. Ramesh Singh, Dr. S. S. Pandey & Neeraj Singh
*4th Topper in the very first Batch (1998)*
*6th Topper in (2002) & 3rd and 4th in 2003.*
WORKSHOP 28 Nov. 9 AM

**ECONOMY** by Dr. Ramesh Singh
*"Making Economy the easiest for anybody"*
*Batches every month*
STARTS 2. 11. 04

**समाजशास्त्र** by Dr. S. S. Pandey
Nex Batch : 25 Nov. Workshop 23 नवंबर (4 बजे सायं) (At CIVILS INDIA only)
*"हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक लोकप्रिय"*

**दर्शनशास्त्र** by Deepak Kumar
*"Class करें और अंतर देखें"* कक्षा प्रारंभ : 25 नवंबर
• Module की सुविधा • Improvement Programme

**HISTORY** by Sanjay Varma & नीरज सिंह
कक्षा प्रारंभ : 25 नवंबर Workshop के साथ

**SPECIAL FEATURES**
• Two types of Notes : (1) Exhaustive type
(2) Model Answer type
• Everyday Assignments/Writing Practice/Timely Tests
• Personal Guidance Programme (PGP) also
• Fleximodule in GS [Listen classes and G.S. is prepared]

CIVILS INDIA®
The Quality Institute for IAS
A/12-13,202-203, ANSALBUILDING
BEHIND BATRA CINEMA,
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09
Ph.: 27652921, 9810553368 (Dr.) 9818244224 (Couns.),

AVINASH TIWARI'S

# निष्ठा

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक उत्कृष्ट संस्थान

## दर्शनशास्त्र

**प्रारम्भिक परीक्षा**

### द्वारा अविनाश तिवारी

- एक दशक से अधिक का सफल एवं लोकप्रिय अध्यापन अनुभव।
- तर्कशास्त्र की मानक पुस्तकों के लेखक (तर्कशास्त्र के सिद्धान्त, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र)।
- पाठ्यक्रम के तीनों भागों दर्शन की समस्यायें, तर्कशास्त्र तथा नीतिशास्त्र पर समान बल।
- क्या पढ़े? कैसे पढ़ें? कहाँ से पढ़ें? जैसी समस्याओं की निवृत्ति।
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का बिन्दुवार विश्लेषण करके लक्षित रणनीति।
- अब पाश्चात्य दर्शन तथा भारतीय दर्शन पर भी समान बल।

**मुख्य परीक्षा**

### द्वारा प्रो० द्विवेदी एवं अन्य

- भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ समूह द्वारा।
- दर्शनशास्त्र की ख्यातिलब्ध पुस्तकों के लेखक।
- तीन माह का गहन अध्यापन।
- विषय का विशद्, समग्र तथा विश्लेषणात्मक अध्यापन के साथ परिष्कृत एवं परिमार्जित अध्ययन सामग्री।
- मॉडल उत्तर तथा सम्पूर्ण पृष्ठभूमि सहित उत्तर लेखन कला का विकास प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए।
- सामाजिक राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा

● लेखक श्री राममूर्ति पाठक ●

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वांछनीय एवं उपयोगी

**कक्षाऐं प्रारम्भ 28 दिसम्बर, 2004**

## सामान्य अध्ययन

| | |
|---|---|
| भारतीय अर्थव्यवस्था | अरूणेश सिंह (लेखक) |
| विद्यान एवं प्रौद्योगिकी | एस. के. आर. वर्मा |
| भारतीय राजव्यवस्था | ओ. पी. सिंह |
| भूगोल | सिद्धार्थ कुमार(लेखक) |
| इतिहास | विषय विशेषज्ञ |
| साख्यिकी व मानसिक योग्यता | असीम मुखर्जी |

- सामान्य अध्ययन के सभी खण्ड विषय-विशेषज्ञों द्वारा।
- सामान्य अध्ययन के प्रत्येक खण्ड की नियमित टेस्ट व्यवस्था
- पाठ्यक्रम अवधि 4 माह

निःशुल्क कार्यशाला 28, 29, 30 दिसम्बर '04' * कक्षाएं प्रारम्भ 6 जनवरी 2005

लोक प्रशासन : एम० के० सिंह (दिल्ली) कार्यशाला 28 दिसम्बर

दर्शनशास्त्र का
पत्रचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
प्रारंभिक परीक्षा: 2000/ और मुख्य परीक्षा: 2500/

**सम्पर्क सूत्र**

Phone : 0532-2611212, 2467642,
Mob. : 9415638449, 9415308157

1183, इस्लाम काम्पलेक्स, मनमोहन पार्क, पुराना कटरा, इलाहाबाद - 211002

# सारी बीमारियों की रामबाण दवा – प्राणायाम

## स्वामी रामदेवजी द्वारा प्रतिपादित

○ राजेन्द्र राय

'प्राणायाम' शब्द का सामान्य अर्थ प्राण वायु अर्थात सांस को नियंत्रित करना है। हालांकि प्राणायाम का संबंध हमारे सांस लेने की प्रक्रिया से है लेकिन इससे हमारे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों, जैसे – मस्तिष्क, नाड़ियां, फेफड़े, हृदय, यकृत, गुर्दे, अग्नाशय और आंतों सहित संपूर्ण शरीर के समस्त अवयवों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। नियंत्रित श्वास–क्रिया (प्राणायाम) की शक्ति की जांच कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आप इंटरव्यू में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं या आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है और हृदय तेजी से धड़क रहा है अथवा किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं या आपको किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है तो यह उपाय आजमाइए। केवल 10 बार धीरे–धीरे लंबी और गहरी सांस लीजिए और फिर देखिए कमाल! आपका तनाव और गुस्सा छू मंतर हो जाएगा।

यह लेख आरोग्य के बारे में मेरे 30 वर्ष के व्यक्तिगत अनुभवों और पतंजलि के योग–सूत्र में बताए गए प्राणायाम की स्वामी रामदेवजी द्वारा की गई नई व्याख्या पर आधारित है। यहां मैं बता दूं कि स्वास्थ्य के बारे में मैं जुनून की सीमा तक जागरूक हूं और कह सकता हूं कि सेवा नियमों और कानूनों के अध्ययन के बाद स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें पढ़ना और

व्यायाम करना मेरी दूसरी हाबी है। 1983–84 के दौरान 39–40 वर्ष की उम्र में जब मैं आकाशवाणी, नई दिल्ली में संपादक के रूप में कार्यरत था, श्रीनिवासपुरी से आकाशवाणी भवन की 10.5 किलोमीटर की दूरी जागिंग करते हुए एक घंटे में तय करता था। यह कार्यक्रम 21 महीने तक चला जब तक कि रेडियो से मेरा तबादला नहीं हो गया। स्वास्थ्य संबंधी विषयों की पुस्तकों और पत्रिकाओं पर मैंने हजारों रुपये खर्च किए हैं। पिछले 25 साल से मैं नियमित रूप से *'रीडर्स डायजेस्ट'* का ग्राहक हूं क्योंकि इसके प्रत्येक अंक में स्वास्थ्य पर दो–तीन लेख होते हैं।

मुझे याद है, *'रीडर्स डायजेस्ट'* के 1979 या 1980 के किसी अंक में प्राणायाम पर फिलिप स्मिथ का एक पूरा लेख छपा था। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह प्राणायाम का अभ्यास करके उन्होंने अपने अनेक जीर्ण रोगों का उपचार खुद कर लिया। *'रीडर्स डायजेस्ट'* के मई 1998 के अंक में भी प्राणायाम के बारे में एक डाक्टर की संक्षिप्त आप बीती कहानी छपी थी जिसे मैं आपके लिए यहां दे रहा हूं।

***जीवन की सांस***

*अपने आपरेशन थियेटर के बाहर एक दिन मैंने एक बुजुर्ग रोगी को स्ट्रेचर पर लेटे अपनी बारी का इंतजार करते देखा। मैं उसका इलाज नहीं कर रहा था लेकिन उसकी सुगठित देह को देखकर मैं चक्कर में पड़ गया। जब मैंने उसके रोगी –चार्ट को देखा तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह 90 साल का था। मैंने उससे दीर्घ जीवन का रहस्य पूछा तो उसने बताया: 'बस सांस लेते रहिए।'*
*– नारिस जानविरिया द्वारा प्रेषित।*

तमाम बीमारियों की रोकथाम और इलाज की संपूर्ण विधि के रूप में स्वामी रामदेवजी का बताया तरीका महान योगाचार्यों द्वारा योग और प्राणायाम पर लिखी गई समस्त परंपरागत पुस्तकों में वर्णित विधियों से अलग है। स्वामी रामदेवजी कपालभाति पर जितना जोर देते हैं उतना और किसी ने नहीं दिया है। सभी पुस्तकों में पेट से सांस लेने को कहा गया है जबकि स्वामीजी फेफड़ों और सीने से सांस लेने की बात कहते हैं।

जब तक मैं और मेरी पत्नी श्रीमती उषा राय नई दिल्ली के जवाहर लाल

नेहरू स्टेडियम में आयोजित (7 से 13 अक्टूबर 2004) साधना शिविर में सम्मिलित नहीं हुए तब तक मुझे एक सप्ताह में 5 से 10 किलोग्राम वजन कम होने, मधुमेह के पूरे उपचार, रक्तचाप पर नियंत्रण, हृदय रोगों (धमनियों में रुकावट दूर करने और कोलेस्टरोल व ट्राइग्लीसराइड्स के स्तर में कमी), दमा तथा मानसिक अवसाद के उपचार के रामदेवजी के दावे पर थोड़ा संदेह था। लेकिन प्राणायाम पर उनकी पुस्तक पढ़कर तथा उनकी पुरानी सी.डी. पर कार्यक्रम देखकर 5 अप्रैल, 2004 से उनके प्राणायाम का अभ्यास करते हुए छह महीने हो गए हैं। इसके साथ ही मैंने सुबह को 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक घंटा सैर करना भी नहीं छोड़ा है। (तेज–तेज चलने के लिए आदर्श रफ्तार 10 से 12 मिनट प्रति किलोमीटर है) लेकिन मेरे वजन में कोई कमी नहीं आई और यह 67 किलोग्राम पर बना रहा। 1996 से मैं नियमित रूप से लोधी गार्डन सैर के लिए जाता हूं और अपने खान–पान पर बिना कोई नियंत्रण किए पूर्ण स्वस्थ हूं (मैं औसतन तीन मिठाई रोज खाता हूं)। शक्कर वजन का बड़ा दुश्मन है। मेरी पत्नी 1999 से रोजाना शाहजहां रोड पार्क में एक घंटे योगासन कर रही हैं, फिर भी 6 अक्टूबर, 2004 को उनका वजन बढ़कर 69 किलो ग्राम हो गया जबकि 2 जून, 1998 को यह 65 किग्रा. था। 7 दिन के शिविर के दौरान मेरी पत्नी और मेरा वजन एक–एक किलोग्राम कम हो गया। 10 अक्तूबर, 2004 को स्वामीजी के आह्वान पर मैंने अपनी पत्नी के साथ रक्तदान किया। उसी दिन मैंने तंबाकू का सेवन न करने का भी संकल्प लिया। 1970 से मैं इस लत का शिकार था।

मेरे मित्र और सहयोगी श्री रामजी त्रिपाठी भी अपनी पत्नी के साथ शिविर में शामिल हुए थे। श्री त्रिपाठी का वजन 85 किग्रा. से घट कर 78 किग्रा. और उनकी पत्नी का 75 किग्रा. से 3 किग्रा. घट कर 72 किग्रा. रह गया। इसी दिन श्री त्रिपाठी के लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में भी सुधार हुआ। उनका रक्त कोलेस्टोराल 226 (14 जुलाई, 2004) से 16 मिग्रा. प्रति डेसीलीटर घटकर 210 पर आ गया। उनकी साइनस की बीमारी में भी में 75 प्रतिशत का सुधार हुआ। अब पति–पत्नी दोनों टेलीविजन पर स्वामी रामदेवजी का कार्यक्रम देख कर एक घंटे से अधिक योगासन और प्राणायाम करते हैं। मेरे दूसरे अभिन्न मित्र श्री विनोद कुमार मिश्र पिछले 22 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित हैं। पिछले चार वर्षों से सुबह–शाम 500 मिग्रा. वालाफ़ेज की एक–एक टेबलेट और दिन में इगलूकॉन की एक गोली खा रहे हैं। लेकिन खाने के बाद उनकी रक्त–शर्करा में 208 (14.4.2004 की जांच रिपोर्ट) से कमी नहीं आई। वे 5.5.2004 से टी.वी. देखकर लगातार स्वामी रामदेवजी के प्राणायाम कर रहे हैं। अब उनकी पी.पी रक्त–शर्करा पूर्ण सामान्य 130 (27.5.2004) और 135 (27.6.2004) रही है। अभी उन्होंने दवाई नहीं छोड़ी है।

अपने इस अनुभव से मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केवल स्वामीजी की पुस्तकों और सी.डी. पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि रामदेवजी खुद भी प्राणायाम के अपने तरीके में दिन–प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं। आप समय के साथ–साथ आए परिवर्तन को कुछ साल पुराने कैसेट पर देखकर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। रामदेवजी ने प्राणायाम को इतना आसान बना दिया है कि 2 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का वयोवृद्ध व्यक्ति भी कठोर नियमों के चक्कर में उलझे बिना इसका अभ्यास आसानी से कर सकता है। आपको कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम में सांस की रफ्तार बहुत अधिक बढ़ाने से बचना चाहिए। कपालभाति में एक मिनट में 60 से 65 बार सांस खींचनी–छोड़नी चाहिए।

प्राणायाम पर लिखी सभी पुस्तकों में इस बात पर जोर दिया गया है कि भस्त्रिका में सांस खींचना और छोड़ना पूरा जोर लगाकर और तेजी से करना चाहिए। लेकिन स्वामी रामदेवजी का कहना है कि भस्त्रिका में धीमी गति से पूरी सांस लेनी और छोड़नी चाहिए। नई दिल्ली के एस्कार्ट्स अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डा. नरेश त्रेहन इसे विपासन का नाम देते हैं और इसे ऐसा ध्यान मानते हैं जिससे उनके शरीर में नई स्फूर्ति का संचार होता है। उनके अनुसार इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। डा. त्रेहन सुबह अपने घर से अस्पताल जाते हुए कार में ही 5–7 मिनट इसका अभ्यास कर लेते हैं।

इस समय स्वामी रामदेवजी कई जीर्ण और घातक रोगों के स्वयं उपचार करने और स्वस्थ रहने के लिए 6 तरह के प्राणायाम के एक पैकेज का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। ये हैं – (1) भस्त्रिका (2) कपालभाति (3) बाह्य प्राणायाम (4) अनुलोम–विलोम प्राणायाम (5) भ्रामरी प्राणायाम और (6) ओंकार जाप। प्राणायाम की ये विधियां स्वामी रामदेवजी द्वारा आयोजित साधना शिविरों के कार्यक्रमों के सीधे प्रसारणों को देखकर सीखी जा सकती हैं।

स्वामीजी बताते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 2 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट कपालभाति, 3 बार बाह्य प्राणायाम, 5 से 10 मिनट अनुलोम–विलोम, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और 3 बार ओंकार जाप करना चाहिए। जीर्ण रोगी स्वचिकित्सा के रूप में कपालभाति और अनुलोम–विलोम प्राणायाम का अभ्यास हर सुबह 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इस पैकेज के अलावा

सर्दी–जुकाम, हकलाने, खर्राटे भरने, थायराइड, टौंसिल, रक्तचाप, मानसिक अवसाद और हृदय रोग में 10 बार तक उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए।

अंत में मैं आपको यह भी बता दूं कि आज भी स्वामीजी के प्रवचनों में बताई जाने वाली सभी बातों में मेरी पूरी आस्था नहीं है। उदाहरण के लिए स्वामीजी प्राणायाम का अधिकतम फायदा उठाने के लिए ब्रह्मचर्य के पालन का उपदेश देते हैं, जबकि मेरा मानना है कि यह कल्पना मात्र है। काम भावना सभी जीवों की – जिनमें मनुष्य और पशु–पक्षी आदि समस्त प्राणी शामिल हैं – सबसे स्वाभाविक सहज वृत्ति है। इसके दमन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आज के युग में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन बिताने की बात सोची भी नहीं जा सकती।

इसके अलावा मैं स्वामी रामदेवजी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि सुबह–सुबह एक गिलास पानी पी लेने से कब्ज दूर हो जाएगा। मुझे दिल्ली के पानी से हमेशा कब्ज रहता था। इससे निपटने के लिए मैं 1983 से नियमित व्यायाम के साथ कई दवाओं (त्रिफला, कब्जहर, होम्योपैथी आदि) का सहारा ले चुका हूं, मगर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 1996 से जब से मैंने सुबह को सवा से डेढ़ लीटर पानी एक साथ पीना शुरू किया है तब से मैं कब्ज और बदहजमी से पूरी तरह मुक्त हूं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और नियंत्रित आहार भी बेहद जरूरी है। सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अध्यक्ष श्री आर.पी. पुरी 84 साल की उम्र में भी जोशो–खरोश से भरे हुए हैं और इस अवस्था में पहुंच कर भी अपना व्यवसाय देखते हैं। उन्होंने अपने वजन में 30 किलोग्राम की कमी करके इसे 90 से 60 किलोग्राम पर ला दिया है और पिछले 30 साल से उनका यही वजन बरकरार है। रोजाना केवल 1350 कैलोरी वाला भोजन लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरे साथी और सहयोगी मोहम्मद यूनुस सिद्दिकी पिछले 40 वर्ष से केवल 15 से 20 मिनट तक घर पर ही रोज व्यायाम कर (जिसमें हमारे पारंपरिक दंड–बैठक भी शामिल हैं) पूर्णरूप से तंदुरुस्त हैं। उन्होंने खाने में कैलोरी पर कभी नियंत्रण नहीं रखा लेकिन जीवन में कभी चाय या काफी को हाथ नहीं लगाया। तात्पर्य यह है कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन पर सामान्य नियंत्रण रखते हुए व्यायाम करना आवश्यक है।

गत 23 अक्तूबर, 2004 को इतिहास पुरुष फील्ड मार्शल मानेकशा ने 61वीं घुड़सवार सेना की परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। जब मैंने उनसे उनके स्वास्थ्य का राज पूछा तो अपनी कड़कती आवाज में उन्होंने उत्तर दिया : "आज के दिन मैं 90 वर्ष, 6 महीने और 13 दिन का हूं... आप खुद मेरे स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं।"

आश्चर्य है कि स्वामीजी ने दूध और दूध से बनी चीजों के सेवन के फायदों के बारे में कुछ नहीं कहा है जो हजारों वर्षों से भारतीयों का मुख्य आहार रहे हैं। इन्हीं की बदौलत भारतीयों का स्वास्थ्य अच्छा रहता रहा है। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर कपालभाति प्राणायाम के साथ दिन में 3–4 बाद कम वसा वाला दूध या दही अथवा पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद भी लिए जाएं (कैल्शियम से वजन और उच्च रक्तचाप कम होता है) तो इससे मोटापा घटने की प्रक्रिया की रफ्तार दुगुनी हो जाएगी। लेकिन प्राणायाम से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हां, इससे आप स्वस्थ जीवन जीने का तरीका सीख सकते हैं। अधिक मोटे लोगों के वजन कम होने में प्राणायाम का असर तेजी से होता है। आप देख सकते हैं कि स्वामीजी के साधना शिविर में भाग लेने वालों में 60 प्रतिशत से अधिक लोग काफी मोटे होते हैं।

स्वामीजी के प्रवचन के कुछ मुद्दों पर मेरे मतभेद के चाहे जो भी कारण रहे हों, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि **स्वामी रामदेवजी ने भारत की प्राचीन योग और प्राणायाम जैसी विधाओं के फायदों के बारे में करोड़ों लोगों में जागरूकता पैदा करके उनके जीवन में क्रांति ला दी है।** उन्होंने मानवता को स्वस्थ और निरोग बनाने का जो अभियान शुरू किया है उसके माध्यम से वह मानव जाति की बड़ी सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह यह कार्य निःशुल्क करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करके और उनके "आरोग्य हमारा जन्म–सिद्ध अधिकार है" के सूत्रवाक्य को आत्मसात करके हम उनके इस अभियान को सफल बना सकते हैं। इससे सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला करोड़ों रुपये का भारी खर्च भी बचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. ए. रामदास ने 4 नवंबर, 2004 को सामाजिक क्षेत्र के विषयों के संपादकों के पांचवें सम्मेलन में घोषणा की है कि सरकार नई दिल्ली के अशोक रोड स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग की पढ़ाई की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे डाक्टर हृदय रोग विज्ञान के उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जा रहे हैं जबकि अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञों ने हृदय रोगियों के इलाज के लिए योग का अभ्यास अनिवार्य कर दिया है। विश्व में आरोग्य की समृद्ध विरासत में भारत ने योग विद्या के रूप में जो अवदान दिया है वह अप्रतिम है। ❑

**(राजेन्द्र राय 'योजना' के संपादक हैं)**

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा - 2005

IAS

# दर्शनशास्त्र

PCS

सर्वाधिक लोकप्रिय एवं अंकदायी विषय

द्वारा

## धर्मेन्द्र कुमार

कक्षा कार्यक्रम, सत्र-2004-05

## दर्शनशास्त्र (Philosophy)

**प्रथम स्वतंत्र बैच**

**5** नवम्बर, समयः 8.30 प्रातः)

**द्वितीय स्वतंत्र बैच**

**25** नवम्बर, समयः 5.30 सायं)

*(निःशुल्क परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ)*

दर्शनशास्त्र (प्रारम्भिक)
Philosophy (P.T.)

**16** जनवरी

**पत्राचार कार्यक्रम**
दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा)

संस्थान दर्शनशास्त्र हेतु पर्याप्त, गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ, अत्यन्त उपयोगी एवं प्रमाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। इसमें वैसे अध्यायों पर विशेष बल दिया गया है जिस पर प्रमाणिक सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं है। पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिये २६०० रू० का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट 'PATANJALI IAS CLASSES' के नाम भेजें।

**PATANJALI**

2580, हडसन लाईन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009
फोन : 011-30966281, मोबाईल : 9810172345

सलाह, सहयोग, समर्थन-दर्शन प्रसार एवं अनुसंधान केन्द्र

# I.A.S. 2005

प्रारम्भिक एवम् मुख्य परीक्षा

# राजनीति विज्ञान

सर्वाधिक लोकप्रिय एवम् सशक्त विषय

द्वारा

## जितेन्द्र कृष्णन

.....आपके श्रम व प्रतिभा को सही आकार एवम् दिशा देने के लिए
.....राजनीति विज्ञान के उचित मार्ग दर्शन की शून्यता को भरने के लिए

बैच प्रारंभ - 1 दिसम्बर 2004
नामांकन प्रारंभ - 15 नवम्बर 2004

*उनके लिए- जो प्रारंभ कर रहे हैं,*
*और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।*

**निःशुल्क कार्यशाला**

28, 29 व 30 नवम्बर 2004

समय : 11.00 बजे से 01.00 बजे तक

**PATANJALI**

2580, हड़सन लाईन,
किंग्जवेकैम्प, दिल्ली-110009
फोन : 011-30966281, मोबाइल : 09891138408

# अंतरिक्ष से अध्यापन

○ शैलेंद्र मोहन कुमार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 20 सितंबर, 2004 की एडुसैट नामक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कर देश के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित यह उपग्रह पूर्णतः स्वदेशी है।

एडुसैट का आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से ठीक 4 बजकर 1 मिनट पर जी.एस.एल.वी. रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। प्रक्षेपण इतना सही था कि 17 मिनट बाद ही यह निर्धारित भू–कक्षा में पहुंच गया। 1950 किलोग्राम भारी, एडुसैट भारत द्वारा अब तक प्रक्षेपित सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। जी.एस.एल.वी. अर्थात् जियोस्टेशनरी लांच भेहिक्ल, जिसने एडुसैट उपग्रह को भू–कक्षा में पहुंचाया, के लिए भी यह एक बड़ी सफलता थी। 414 टन वजन के इस रॉकेट ने इससे पहले जी एस ए टी–1 और जी एस ए टी–2 उपग्रहों को क्रमशः अप्रैल 2001 और मई 2003 में अंतरिक्ष में पहुंचाया था।

अभी हाल ही में प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिकों को शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करते समय नई दिल्ली में कहा था कि भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम सभी का जीवन और अच्छा बनाना चाहिए। एडुसैट इस ध्येय को निश्चय ही पूरा कर सकेगा।

जैसाकि इसके नाम से ही विदित है, यह उपग्रह सभी स्तरों पर शिक्षा और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को एक दुष्कर काम के लिए अपनाया जा रहा है। यह अच्छे शिक्षकों और पाठ्य सामग्री की कमी को दूर करने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है। देश के छोटे नगरों और गांवों के विद्यार्थी इससे विशेष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। विद्यार्थी न केवल अपने शिक्षक को देख और सुन सकेंगे बल्कि पाठ समझ में नहीं आने पर उसी समय उनसे प्रश्न और स्पष्टीकरण भी पूछ सकेंगे। इस क्रिया में उपग्रह–प्रसारण तकनीक को अत्यंत व्यापक बना दिया जाएगा।

आशा की जाती है कि इस प्रौद्योगिकी की देशव्यापी पहुंच और प्रभाव का लाभ उठाकर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अधिकारी अपने श्रेष्ठ शिक्षकों को न केवल इस कार्य में लगायेंगे बल्कि नई–नई शिक्षण प्रणाली भी विकसित कर सकेंगे।

अगले दो वर्षों तक अपनी प्रायोगिक अवस्था में रहने के दौरान एडुसैट से प्रसारित कार्यक्रम एक हजार कक्षाओं में लगभग 50 हजार छात्र–छात्राओं तक पहुंच सकेंगे। जैसे–जैसे इस पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ेगी लोग स्वयं ही बड़ी संख्या में आकृष्ट होकर इससे लाभ उठाने लगेंगे। इसरो के अध्यक्ष श्री जी. माधवन नायर का मानना है कि एडुसैट बहुत जल्द ही उपग्रह के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में भारत को पूरे विश्व में अग्रणी स्थान पर ला देगा।

एडुसैट अंतरिक्ष यान को भू–कक्षा में पहुंचाने वाले जी एस एल वी रॉकेट की उपलब्धि भी उल्लेखनीय है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर इस श्रृंखला का एक यान फरवरी 2004 में उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें कई लोग मारे गए थे। इस बार भी उसके प्रक्षेपण से एक दिन पहले श्रीहरिकोटा में भारी वर्षा के कारण आशंका थी कि कहीं उसका प्रक्षेपण स्थगित न करना पड़े। लेकिन संयोग से मौसम एकदम ठीक हो गया और प्रक्षेपण निर्धारित समय पर एकदम ठीक से हुआ।

एडुसैट का निर्माण 90 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। 21 सितंबर को कर्नाटक में हासन स्थित नियंत्रण–कक्ष से कमान देकर इसे पृथ्वी की कक्षा में निर्धारित बिंदु पर पहुंचा दिया गया। यह इस समय 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की गति के अनुरूप अंतरिक्ष में उड़ रहा है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ट्रांसपौंडर लगे हुए हैं। ट्रांसपौंडर वे इलेक्ट्रोनिक यंत्र हैं जो पृथ्वी–स्थित केंद्रों से प्रेषित विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त और विस्तार कर पुनर्प्रसारित कर देते हैं।

एडुसैट की क्षमताओं के बारे में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर पिछले तीन महीनों में पांच सम्मेलन हुए हैं। इनमें इसरो के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और इस अंतरिक्ष यान के उपयोगकर्ताओं को बताया कि वे कैसे शिक्षा विस्तार के कार्यक्रमों में इसे प्रयोग कर सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने 7 वर्षों के जीवन–काल में एडुसैट ज्ञान और साक्षता बढ़ाने में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। ❑

(विज्ञान लेखक)

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

# इतिहास
# रजनीश राज

**पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 15 छात्रों ने 325 से 360 के बीच अंक प्राप्त किए।**

**कैसे?**

- इतिहास पढ़ाने की वैज्ञानिक शैली।
- हम आपको प्रशासक बनाते हैं इतिहासकार नहीं।
- 150 प्रश्नोत्तरों का समुचित मूल्यांकन।
- उत्तर लेखन शैली में सुधार।
- जानिए कि एक-2 अंक कैसे बढ़ता है।
- मॉडल उत्तर और समेकित सामग्री।
- यथोचित पुनरावलोकन।

**Pt.-**

- Pt. की तैयारी तथ्यों के अम्बार से नहीं तकनीकी स्तर पर।
- 20 सावधिक टेस्ट।
- 4000 प्रश्नों के माध्यम से पुनरावलोकन।
- विशद विश्लेषण।
- उच्चस्तरीय सामग्री।

**तृतीय बैच आरम्भ : 25 दिसम्बर से**

**नामांकन प्रारम्भ**

**SIHANTA IAS**

632, Mukherjee Nagar, Delhi-9
(Near Aggarwal Sweets)
9873399588, 9871423426

# विकास, स्वच्छ वातावरण और भलाई के प्रतीक : संत बलबीर सिंह सीचेवाल

○ बलबीर माधोपुरी

*पवित्र काली वेईं (नदी) की कार–सेवा निर्मल कुटिया सीचेवाल के मुख्य संचालक संत बलबीर सिंह सीचेवाल की ओर से चार वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। वह 'वेईं वाला बाबा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यों के साथ–साथ पारस्परिक भाईचारे के प्रतीक और प्रेरणा के केंद्र बन चुके 'बाबा जी' और उनके कार्यों का ब्यौरा यहां प्रस्तुत है।*

'काली वेईं (महान कोश के अनुसार सफेद वेईं) यानी निर्मल और स्वच्छ पानी की नदी। सदियों पुरानी इस नदी का स्रोत धनोआ हिम्मतपुर गांवों (निकट – मुकेरियां, जिला–होशियारपुर) के करीब से बहते व्यास दरिया की सेम है। कहने का तात्पर्य है कि जमीन के नीचे से पानी सोते–झरनों की शक्ल में अपने–आप फूटती है जिससे पानी के बहाव की धारा बनती है और फिर एक नदी का रूप धारण करती है। दसूहा, बेगोवाल, भुलथ्थ, सुभानपुर, सुल्तानपुर लोधी और अन्य गांवों–कस्बों के करीब से 160 किलोमीटर का रास्ता तय करके 'हरि के पत्तण' के निकट, जहां सतलुज और व्यास दरिया आपस में मिलते हैं, में समाहित हो जाती है।

जैसा कि ऐतिहासिक तथ्य है कि दुनिया की समूची सभ्यताएं नदियों के किनारों पर विकसित हुई हैं और परवान चढ़ी हैं। काली नदी की भी इस प्रसंग में अपनी पृथक और न्यारी भूमिका है।

काली नदी के किनारे बसा सुल्तानपुर लोधी कस्बा अब जिला कपूरथला का सब–डिवीजन हैडक्वार्टर है, जो कपूरथला से 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है।

यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि गुरु नानक यहां अपनी बहन बीबी नानकी बी की ससुराल में आकर टिके, इस कारण इस शहर को अथाह प्रसिद्धि मिली। गुरु नानक अपने प्रवास के दौरान लगभग 14 साल वह इसी नदी में स्नान करते रहे। यहीं पर उन्होंने 'न हम हिंदू, न मुसलमान' का नारा बुलंद किया। कहा जाता है कि गुरु नानक ने 'जपुजी' का मूल मंत्र इसी नदी के तट पर उच्चारा था।

अब इस कस्बे में गुरुद्वारा संतघाट, हट्ट साहिब, कोठड़ी साहिब, गुरु का बाग, बेर साहिब आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं।

*काली नदी की पवित्रता को फिर से बहाल करने में जुटे लोग*

**काली नदी : गंदे नाले का रूप**

कभी निर्मल और पवित्र जल के रूप में जानी जाती काली नदी पिछले कुछ दशकों से गंदे नाले की शक्ल अख़्तियार करती गई। लोग इसके प्रति ग़ैर–जिम्मेदारी का रवैया अपनाते गए। शहरों के विस्तार के कारण इसके किनारे बसते कस्बों–शहरों, जैसे – कपूरथला, दसूहा, टांडा, बेगोवाल के सीवरों का और आसपास के गांवों का गंदा पानी इसको मैला करता चला गया। कारखानों के प्रदूषित और रसायनों से भरपूर पानी तथा लोगों की बेसमझी और स्वार्थी भावना के चलते इस नदी के साथ अन्याय और जोर–जबर्दस्ती होती गई। गंदगी के ढेर उसकी छाती पर रखे जाते रहे। परिणामस्वरूप, स्वच्छ पानी का बहाव रुक गया और बूटी, दंभ (एक प्रकार की घास), आक–आकड़ा, नड़ी आदि उगते चले गए। पानी की सड़ांध दूर–दूर तक मार करने लगी। बरसात के दौरान मारक असर अपना जलवा दिखाने लगा। सेम के कारण आसपास के इलाके की फसलें गलने–सड़ने लगीं। किसानों में रोष–विद्रोह उपजा। लोग सरकार को ज्ञापन दे–देकर थक गए।

**काली नदी : कार–सेवा का सबब**

काली नदी की पवित्रता को फिर से बहाल करने के लिए बातें आरंभ हुईं और खत्म हुईं। पर 'धरत सुहाई' नाम की गैर–सरकारी स्वयंसेवी संस्था ने 15 जुलाई, 2000 को इस नदी को प्रदूषण–रहित बनाने के मसले पर विचार–विमर्श करने के वास्ते बुद्धिजीवियों और समाज सेवा को समर्पित शख्सीयतों की बैठक जालंधर में बुलाई। विद्वानों ने पवित्र नदी की खतरनाक और नाजुक हालत पर अपने–अपने विचार पेश किए। उपस्थित जनों ने गंभीरता से चिंता प्रकट की। यह सब सुनने और विचारने के बाद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने इसकी पवित्रता को पुनः कायम करने का जिम्मा लिया और उन्होंने काली नदी की कार–सेवा आरंभ करने के अपने फैसले का ऐलान कर दिया। इस मानसिकता के पीछे ऋषियों–मुनियों, गुरुओं–पीरों की सफाई और पवित्रता की भावना कार्यशील थी। दूसरी बात यह कि इसके जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़नी थी ताकि वे प्रेरणा ले सकें और वर्तमान पीढ़ी अपनी गलतियों से सुर्खरू हो सकें। कुछ लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि इस पहाड़ जैसे बड़े और अनोखे काम को कोई अकेला व्यक्ति कैसे पूरा कर सकता है! पर अगले ही दिन यानी 16 जुलाई, 2000 को संत बलबीर सिंह ने सुल्तानपुर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बेर साहिब को आती सड़क की कार–सेवा आरंभ की ताकि कार–सेवकों को सुल्तानपुर आने के लिए कोई कठिनाई न हो और न ही अधिक समय नष्ट हो।


# भूगोल विश्व एवं भारत

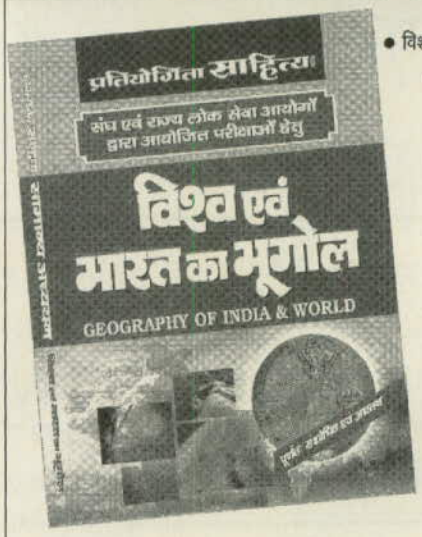


- विश्व एवं भारत के रंगीन मानचित्र
- विश्व के 191 देशों के रंगीन ध्वज

Book Code : 850
Pages : 184
Price : Rs. 140/-

**विषय-सूची**

**विश्व का भूगोल :** • ब्रह्माण्ड (सौरमण्डल, सौरमण्डल की उत्पत्ति) • अक्षांश, देशान्तर और समय • स्थलमण्डल • महाद्वीप (एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अण्टार्कण्टिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, आस्ट्रेलिया) • पर्वत • पठार • मैदान • झीलें, शैल अथवा चट्टान • विश्व की मिट्टियां, भूतल पर परिवर्तनकारी शक्तियां • वायुमण्डल • जलमण्डल (महासागरीय नितल के उच्चावच, महासागर जल की गतियां, ज्वार भाटा) • विश्व : कृषि • विश्व : ऊर्जा और खनिज • विश्व : उद्योग • विश्व : जनसंख्या (जनसंख्या : वितरण एवं वृद्धि, मानव का अर्विभाव एवं विकास, मानव प्रजाति का वर्गीकरण) • विश्व : परिवहन एवं व्यापार • विश्व : पर्यावरण (विश्व वन वितरण, विश्व के पशु-पक्षी) • विश्व के देश • भौगोलिक परिभाषाएं • जलवायु : पारिभाषिक शब्दावली • विभिन्न भौगोलिक शब्दावली • सममान रेखाएं • वस्तुनिष्ठ प्रश्न

**भारत का भूगोल :** • भू-वैज्ञानिक संरचना • प्रशासनिक परिचय • उच्चावच एवं भू-आकृतिक प्रदेश • अपवाह प्रणाली • जलवायु • मिट्टियां • प्राकृतिक वनस्पति • जल संसाधन • कृषि • वानिकी एवं मत्स्य व्यवसाय • खनिज • ऊर्जा • उद्योग एवं औद्योगिक विकास • जनसंख्या एवं सामाजिक भूगोल • परिवहन • भारत के राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश

**प्रतियोगिता साहित्य**

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

**बहुपक्षीय विकास कार्य और आलोचना**

शहर की प्रमुख हस्तियों और लोगों के सहयोग से गुरुद्वारा संत घाट के समीप कार–सेवा शुरू की गई। निश्चय ही यह एक विशाल कार्य का आरंभ था जिसके विषय में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। सरकारों की तो बात ही क्या! दूसरे, यह बहुपक्षीय काम अति महत्वपूर्ण था जैसे कि नदी के रास्ते की सफाई करना, बांध लगाना, पेड़ और फूल–पौधे लगाना, बांध पर पत्थर लगाना, रकबे की निशानदेही करना आदि।

इस सबके पीछे कुछ चुनौतियां भी खड़ी थीं। सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर कई तकनीकी कठिनाइयां सामने थीं जैसे कि अधिकारियों द्वारा सहयोग न करना या नदी के रकबे की निशानदेही करवाने से कन्नी काटना और रिकार्ड आदि उपलब्ध न करवाना। एक बड़ी समस्या यह थी कि जिन किसानों की जमीनें नदी के साथ लगती हैं– वे इस बात से डरकर संत सीचेवाल का विरोध करते थे कि नाजायज कब्जे वाली उनकी जमीनें कहीं उनके हाथ से चली न जाएं।

**संत सीचेवाल से बातचीत**

संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने बताया कि कइयों के सामने हाथ जोड़ने पड़े, कइयों को नदी की ऐतिहासिक पवित्रता और उसके लाभों से परिचित कराना पड़ा। राजनेताओं की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें लोगों ने स्वयं ही दूर कर लीं। हम मजबूत और दृढ़ इरादे से कार–सेवा के कामों में जुटे हुए हैं और ऐसा करते हुए हमें चार वर्ष हो गए हैं।

अब तक कार–सेवा का काम कितना हो चुका है? इस प्रश्न के उत्तर में संत सीचेवाल ने बताया कि नदी में से बूटी, घास, गारा निकालने, तटबंधों को पक्का करने का काम चल रहा है। (उन्होंने कंप्यूटर पर चल रही ऑडियो–वीडियो सी.डी. की ओर इशारा करते हुए कहा– इधर देखो, कल (19 अगस्त, 2004) ही इस तरफ कार–सेवा शुरू की गई है)। संत जी स्वयं नदी में घुसकर जोर लगाकर बूटी को धकेलते हुए बाहर निकाल रहे थे।

उनकी ओर मैंने आश्चर्य से देखा और पूछा– आप? उन्होंने मुस्करा कर कहा कि अगर हम कार–सेवा के लिए नदी में न घुसें तो इस जोख़िम भरे काम में संगतें कैसे शामिल हो सकती हैं! हालांकि कार–सेवकों को सांप डसते हैं, जोंकें चिपटकर सेवकों का लहू चूसती हैं, अन्य जहरीले कीड़े–मकोड़े काटते हैं, पर संगतों के हौसले बुलंद रहते हैं और जान की बाजी लगाकर गुरु नानक जी की पवित्र नदी को शुद्ध करने के लिए सेवा करते हैं। हम बातें करने में नहीं, हाथ से सेवा करने के काम को तरजीह देते हैं। कार–सेवा में बच्चों से लेकर बूढ़े, मांएं, भाई दिल से लगे हुए हैं। कुछ राजनैतिक नेता भी इस नेक कार्य में शामिल हुए। पवित्र नदी की कार–सेवा संबंधी


IAS नामांकन प्रारंभ IAS

प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा-2005

सफलता हमारी परंपरा है

सिविल सेवा परीक्षा में हमारे अंतिम रूप से चयनित छात्र

DEEPAK KR.
क्रमांक: 013539
प्रथम प्रयास में चयनित

RICHA
क्रमांक: 133940
प्राप्तांक: 325 (समाजशास्त्र)

PANKAJ S. SISODIYA
क्रमांक: 202681

KUMAR RAVI
क्रमांक: 063262

?

आप भी हो सकते हैं

प्रारंभिक परीक्षा 2005 हेतु 5 महीने का विशेष कक्षा-कार्यक्रम

समाजशास्त्र

BY

DR. S.S. PANDEY

(At CIVILS INDIA only)

"हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक लोकप्रिय"

"Class करें, अंतर देखें" "बाद में पछताने से बचें"

निःशुल्क कार्यशाला: 23 नवंबर '04 (4 बजे सायं)
कक्षा प्रारंभ: 25 नवंबर '04 (4 बजे सायं)

CIVILS INDIA®
The Quality Institute for IAS

A/12-13,202-203, ANSAL BUILDING BEHIND BATRA CINEMA,
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09
Ph.: 27652921, 9810553368 (Dr.) 9818244224 (Couns.),

आर्थिक सहायता प्राप्ति से जुड़े प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि संगतें दिल खोलकर इस पवित्र कार्य में शामिल हैं। विदेश में बस रही संगतों का भी भरपूर सहयोग मिलता रहता है और वे पंजाब को साफ–सुथरा, सुंदर और आधुनिक रूप में देखना चाहती हैं। नदी–सुधार मिशन के अपने प्रचार के लिए हम तीन बार फिलीपीन्स और दो बार इंग्लैंड गए।

अब तक हुए खर्च के अनुमान के बारे में उन्होंने बताया कि 16 जून, 2003 से पहले करवाए गए पंजाब सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार पवित्र नदी पर करवाया जा चुका कार्य लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक के बराबर था। जहां तक सरकारी योगदान की बात है, वह हमारे नदी कार–सेवा के यत्नों की प्रशंसा करती रहती है।

कार–सेवा में सैकड़ों लोगों के शामिल होने की जानकारी दी गई कि नदी के किनारे बसे गांवों सहित दूर–दराज के गांवों की संगत का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। रोजाना 50 गांवों की संगत अपनी ट्रालियों में बैठकर दूध और लंगर का प्रबंध करके शामिल हुईं। हम पारंपरिक पवित्र कार–सेवा के साथ–साथ आधुनिक मशीनरी को भी उपयोग में लाए।

नदी कार–सेवा की चेतना और इसके नतीजों के बारे में संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने जानकारी दी कि मुकेरियां हाइडल नहर से पाइपों के रास्ते छोड़ा गया पानी नदी में बहना शुरु होने से इसकी सफाई में आसानी हुई और सेम (जमीन के नीचे पानी के जलस्तर के गिरने की प्रक्रिया) खत्म हो गई। नदी के आसपास की जमीन फिर से खेती लायक बन गई। अब पानी का स्तर ऊंचा हो गया है और हैंडपंप चलने शुरू हो गए हैं। बस, थोड़े अरसे के बाद ही खुशहाली और अधिक बढ़ जाएगी।

संत सीचेवाल ने खुलकर बातें करते हुए कहा कि 'पवणु गुरु, पानी पिता, माता धरति महतु' के सूत्र वाक्य को अपनाना ही भगवान की सच्ची पूजा है। स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा–पानी और खूबसूरत धरती कायम रखना हमारी भलाई के कार्यों का मुख्य मनोरथ है। लोगों की शारीरिक और मानसिक तंदरुस्ती के लिए यत्न करना हमारा कर्त्तव्य है और समय की मांग भी।

वैज्ञानिक विचार रखने वाले संत सीचेवाल ने कहा कि धान की निरंतर रोपाई और कुछ अधिक पानी चूसने वाले पेड़ों के कारण जमीन के पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। अगर धान के स्थान पर नींबू, किन्नू, नाखे, संतरे, आम, जामुन, अमरूद, अंगूर और अन्य फलों के बाग लगाए जाएं तो पानी को बड़ी हद तक बचाया जा सकता है। कारखानों के पानी को स्वच्छ करके फिर से इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। मोटर–गाड़ियों का इस्तेमाल घटाएं और पौधों की गिनती बढ़ाएं,

*(शेषांश पृष्ठ 50 पर)*


**IAS/PCS - 2005-06**
Prelims/Mains हिन्दी माध्यम
**3 ट्रायल कक्षाएं नामांकन के पूर्व**

**समाज शास्त्र**
द्वारा **धर्मेन्द्र**
'SYNONYM OF SOCIOLOGY'

**रूपरेखा :**
* अध्यापन की शुरुआत सतही रूप से।
* सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान।
* सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक संरचना।
* ईक्नॉमिकल एवं पालिटिक्स वीक्ली, योजना एवं विदेशी पत्रिकाओं के सूचनाओं से समृद्ध क्लॉस नोट्स।
* पर्याप्त लेखन अभ्यास।
* नवीनतम समाज शास्त्रीय अध्ययन विवेचना के साथ।

**पत्राचार :**
1. ईक्नॉमिकल एवं पालिटिक्स वीक्ली, योजना एवं विदेशी पत्रिकाओं के सूचनाओं से समृद्ध क्लॉस नोट्स।
2. 10 वर्षों के प्रश्नपत्र का विश्लेषण।
3. मॉडल उत्तर।
4. स्टडीज का विवरण।
5. लेखन कला पर विशेष सूचना / बुकलेट।

**मनोविज्ञान**
द्वारा **ओ.पी. चौधरी**

हिन्दी माध्यम में भी सफलता की ओर अग्रसर 'अग्रणी पहलकर्त्ता'
VIPUL GOYAL = 341 (2002, UPSC),
AMIT MISRA = SDM (UPPCS 2000), SDM (MPPCS 1999)

**विषय के बारे में :**
* पृष्टभूमि की आवश्यकता नहीं।
* प्रथम पत्र के साथ-साथ द्वितीय पक्ष में भी 180+/300 स्तर का अंक प्राप्त करना संभव क्योंकि द्वितीय पक्ष में आधे यूनिट तकनीकी/अवधारणात्मक।
* सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 800 पृष्ट में समाहित।
* गैप की सुविधा।
* अत्यंत रूचिपूर्ण एवं बोधगम्य विषय।

**सा0 अध्ययन** धर्मेंद्र, ओ.पी. चौधरी एवं टीम

**नामांकन प्रारंभ**
**Compulsory/Spoken English**
*by* **PANKAJ K. SINGH**
*For all competitive exams including IAS/PCS/Judicial Exam*

**AAS**
**AN IAS ACADEMY**
302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009.
Ph.: 55152590 Cell.: 9891567782, 31080722

नोट : * अंग्रेजी के समतुल्य पूर्णतः परिभार्जित सामग्री हिन्दी में उपलब्ध * पत्राचार उपलब्ध।

# सुख और दुख

○ आभा श्रीवास्तव

सुख की खोज जीव मात्र की शाश्वत अभिलाषा है। समस्त भौतिक अथवा आध्यात्मिक प्रपंचों के मूल में मनुष्य की यही खोज अभिव्यक्त होती है। वह जान–बूझ कर हो रही हो या अनजाने में, प्रत्यक्ष रूप में हो रही हो या परोक्ष रूप में यह एक अलग बात है। मूल सत्य केवल इतना ही है कि सृष्टि का हर सचेतन प्राणी, जिसमें सुख या दुख अनुभव करने की योग्यता है, सुख की खोज में लगा हुआ है। अतः स्वभावतः ही जिज्ञासा होती है कि यह चिर अभिलषित सुख वस्तुतः है क्या? वैशेषिक दर्शन सुख को परिभाषित करते हुए कहता है कि "अनुकूलत्वम् सुखम्"। सामान्यतः जब तक अपने चतुर्दिक का परिवेश अपने अनुकूल प्रतीत होता है, हम सुख का अनुभव करते हैं तथा प्रतिकूलता ही हमारे दुख का कारण होती है। हमारी वृत्तियां सदैव बहिर्मुखी होती हैं। जहां–जहां हमें इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थ दिख पड़ते हैं उन्हीं में हम सुख खोजते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि जितना ही हम उसे बाहर खोजते हैं, उतने ही दुखी और परेशान हो जाते हैं। परम करुणामय बुद्ध ने वर्षों की तपस्या के बाद जो प्रथम आर्य सत्य उद्घाटित किया है वह भी यही कहता है कि यह संसार दुखमय है। जो कभी–कभी हमें सुख की अनुभूति होती है वह बस वैसी ही है जैसे सिर पर रखा हुआ बोझ कमर पर रख लेने पर सिर को सुख की अनुभूति होती है। प्रश्न यह उठता है कि इस दुखमय संसार में क्या हम वास्तव में सुख प्राप्त कर सकते हैं? यदि हां, तो किन उपायों के द्वारा?

वास्तव में जीवन में न सुख है न दुख। यह केवल मनुष्य का अपना अज्ञान है जो इनका अनुभव कराता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार तो 'ख' का अर्थ है

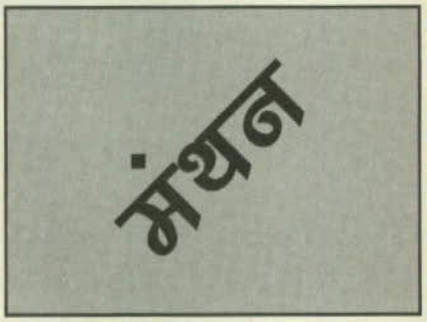


आकाश, जिसे दूसरे शब्दों में परिवेश भी कहा जा सकता है। वस्तुतः हमारा चतुर्दिक परिवेश जब हमें अनुकूलता का अनुभव कराता है, हम समझते हैं कि हम सुखी हैं, उसी प्रकार प्रतिकूल परिवेश हमें दुख की अनुभूति कराता है। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे भलीभांति समझा जा सकता है। मान लीजिए, हम सड़क पर जा रहे हैं, रास्ता पानी–कीचड़ से भरा है और हमारे पांव में नए जूते हैं। हम जूते उतार कर उसे हाथ में लेकर उस कीचड़ भरे रास्ते को पार कर जाते हैं और जूतों के बच जाने के सुख का अनुभव करते हैं। दूसरी स्थिति में हमें यदि यह आदेश दिया जाए कि आप जूते उतार कर उस कीचड़ भरे रास्ते पर चलिए तो वह आदेश हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। जबकि प्रक्रिया की दृष्टि से दोनों ही स्थितियां समान हैं, किंतु परिणाम की दृष्टि से वे दो प्रकार के अनुभवों को देने वाली हैं। इसी प्रकार संसार में सभी परिस्थितियों के साथ यह नियम लागू होता है कि मनोनुकूलता सुख पहुंचाती है तो प्रतिकूलता दुख। अतः यदि कर्मों में से मन को हटा दिया जाए, कर्म केवल कर्म के लिए हो, अनुकूलता या प्रतिकूलता से संबद्ध न हो तो हमारी चेतना समत्व को प्राप्त कर सकती है। थियासोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका सुश्री हेलीना पैट्रोवा ब्लैवस्की ने अपनी पुस्तक "वाइस आफ द साइलैंस" में बड़े ही सहज शब्दों में इसे अभिव्यक्त किया है। वह कहती हैं: "Mind is the slayer of all things... Slay the Slayer". सुनने में ये पंक्तियां जितनी सहज हैं, अनुभव में उतनी ही दुरूह हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य का लक्षण है स्वार्थपरता, स्वकेंद्रितता, स्वतल्लीनता। अतः जब तक इस मानसिकता से निकलकर सहानुभूति, सामंजस्य, एकत्व की मानसिकता से विकास नहीं होता तब तक समत्व के भाव को प्राप्त कर पाना असंभव है।

यह मनुष्य का परम सौभाग्य है कि वह परम स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, एक अवसर की भांति जिसका वह जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकता है, परंतु उसका दुर्भाग्य भी है कि वह सामान्यतः अपनी असीम और अद्भुत संभावनाओं को जल्दी समझ नहीं पाता। वह जिसे हितकर समझता है उसके लिए सतत् प्रयत्न करता है किंतु गंतव्य ही यदि गलत हो तो ईमानदार प्रयत्न भी उसे दुख ही देते हैं, सुख नहीं। मनुष्य की अज्ञानता की जड़ता ही उसका सबसे बड़ा बंधन है। इस बंधन से मुक्ति का उपाय है व्यक्तिगत प्रयास। जब तक हमारा जीवन बाह्य भौतिक वस्तु पर आधारित होता है तब तक 'सुख' हमारा भ्रम है। मनुष्य के भीतर स्थित आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति ही सुख को स्थायी बना सकती है। जब तक हम उस अनंत प्रकाश की ओर उन्मुख नहीं हो जाते तब तक इन सांसारिक कष्टों के बीच हमारा सुख सुरक्षित नहीं हो सकता। अतः निर्माण कीजिए उस पर जो स्थायी, अनंत और वास्तविक है, केवल तब ही हमारे अंदर स्थित सुख को कोई हाथ नहीं लगा सकता और न उसे दुख में बदल सकता है। ❑

**(लेखिका बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल के हिंदी विभाग में प्रवक्ता हैं।)**

*(पृष्ठ 48 का शेषांश)*

पोलीथीन के लिफाफों का इस्तेमाल बंद करें तो वातावरण और पानी से संबंधित हमारी काफी समस्याएं हल हो सकती हैं।

दुनिया की अपने किस्म की सामाजिक और आर्थिक परियोजना जिससे लोगों की सामूहिक हिस्सेदारी, पर्यावरण के प्रति मित्रभाव के साथ–साथ काली नदी की पवित्रता की पुनः बहाली से संबंधित उनकी तसल्ली आदि की जब चर्चा चली तो उन्होंने बताया कि अभी कार–सेवा का काम जारी है। सुल्तानपुर लोधी के सीवर और 29 गांवों का पानी इसमें पड़ना बंद कर दिया गया है। संगतें नदी की कार–सेवा में तन–मन से लगी हुई हैं। सुल्तानपुर के बाद गालोवाल, सुभानपुर, भुलथ्थ, कागजी आदि जगहों पर पक्के और खूबसूरत घाटों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है और अब बैसाखी के अवसर पर संगतें बड़ी संख्या में स्नान करती हैं। इसकी पवित्रता की देखरेख संगतें स्वयं ही करती हैं।

**सड़कों वाला बाबा या वेलफेयर बाबा**

पवित्र काली नदी की कार–सेवा से पहले संत बलबीर सिंह सीचेवाल को 'सड़कों वाला बाबा' या 'वेलफेयर बाबा' के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्होंने लोगों को रास्तों और सड़कों की सहूलियत मुहैया करवाने की कार–सेवा का बीड़ा 16 साल पहले उठाया था। परिणामस्वरूप, जालंधर–लोहियां और सुल्तानपुर लोधी के बीच का फासला बीस मील कम हो गया। काली नदी के साथ–साथ 100 किलोमीटर का कच्चा साफ–सुथरा रास्ता बनाया गया। गांवों की दशा बदलने के लिए आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सीवर डलवाए गए और नलों के रास्ते पीने योग्य पानी की सप्लाई प्रदान की गई। गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाहों के समय आर्थिक सहायता पिछले कई सालों से जारी है। चैरिटेबल ट्रस्ट सीचेवाल की ओर से लोकहित और विकास कार्यों का सिलसिला अलग–अलग रूपों में जैसे कि एडवांस कंप्यूटर लैब, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर पार्कों का निर्माण, लाइटें लगवाना, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, शिक्षा आदि के कार्य निर्विघ्न चलते रहते हैं। अन्य कामों के अलावा आम लोगों के उपयोग के लिए शौचालय बनवाए गए हैं, गंदगी के ढेरों को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। गलियों के गंदे पानी की नालियां अब नहीं रही हैं, गंदे पानी के पोखर अब पार्कों में बदल दिए गए हैं, सड़कों और नदियों के किनारे सुंदर पेड़–पौधे लगा दिए गए हैं। श्मशान भूमि जैसी वीरान जगहों को सुंदर और शांत जगहों में बदल दिया गया है। संत जी इस सब कुछ के साथ–साथ गांवों के लोगों के अंदर सफाई, वातावरण की शुद्धता आदि के बारे में चेतना का प्रचार और प्रसार निरंतर जारी रखते हैं। ❑


# भारतीय राजव्यवस्था एवं भारत का संविधान

**कम मूल्य में इतनी अधिक अद्यतन जानकारी अन्यत्र दुर्लभ है**

Book Code : 849
Pages : 192
Price : Rs. 80/-

**प्रमुख आकर्षण**

• भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की विस्तृत विवेचना • भारत के संविधान में अब तक हुए 92 संविधान संशोधन अधिनियमों का समावेश • 800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न • भारतीय राजनीति की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं सितम्बर 2004 तक का यथास्थान और आवश्यक विस्तार के साथ समावेश इस प्रकार यह पुस्तक पूर्णतया अद्यतन (Most up-to-date) है।

**प्रतियोगिता साहित्य**

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

# झारखंड का आदिवासी जीवन

पुस्तकः झारखंड के आदिवासी; लेखकः चंद्रकांत वर्मा, मानव विज्ञान विभाग, कालूराम मोदी मेमोरियल वनांचल कालेज, गिरिडीह, झारखंड; प्रकाशकः के.वी. पब्लिकेशन्स; पृष्ठ संख्याः 106; मूल्यः 50 रुपये;

जनजातियों में विलुप्त हो रही उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं की झलक दिखाई पड़ती है। 'जनजाति' शब्द के उच्चारण के साथ ही हमारे मानस–पटल पर एक खाका तैयार होता है जिसमें व्यक्ति आदिम अवस्था में जिंदगी की तमाम भौतिक सुख–सुविधाओं से कोसों दूर सीधी–सपाट जीवन शैली को अंगीकार करके प्रकृति के साथ सतत सामंजस्य साध चुका हो। चंद्रकांत वर्मा की पुस्तक 'झारखंड के आदिवासी' में जनजातियों के जीवन के विभिन्न आयामों के संपूर्ण कैनवास का निर्माण होता दिखता है। मूलतः लेखक मानवविज्ञान से सरोकार रखने वाले विषयों पर अपनी कलम को गति प्रदान करते हैं जो उनकी रचनाओं में विषय के सौंदर्य को प्रकट करता है।

भारतीय समाज में जनजातीय समूह शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से अति पीड़ित हैं। पुस्तक के अनुसार इनकी सर्वप्रमुख विशेषता परिवार और परिवारों को समूहों का संकलन है। इनमें 'हम' अर्थात् समुदाय बोध का ज्ञान कूट–कूटकर रचा–बसा है। इनकी अर्थव्यवस्था सरल होती है जो पूर्णतः खाद्य संग्रह पर आधारित होती है। भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण भाषा, बोली, संस्कृति भौगोलिक व आर्थिक आधार पर किया गया है। व्यापकता में यूं कह सकते हैं 'झारखंड के आदिवासी' में झारखंड की पहचान इन्हीं आदिवासी समुदायों की शाश्वत संस्कृति के कारण है। राज्य के सभी जिलों में उनके रहन–सहन के तौर–तरीकों का बहुत ही सूक्ष्मता से लेखक ने अध्ययन किया है।

आदिवासी समुदाय आत्मनिर्भर और स्वावलंबी जीवनचर्या को छोड़कर भौतिकता से आकर्षित होकर नौकरी की तलाश में औद्योगिक शहरों में श्रम बेचने पहुंच जाते हैं। पैसों के लालच में वेश्यावृत्ति की दलदल में औरतें फंसती चली जाती हैं। परिणामस्वरूप एड्स जैसे लाइलाज रोगों का शिकार हो जाती हैं। पहाड़ी और वन्य क्षेत्रों की दुर्गमता में इनका निवास होने के कारण पर्यावरण की समस्या से रोज रू–ब–रू होना पड़ता है। राज्य में कहीं–कहीं साक्षरता का प्रतिशत शून्य भी है। जनजातियों की अपनी प्राचीन कला–ललित कला, रस्सी बनाने की कला तथा अन्य कलाओं के लगातार हो रहे क्षरण के कारणों को लेखक ने बड़ी शिदत के साथ महसूस किया है। उन्होंने इसका मुख्य कारण जनजातियों का ईसाई धर्म और जीवन शैली के आकर्षण में पड़ना बताया है। पुस्तक की खासियत यह है कि जनजातियों की समस्या ही नहीं बल्कि उसके समाधान की चर्चा है। यह पुस्तक की पूर्णता का पाठकों को पल–पल अहसास कराएगी। बेहया राजनीति की सर्वाधिक मार इन्हें ही चुकानी पड़ती है। इनके उत्थान हेतु दिए गए सुझावों में इन्हें शिक्षित करना, बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा–सेवा का बहाल करना तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कारीगारों के लिए उचित वेतन संबंधी कानून बनाना आदि हैं।

पुस्तक में कुछ जनजातियों की विस्तार से चर्चा की गई है जिनमें संथाल, उरांव, मुंडा, हो, बिरहोर और असुर प्रमुख हैं। इन सभी जनजातियों के उत्पत्ति स्थान और वर्तमान में इनके प्रमुख निवास स्थान, रहन–सहन, खान–पान, पहनावा–ओढ़ावा, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति, इनकी वास्तुकला, संस्कृति तथा इनकी मान्यताएं, जादू–टोना, अंधविश्वास, पंचायत व्यवस्था, विशेष परंपराएं, रीति–रिवाज, त्योहार एवं मनोरंजन के साधन की सामान्य चर्चा की गई है।

इंटरमीडिएट कला तथा प्रादेशिक सिविल सेवा परीक्षाओं के छात्रों के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। जनजातियों पर अच्छी पुस्तक का अकाल, इसकी महत्ता को और भी बढ़ा देता है। पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है – विषयों की क्रमवार प्रस्तुति। भाषा की सरलता ने विषय की जटिलता को अत्यंत सुगम बना दिया है। यह पुस्तक दलित, आदिवासी और जंगल बचाने के लिए प्रतिबद्ध गैर–सरकारी संगठन के लिए भी उपयोगी हो सकती है। पुस्तक की कम कीमत कम होने से यह पाठकों की पहुंच से बाहर नहीं है। इसके लिए लेखक धन्यवाद के पात्र हैं। ❑

**समीक्षकः स्वतंत्र मिश्र**

# भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर
इतनी अद्यतन जानकारी
इतने कम मूल्य पर
अन्यत्र दुर्लभ है

Book Code : 851
Pages : 254
Price : Rs. 100/-

## प्रमुख आकर्षण

• सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश • आर्थिक सर्वेक्षण 2003-2004 • भारत 2004 • केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2004 • अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 • मानव विकास रिपोर्ट 2004 • World Economic Outlook, Sept. 2004 • Global Development Finance 2004 • Statesman's Year Book 2004 • दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 • 545 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

**प्रतियोगिता साहित्य**

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

# सामान्य अध्ययन : एक प्रामाणिक पुस्तक

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्यतन पाठ्य सामग्री का अनमोल संग्रह

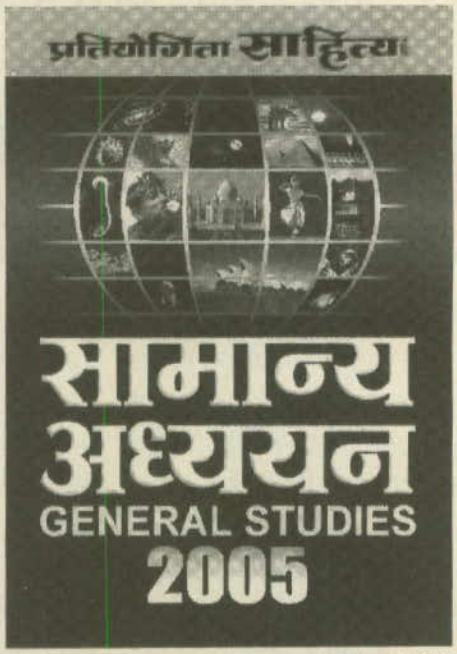


Rs. 690/-

**Free Booklet**

• विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी
• गत परीक्षा के सॉल्वड पेपर्स • 5 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हल सहित

• प्राक्कथन लेखकः श्री एस.पी. आर्य (I.A.S.) पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार • प्रधान सम्पादक : डॉ. बी.एल. फड़िया
• 7th संशोधित संस्करण • 2428 पृष्ठ • 10363 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

**प्रमुख आर्कषण** • सामान्य विज्ञान • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • पर्यावरण व प्रदूषण • कृषि एवं पशुपालन • इतिहास : विश्व एवं भारत • राष्ट्रीय आन्दोलन • भारतीय राजव्यवस्था • विश्व एवं भारत का भूगोल • भारतीय अर्थव्यवस्था • सामान्य मानसिक योग्यता • खेलकूद • प्रमुख सम्मान तथा पुरस्कार • सामान्य ज्ञान • भारत की सामयिक व्यवस्था • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम् घटनाएं • कौन, क्या, कहां? से सम्बन्धित प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित • विगत वर्षों के परीक्षा प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक हल सहित • नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुरूप मानचित्र आधारित प्रश्न, कथन एवं कारण सम्बन्धी प्रश्नों का समावेश • नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित आदर्श प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक हल सहित

**प्रतियोगिता साहित्य**

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

# ज्ञान–सागर

- नोबेल फाउंडेशन एक निजी संस्था है। इसे बारूद के आविष्कारक अल्फ्रेड की वसीयत के आधार पर 1900 में स्थापित किया गया।
- 1901 में पहली बार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए थे।
- अर्थशास्त्र से संबंधित पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था जिसे स्वीडन की सरकार ने स्थापित किया है।
- नोबेल फाउंडेशन ने 29 जून, 2000 को 100 वर्ष पूरे कर लिये हैं।
- नोबेल फाउंडेशन का एक बोर्ड है जो स्टॉकहोम में स्थित है। इसमें सात सदस्य और दो उप सदस्य होते हैं जो स्वीडन या नार्वे के नागरिक होते हैं। इसका चुनाव पुरस्कार देने वाली संस्थाओं के ट्रस्टी अर्थात् न्यासी करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव सरकार करती है।
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें अपनी कविताओं की पुस्तक *गीताजंली* के लिए 1913 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया।
- भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डा. चंद्रशेखर वेंकट रमण थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें प्रकाश की क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज को रमण प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
- हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डा. खुराना का जन्म पंजाब के रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया।
- 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था जो अब युगोस्लाविया में है। 1929 में मदर टेरेसा कोलकता आ गईं। मदर टेरेसा की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल कर सका।
- सन् 1983 में भौतिकी शास्त्र के लिए डा. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (जो खगोल भौतिक शास्त्री थे) को नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अनेक रहस्यों का पता चला।
- अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है।
- वर्ष 2004 के लिए औषधि के क्षेत्र में रिचर्ड एक्सेल और अन्वेषक लिंडावक को घ्राणेन्द्रिय की कार्य प्रणाली के क्षेत्र में कई अग्रगामी अध्ययनों के लिए नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया गया।
- 2004 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार फ्रैंक विलजैक, एच डेविड पोलित्जर और डेविड जे ग्रॉस को उनके उस माडल के लिए दिया गया है जो प्रकृति में लघुतम पदार्थों का विवरण तो देता ही है, साथ ही उनके पारस्परिक प्रभावों की प्रणाली को भी दर्शाता है।
- रसायन में क्षेत्र में इस वर्ष (2004) का नोबेल पुरस्कार आरों सीशानोवर अवरम हर्ष को और इरविन रोज को दिया गया। इनकी खोज से पता चला कि कोषाणु कैसे कोशिकीय कोषाणु के आवर्तन, डी एन ए की मरम्मत, जीन–प्रतिलेखन करते थे और नवोत्पादित प्रोटीन की गुणवत्ता कैसे बनाई रखी जा सकती है।
- 2004 में आस्ट्रिया के उपन्यासकार एवं नाटककार एलफ्रिड जेलिनेक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला।
- फिन केलैन्ड और एडवर्ड प्रेसकोट को इस वर्ष (2004) का अर्थशास्त्र नोबेल स्मारक पुरस्कार मिला।
- वर्ष 2004 का शांति नोबेल पुरस्कार कीनिया के पारिस्थितिकी विशेषज्ञ–वांगरी मथाई को दिया गया। वांगरी मथाई के नेतृत्व में अफ्रीका में पर्यावरण आंदोलन चल रहा है जिसके अंतर्गत वहां 3 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। ❑

**संकलन : रीना**
**(प्रोडक्शन एक्ज़ीक्यूटिव, सहारा टी.वी.)**

**प्रो० उमाकांत मिश्रा, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–32**
**संपादक : राजेन्द्र राय**

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi. R.N. 951/57


# IAS/PCS PT-CUM-MAINS-2005

सामान्य अध्ययन पर कम ध्यान दिये जाने से सफलता संदिग्ध हो सकती है, जिसकी प्रामाणिकता वर्ष 2003 की मुख्य परीक्षा के परिणाम हैं। इस परिणाम ने सामान्य अध्ययन की नये दृष्टिकोण के साथ तैयारी की रणनीति को अनिवार्य बना दिया है। निश्चित रूप से एक वैकल्पिक विषय की अपेक्षा सामान्य अध्ययन की महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस आलोक में ***DISCOVERY*** के **"सुधार आधारित विकास कार्यक्रम"** की लक्षित एवं तार्किक रणनीति सफलता की पथ प्रदर्शक बन सकती है–

# सामान्य अध्ययन

## –सी.बी.पी. श्रीवास्तव, अख्तर मलिक, अनिल केशरी एवं अन्य

**सी.बी.पी. श्रीवास्तव** के निर्देशन में डिस्कवरी द्वारा संचालित सामान्य अध्ययन की कक्षा की सफलता का प्रमाण 2003 का प्रश्न था। इसी कड़ी में **मुख्य परीक्षा 2004** के प्रश्न कक्षा की अप्रत्याशित सफलता के परिचायक हैं। निम्नांकित प्रश्न कक्षा में विस्तृत चर्चा, शब्द सीमा में उत्तर प्रारूप तथा प्रश्नों की सम्भावित सूची में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। कक्षा की विशिष्ट बात यह रही कि दीर्घ, लघु तथा 20 शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर **"क्लास नोट्स"** से सीधे प्राप्त हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सिविल सेवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की मांग तथा प्रवृति के अनुरूप डिस्कवरी में कक्षा संचालित होती है जो आपकी सफलता भी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

**प्रथम पत्र** प्र.सं. 1. ख, 2. क, ख, 4. ग, 5. क, ग, घ, 6. क, ख, 7. क, 8. क, ख, 9. क, ग, घ, ङ, 10. क, ख, 11. क, ख, ग, 12. ख, 13. क, ख, ग।

**द्वितीय पत्र** प्र.सं. 1. क, ख, ग, 2. क, ख, ग, ङ, 3. क, ङ, 4. क, ख, 5. क, ख, ग, 6, क, ख, ग, घ, च, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, 7. ख, ग, 8. घ, 9. क, घ, ङ, 10. क, ख, 11. ख, ग, 12. क, ख, ग (i, iv) घ, ङ।

## R.B.D.P. द्वारा संचालित कक्षा की रूपरेखा–

### प्रारम्भिक परीक्षा

- पाठ्यक्रम के विभिन्न खण्डों की आधारिक जानकारी तथा तथ्यों के साथ अवधारणाओं के विकास के लिए कक्षा का संचालन।
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा एवं उनका संकलन।
- प्रति सप्ताहांत खंड विशिष्ट जांच परीक्षा जो विषय के व्यावहारिक, अवधारणात्मक तथा सूक्ष्म तथ्यों वाले प्रश्न पर आधारित।
- समसामयिक प्रश्नों के हल के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र में प्रकाशित घटनाक्रमों पर चर्चा।
- अवधारणाओं के साथ तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री। साथ ही भारत संदर्भ ग्रंथ, आर्थिक सर्वेक्षण तथा विभिन्न सरकारी रिपोर्टों का संक्षिप्त रूप।

### मुख्य परीक्षा

- कक्षा क्रमशः तथ्यात्मक-विश्लेषण एवं पूर्णतः विश्लेषणात्मक ताकि प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप उत्तर लेखन सम्भव हो सके।
- "फाइल मेन्टिनेन्स सिस्टम" द्वारा लेखन शैली का चरणबद्ध विकास–
  - प्रत्येक अध्याय की संकल्पना का विकास।
  - पूछे गए तथा संभावित प्रश्नों का उत्तर प्रारूप।
  - प्रतिदिन प्रश्नोत्तर लेखन (२० शब्द, १५० शब्द और २५० शब्द)।
  - मूल्यांकन एवं सुधारात्मक सुझाव।
  - गत वर्षों में पूछे गए तथा संभावित प्रश्नों की आवश्यकता के आधार पर पूर्णतः संशोधित अध्ययन सामग्री।

## लोक प्रशासन –दिवाकर गुप्ता

- विषय के दोनों पत्रों की विशिष्टताओं के संदर्भ में विभिन्न खण्डों में निहित तथ्यों एवं संकल्पनाओं का विश्लेषण।
- प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम के विभिन्न खण्डों की आधारिक जानकारी तथा तथ्यों के साथ अवधारणाओं के विकास पर समान बल ताकि व्यावहारिक पक्षों तथा कथन कारण वाले प्रश्नों का हल सम्भव हो सके।
- अवधारणाओं की व्याख्या के साथ तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री।

## समाजशास्त्र –सी.बी.पी. श्रीवास्तव

- प्रथम पत्र में सामान्य समाजशात्र के तहत विश्लेषण की विधा के विकास के लिए कक्षा में विभिन्न खण्डों पर विस्तृत चर्चा।
- द्वितीय पत्र में भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन के क्रम में अद्यतन आंकड़ों के साथ तुलनात्मक अध्ययन।

## इतिहास –डॉ० हरिश्चन्द्र वर्मा, डॉ० लाल बहादुर वर्मा एवं अख्तर मलिक

- प्रथम पत्र में प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत के तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक आयामों का खण्ड विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन। द्वितीय पत्र में विश्व इतिहास के सूक्ष्म पहलुओं के अध्ययन के साथ- साथ आधुनिक भारत के इतिहास के विभिन्न खण्डों का गहन विश्लेषण।

## भूगोल –अनिल केशरी

- विषय के सूक्ष्मतम बिन्दुओं तथा उनकी अवधारणा के विकास के लिए आधारिक कक्षा का संचालन।
- प्रथम एवं द्वितीय पत्र की मिश्रित अवधारणाओं वाले प्रश्नों पर विशेष बल।
- विगत १० वर्षों में पूछे गए प्रश्न एवं प्रत्येक टॉपिकों पर संभावित प्रश्नों की संरचना कक्षा में कराने का प्रावधान।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु लगभग ४० से ४५ प्रश्नों की तैयारी एटलस के माध्यम से।

## हिन्दी साहित्य –अजय अनुराग

- प्रथम पत्र में छात्रों की भाषा विज्ञान से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए विशिष्ट अध्यापन पद्धति द्वारा मार्गदर्शन।
- द्वितीय पत्र में नये पाठ्यक्रम में समावेशित पहलुओं, जिन पर अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री, दोनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, पर कक्षा में गहन चर्चा के साथ लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान।

**DISCOVERY**
*...Discover your mettle*

B-14 (Basement), Commercial Complex,
Beside HDFC Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-9
30906050, 9313058532, 27655891